

मोदी सरकार के 18 महीने



देश की जनता निराश है

गरीबों का पेट भाषणों से नहीं भरा जा सकता. आम जनता की अपेक्षाएं आंकड़ों की बाजीगरी से पूरी नहीं हो सकतीं. हवा-हवाई बातों से युवाओं को रोजगार नहीं मिलता. सिर्फ लोकप्रिय नारे उछालने से सामाजिक बदलाव नहीं आता. जब कल-कारखानों की हालत खराब होने लगे, किसान आत्महत्या करने लगे, मजदूर हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएं, रोजगार मिलना बंद हो जाए और महंगाई की मार लोगों की कमर तोड़ने लगे, तो समझना चाहिए कि देश में बुरे दिन आने वाले हैं. नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 18 महीने यानी डेढ़ साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है. ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नज़र नहीं आता. हर सरकार पांच साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन पहले ही साल में सरकार के लक्ष्यों और दिशा का पता चल जाता है. क्या मोदी सरकार मूलभूत परिवर्तन लाने में सफल होगी? क्या वार्दों के मुताबिक विकास संभव है? इस बात को समझने के लिए 18 महीनों के बाद आज मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और आर्थिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों का आकलन बहुत ज़रूरी है.



मनीष कुमार

दे श की जनता ने बड़ी आशा के साथ नरेंद्र मोदी को चुना था. लोगों को लगा था कि उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से मुक्ति मिलने के बाद राहत मिलेगी.

भ्रष्टाचार कम होगा, महंगाई पर लगाम लगेगी और बेरोजगारी की समस्या का हल निकलेगा. नरेंद्र मोदी भी अपने चुनावी भाषण में यह कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन आए क्या? देश के 80 फीसद लोग गरीब है. ज़िंदगी जीने के लिए रोज उन्हे ज़िंदगी से लड़ना पड़ता है. उनकी तकलीफों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन सरकार से उनकी अपेक्षाएं बहुत कम हैं. इसके ठीक विपरीत देश के 20 फीसद समृद्ध वर्ग की तकलीफें कम हैं, लेकिन उसकी अपेक्षाओं की सूची बहुत लंबी है. हर सरकार को यह तय करना होता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है. दुर्भाग्य से सबसे देश में नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई, सबसे जितनी भी सरकारें आईं, उनकी प्राथमिकता में वे 80 फीसद लोग नहीं रहे, जो गरीब हैं. अच्छे दिनों का सही मतलब तो यही था कि मोदी सरकार की प्राथमिकता बदलेगी, लेकिन नई सरकार ने भी वही काम किया, जो 1991 से होता आ रहा है.

समस्या यह है कि गरीब तो परेशान हैं ही,

उद्योगपतियों को भी अब लगने लगा है कि सरकार की दिशा-दशा ठीक नहीं है. मतलब यह कि मोदी सरकार न तो उद्योग जगत को खुश कर पा रही है और न उन 80 फीसद लोगों को राहत दे पा रही है, जिन्हें मदद की वाकई ज़रूरत है. हकीकत यह है कि पिछले 18 महीनों में हर वर्ग निराश हुआ है. किसान परेशान हैं, मजदूर आंदोलित हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई आसमान छू रही है. ऐसे में आर्थिक क्षेत्र में सरकार के सफल होने के सारे संकेत धुंधले होते दिख रहे हैं. लोकसभा चुनाव के पहले भी चौथी दुनिया लगातार यह कहता रहा कि नरेंद्र मोदी नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों को ही आगे लेकर जाएंगे. लेकिन, जब उन्होंने अच्छे दिनों का सपना दिखाया, तो देश के बेरोजगार युवाओं और गरीबों के बीच एक आशा जगी. देश के 80 फीसद लोगों के लिए अच्छे दिनों का मतलब सिर्फ इतना है कि महंगाई कम हो और हर युवा को नौकरी मिले. बीते 18 महीनों के दौरान इन दोनों बिंदुओं पर मोदी सरकार विफल साबित हुई है. वह बाकी सारी बातें कर रही है, लेकिन देश के आम लोगों की असल ज़रूरत पर उसका कोई ध्यान नहीं है.

सरकार बार-बार यह बात जोर-शोर से कह रही है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है और महंगाई कम हो रही है. कहने का मतलब यह कि देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और लोगों को महंगाई से राहत मिल गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली शायद यह भूल गए कि देश की जनता ने यूपीए सरकार की आंकड़ेबाजी से तंग आकर ही उसे बाहर का

आंकड़े बोलते हैं

- ➔ वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में विकास दर 7.5 फीसद से कम यानी सिर्फ 7.0 फीसद ही रही.
- ➔ अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 5.25 फीसद रही.
- ➔ अक्टूबर 2015 में निर्यात में 17.5 फीसद की गिरावट देखी गई.
- ➔ मार्च 2015 से अब तक निजी क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश में 30 फीसद की कमी आई है.
- ➔ पिछले साल यानी अक्टूबर 2014 में 25.89 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ था.
- ➔ अप्रैल से सितंबर के बीच औद्योगिक उत्पादन महज 3.94 फीसद की बढ़त दर्ज करा सका.
- ➔ 2015 के अक्टूबर महीने में सिर्फ 21.35 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ.
- ➔ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति भी दयनीय है, वह सिर्फ 2.64 फीसद की दर से बढ़ रहा है.
- ➔ पिछले 14 सालों में करीब 61,000 करोड़पति भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में पलायन कर चुके हैं.
- ➔ कर्मांडी इंडेक्स प्राइस जुलाई में 3.69 फीसद और अक्टूबर में 5.0 फीसद ही रहा.

रास्ता दिखाया था. वित्त मंत्रालय हो या अन्य दूसरे मंत्रालय, सबने आंकड़ों की बाजीगरी को ही देश चलाना समझ लिया है. नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने एक नया शिगूफा छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर इस साल आठ फीसद पर पहुंचने वाली है. कुछ महीने पहले देश के विभिन्न अखबारों ने यह खबर दी थी कि भारत की विकास दर चीन से आगे बढ़ जाएगी और वह 7.5 फीसद होने वाली है. अब जबकि नतीजे आने लगे हैं, तो पता चला कि यह महज एक भ्रामक प्रचार था. वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में विकास दर 7.5 फीसद से कम यानी सिर्फ 7.0 फीसद हो पाई. अब पता नहीं कि सरकार आंकड़ों का कौन-सा खेल खेलकर वार्षिक विकास दर 7.5 या 8.0 फीसद पर पहुंचाएगी. जबकि विकास के सारे मानक निराशा की ओर इशारा कर रहे हैं.

जुलाई से सितंबर यानी मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में लगातार तीसरी बार बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट देखने को मिली. बिक्री में गिरावट के चलते व्यापार जगत में हड़कंप मचा हुआ है, जिसका सीधा असर घरेलू निवेश पर पड़ रहा है. ज़्यादा मुनाफे का मतलब ज़्यादा निवेश है. मुनाफे में कमी के चलते घरेलू निवेश कम नहीं लगा रहे हैं. नतीजतन, मार्च 2015 से अब तक निजी क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश में 30 फीसद की कमी आई है. सरकार विदेशी निवेश के बारे में यह तो प्रचारित कर रही है कि उसमें पिछले साल के मुकाबले 37 फीसद

(शेष पृष्ठ 2 पर)

देश की जनता निराशा है

पृष्ठ 1 का शेष

का इजाजा हुआ है, लेकिन निजी क्षेत्र में 30 फीसद की कमी आई है, इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही। रियल स्टेट सेक्टर का हाल खराब है। लोगों के पास पैसा नहीं है। ऋण की व्याज दर में बहुत ही कम कमी आई है, इसलिए पुराने फ्लैट खाली पड़े हैं और नया प्रोजेक्ट लाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके चलते इस सेक्टर में बेरोजगारी भी बढ़ी है। औद्योगिक उत्पादन का हाल भी कमोबेश यही है। अप्रैल से सितंबर के बीच वह महज 3.94 फीसद की बढ़त दर्ज करा सका। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति भी दयनीय है, वह सिर्फ 2.64 फीसद की दर से बढ़ रहा है।

अगर कोर सेक्टर की बात करें, तो उसकी वृद्धि दर में गिरावट आई है। उसमें 2014-15 की पहली छमाही में 5.07 फीसद की वृद्धि हुई थी, जो इस बार घटकर महज 2.33 फीसद रह गई है। लेकिन, इन तमाम आंकड़ों से आम जनता को क्या लेना-देना! भारत जैसे देश में आम जनता के लिए अच्छी आर्थिक नीति का मतलब सिर्फ यही है कि वह नीति, जिससे महंगाई कम हो जाए। इसके अलावा देश की जनता को और कोई अपेक्षा शायद नहीं है। महंगाई के नाम पर जो आंकड़ेबाजी होती है, वह खासी मजेदार है। हर शख्स कहता है कि सब्जियां महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, तेल महंगा हो गया है। लेकिन, सरकार कहती है कि महंगाई नियंत्रण में है। सरकार के मुताबिक, कंप्यूटर प्राइज इनडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में कमी आई है और कमोडिटी इंडेक्स प्राइस जुलाई में 3.69 फीसद और अक्टूबर में 5.0 फीसद ही रहा। अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 5.25 फीसद रही।

यह अजीब इत्तेफाक है कि मोदी सरकार के 18 महीनों के कार्यकाल में पिछले 11 महीनों से निर्यात में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अक्टूबर 2015 में निर्यात में 17.5 फीसद की गिरावट देखी गई। पिछले साल यानी अक्टूबर 2014 में 25.89 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ था, जबकि इस साल इस महीने में सिर्फ 21.35 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ। पिछले कई महीनों में निर्यात का यही हाल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस साल जिस तरह निर्यात बाधित हुआ, वह 2008-09 के दौर से भी खराब है। निर्यात कम होने के अलावा मुसीबत यह है कि देश में व्यापार करने वाली कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। उनकी परेशानी यह है कि लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं। करीब 1,600 कंपनियों, जिन्होंने साल की दूसरी छमाही के नतीजे पेश किए, की बिक्री में 4.8 फीसद की कमी आई है।

सरकार यह बात प्रचारित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती कि विदेशी निवेश के मामले में उसे सफलता मिली है। आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में 36 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में हुआ था और चालू वित्त वर्ष (2015-16) में अब तक 44 बिलियन डॉलर का निवेश हो चुका है। हकीकत यह है कि 2005 में भारत में नौ बिलियन डॉलर और 2007 में 37 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ था। लेकिन, अब तक सबसे ज्यादा विदेशी निवेश 2011-12 में हुआ यानी 46.5 बिलियन डॉलर का। इसलिए सालाना 37 से 47 बिलियन



डॉलर का विदेशी निवेश सामान्य ही माना जाएगा। जब तक 60 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश नहीं होता, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से विदेश निवेश में बढ़ोत्तरी हुई है।

विदेशी निवेश हो या फिर चंद औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने की नीतियां, यह सब सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आम जनता के लिए इनका और आंकड़ेबाजी का कोई मतलब नहीं है। मूलभूत बात यह है कि भारत में 60 से 70 फीसद लोग कृषि पर निर्भर हैं और

यह अजीब इत्तेफाक है कि मोदी सरकार के 18 महीनों के कार्यकाल में पिछले 11 महीनों से निर्यात में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अक्टूबर 2015 में निर्यात में 17.5 फीसद की गिरावट देखी गई। पिछले साल यानी अक्टूबर 2014 में 25.89 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ था, जबकि इस साल इस महीने में सिर्फ 21.35 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ। पिछले कई महीनों में निर्यात का यही हाल रहा है।



वे हमारी अर्थव्यवस्था से अलग-थलग हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। आज भी ज्यादातर किसान भगवान भरोसे यानी मानसून पर आश्रित हैं। बारिश हुई, तो अच्छी फसल होती है और अगर मौसम ने धोखा दे दिया, तो वे बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। न तो कोई बीमा होता है और न कोई वैकल्पिक व्यवस्था। ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन मजदूरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मनरेगा जैसी योजनाएं वहां के लिए कारगर साबित हो सकती थीं, लेकिन मनरेगा भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र बनकर रह गई। जिस देश में 60 फीसद आबादी के पास खर्च करने के लिए पैसे न हों, वहां भला उद्योग कैसे सफल हो सकता है! वित्त मंत्री को यह समझना होगा कि भारत को उन आर्थिक नीतियों की जरूरत है, जो गांव के लोगों को आर्थिक मजबूती दे सकें। मौजूदा हालत यह है कि ज्यादातर किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। इसलिए जब तक गांव के लोगों को अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना चाहती है, तो बढ़ाए, लेकिन कृषि क्षेत्र में जारी डेथ इन इंडिया पर कौन ध्यान देगा? किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह किस प्रकार के अच्छे दिनों की सौगात है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन समेत दुनिया के विभिन्न देशों में जा-जाकर भारतीय मूल के लोगों को भारत आने का निमंत्रण दे रहे हैं। हर जगह वह यही कहते हैं कि अब भारत में माहौल बदल गया है, इसलिए भारत आकर आप अपना भविष्य चमकाएं और देश को आगे बढ़ाएं। टीवी पर प्रसारित होने वाले इन कार्यक्रमों को देख-सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से फूल तो जाता है, लेकिन हकीकत चिंतित करने वाली है। हमने ब्रेन ड्रेन के बारे में तो सुना है, लेकिन आज भी भारत से प्रोफेशनल्स, उद्यमियों एवं व्यापारियों का पलायन जारी है। न्यू वर्ल्ड वेथ नामक संस्था के सर्वे से यह चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है कि पिछले 14 सालों में करीब 61,000 करोड़पति भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में पलायन कर चुके हैं। भारत छोड़ने के उनके

फैसले के पीछे पहली वजह यहां की ऊंची कर प्रणाली है। दूसरी वजह सुरक्षा व्यवस्था है और तीसरी वजह बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा है। ये वे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में विदेश नहीं जा रहे, बल्कि जमे-जमाए उद्यमी हैं, जो भारत से अपनी पूरी कमाई और व्यापार समेट कर दूसरे देशों की ओर रुख कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर भारतीय अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई एवं सिंगापुर जाना पसंद करते हैं। इन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो चुका है। अब यह नहीं पता कि उनके दौरों के बाद कितने भारतीय वापस भारत लौटे या वापस आने की योजना बना रहे हैं।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लोग भारत से इसलिए पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है, शहरों में अव्यवस्था के साथ-साथ प्रदूषण है, खाने-पीने की चीजों में मिलावट है। दरअसल, लोग इन तमाम अव्यवस्थाओं से तंग आ चुके हैं, इसलिए जिनके भी पास पैसा है, वे दूसरे देश में बसने की सोचने लगते हैं। पिछले एक साल के दौरान मुंबई से 619 और दिल्ली से 157 करोड़पति देश छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए। हालात जब ऐसे हैं, तो श्रेष्ठ भारत का सपना कैसे पूरा होगा? समझने वाली बात यह है कि इन तमाम समस्याओं का निदान इनके कारणों में छिपा है। अगर भारत में सरल कर प्रणाली हो, सख्त कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षित माहौल हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, प्रदूषण रोकने के इंतजाम हों और मिलावटखोरों के साथ सख्ती बरती जाए, तो यह पलायन रोक जा सकता है। भारत छोड़कर विदेश जाने वाला चर्च वर्ग सिर्फ अकेले नहीं जाता, बल्कि अपने साथ वह पैसा, रोजगार और व्यापार भी ले जाता है तथा अपने पीछे कई लोगों को बेरोजगार छोड़ जाता है। मोदी सरकार की नजर अब तक इस भीषण समस्या पर नहीं गई है।

मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय संगठनों की नीतियों के माध्यम से देश में अच्छे दिन लाना चाहती है। यह प्रयोग देश के कई प्रधानमंत्री कर चुके हैं, लेकिन वे नाकाम रहे। समझने वाली बात यह है कि नव-उदारवादी व्यवस्था में जब तक हम अपने लोगों को सामान खरीदने की ताकत नहीं देंगे, तब तक अर्थव्यवस्था में गतिशीलता नहीं आएगी। भारत में किसी भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। अब तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी विश्वास डोलने लगा है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी ने कहा है कि आर्थिक सुधारों के लिए यदि जरूरी कदम न उठाए गए, तो उसका असर भारत में होने वाले निवेश पर पड़ेगा। मूडी ने यह भी कहा कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास जो संख्या बल है, उससे यह नहीं लगता कि मोदी सरकार आर्थिक सुधारों के मद्देनजर कोई बड़ा कदम उठा पाएगी। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं निराशा हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की जनता मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। मोदी सरकार को आर्थिक बदलाव के लिए अविन्यक्त सक्रिय होना पड़ेगा। उद्योग, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात समेत कई क्षेत्रों की स्थिति ठीक नहीं है। मोदी सरकार के 18 महीने बीत चुके हैं। लोग अब सरकार की नीतियों के नतीजे देखना चाहते हैं। मोदी सरकार अगर विफल होती है, तो देश निराशा के एक ऐसे दौर में जा पहुंचेगा, जिसमें कई लोगों का प्रजातांत्रिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 07 अंक 40

दिल्ली, 07 दिसंबर-13 दिसंबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक

संतोष भारतीय

संपादक समन्वय

डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)

प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक

सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,

हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001

फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के-2, गैसन, चौधरी बिल्डिंग, कनांट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैसन, चौधरी बिल्डिंग कनांट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कंप कार्यालय एक-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-6451999

6450888

विज्ञापन व प्रसार 022-42296060

+91-8451050786

+91-9266627379

फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है। बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समस्त कानूनी विषयों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा।

दिल्ली का बाबू



नीतीश की नई टीम

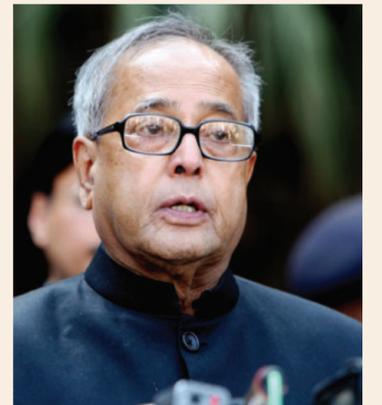
एतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अपने काम पर लौट आए हैं। पहले के मुकाबले इस बार स्थिति थोड़ी अलग जरूर होगी। एक तो राजद के साथ गठबंधन की सरकार और दूसरी ओर लालू यादव। लेकिन, नीतीश तेजी से बाबुओं की अपनी टीम फिर से तैयार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री से नज़दीकी की वजह से चरिष्ठ आईएसएस अधिकारी आमिर सुब्हानी को गृह विभाग से हटाना पड़ा था। सबसे पहला काम नीतीश ने यह किया है कि वह सुब्हानी को एसके राकेश की जगह फिर से गृह विभाग में ले आए। एसके राकेश को पुनः पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिन्हा के मुताबिक, बाबुओं के विभागों में एक मामूली फेरबदल और होना है। ■

बाबू बनाम सरकार

उत्तर प्रदेश में नौकरशाह अखिलेश यादव द्वारा लगातार स्थानांतरण करने की वजह से बहुत परेशान हैं, जिसे लेकर उनकी सरकार बेहद उत्साहित है। हालांकि, वह अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और आगामी चुनाव उनके दिमाग में है। लखनऊ में आयोजित सोशल इंटरप्राइज सम्मिट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अखिलेश यादव ने कई आगंतुकों एवं अधिकारियों को यह कहकर डरा दिया कि अगर वे सरकार की नीतियां सही ढंग से लागू नहीं करेंगे, तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में बाबू नहीं फंसना चाहते। ऐसा लगता है कि बाबुओं और सरकार के बीच संबंध थोड़े तल्ल हो गए हैं। भले ही किसी ने अखिलेश के बयान पर त्वरित प्रतिक्रिया न दी हो, लेकिन कुछ बाबुओं ने बोलना शुरू कर दिया है। निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की शिकायत राज्यपाल से की है। ■

वरीयता क्रम का असमंजस

कुछ लोगों को लगता है कि बीते जून माह में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और नए केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) का शपथ ग्रहण एक नियमित कार्यक्रम था, लेकिन ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों के वरीयता क्रम को लेकर असमंजस में थे कि प्रोटोकॉल के अनुसार किसे पहले शपथ लेनी चाहिए। राष्ट्रपति ने अपनी यह उलझन केंद्रीय गृहमंत्री से भी साझा की थी। नौकरशाहों ने तब इस बात की तस्दीक की कि दोनों में से किसी का भी नाम आधिकारिक वरीयता क्रम की सूची में शामिल नहीं है, ऐसे में सरकार का फैसला अंतिम होगा। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटे पहले सरकार कई नियम-कायदों की पड़ताल करके इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सीवीसी सीआईसी से वरिष्ठ हैं, इसलिए केवी चौधरी को विजय शर्मा से पहले शपथ दिलाई जाएगी। इस समस्या के समाधान के बाद सबसे राहत की सांस ली। यहां सबसे रोचक बात यह रही कि पर्दे के पीछे समस्या के निराकरण के समय किसी तरह का कोई नाटक नहीं हुआ। ■



dilipcheran@gmail.com



सपा से तालमेल की अटकलें खारिज करने वाली मायावती दूसरी तरफ़ अकबरुद्दीन औवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन से तालमेल को प्राथमिकता दे रही हैं। बसपाई गलियारे में कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की भुनभुनाहट साफ़-साफ़ सुनी जा सकती है। बसपा में मायावती के अलावा कोई अन्य नेता मुंह नहीं खोलता, लेकिन कुछ नेता गुपचुप तरीके से औवैसी की पार्टी के साथ बसपा के तालमेल को क़रीब-क़रीब तय बताते हैं। यह सब जानते हैं कि मायावती समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को मुस्लिम वोटों के कारण ही करारा झटका लगा था। इस वजह से बसपा को यह उम्मीद है कि एमआईएम के साथ तालमेल कर उसे मुसलमान मतदाताओं का व्यापक समर्थन हासिल हो सकता है।

उत्तर प्रदेश : अधर में महागठबंधन

जब तेवर में हो गरमी, तो रिश्तों में कैसे आए जरमी!



प्रभात रंजन धन

बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का प्रयोग दोहराने के दबाव के बीच समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच मतभेद गहराने लगे हैं। तीनों पार्टियां एक-दूसरे पर तलख टिप्पणियां कर रही हैं। इसमें कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कुछ अधिक तलख हैं। बहुजन

समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश महागठबंधन में सपा के साथ शामिल होने की संभावनाओं पर पानी डाल दिया है। मायावती ने ऐसे किसी भी तालमेल में शामिल होने से मना कर दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी की मौजूदगी हो। बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के बसपा या कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावना बन सकती है, लेकिन दोनों ही दलों ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखने के बयान देने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने तो मुलायम सिंह के जन्मदिवस समारोह पर भी तलख टिप्पणियां कीं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने बूते चुनाव लड़ेगी। बसपा ने भी कह दिया कि वह 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने ऐसी सभी अटकलबाजियों को खारिज कर दिया।

सपा से तालमेल की अटकलें खारिज करने वाली मायावती दूसरी तरफ़ अकबरुद्दीन औवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन से तालमेल को प्राथमिकता दे रही हैं। बसपाई गलियारे में कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की भुनभुनाहट साफ़-साफ़ सुनी जा सकती है। बसपा में मायावती के अलावा कोई अन्य नेता मुंह नहीं खोलता, लेकिन कुछ नेता गुपचुप तरीके से औवैसी की पार्टी के साथ बसपा के तालमेल को क़रीब-क़रीब तय बताते हैं। यह सब जानते हैं कि मायावती समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को मुस्लिम वोटों के कारण ही करारा झटका लगा था। इस वजह से बसपा को यह उम्मीद है कि एमआईएम के साथ तालमेल कर उसे मुसलमान मतदाताओं का व्यापक समर्थन हासिल हो सकता है। अगर उसे 19 प्रतिशत मुसलमानों का समर्थन मिल गया, तो वह 15 प्रतिशत दलित वोटों के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए अकेली मजबूत दावेदार हो जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर मायावती को पहले से सवर्णों, ख़ास तौर पर ब्राह्मणों का समर्थन मिलता रहा है।

बहरहाल, कांग्रेस सांसद एवं राहुल के खास पीएल पुनिया का बयान गठबंधन-राजनीति के मद्देनज़र काफी महत्वपूर्ण है। पुनिया कहते हैं कि जनता हर जगह बदलाव चाहती है। उनका इशारा स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ़ था। महागठबंधन समाजवादी पार्टी के अलग होने को वह भाजपा-सपा के गोपनीय गठबंधन का नतीजा बताते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस ने फेंसला किया है कि उत्तर प्रदेश में वह किसी से कोई समझौता नहीं करेगी। जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में उसे कांग्रेस सबसे अच्छे विकल्प के रूप में दिख रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री भी इसी अंदाज़ में कहते हैं कि राज्य में सपा और भाजपा दोनों एक साथ हैं। खत्री कहते हैं कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा विरोधी दलों का महागठबंधन फिलहाल शकल में आता नहीं दिख रहा है। खत्री मानते हैं कि सपा और बसपा दोनों ही भाजपा के साथी हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो कांग्रेस कार्यसमिति ही गठबंधन में जाने या न जाने का फेंसला लेने के लिए अधिकृत है, लेकिन वह निजी तौर पर ऐसे किसी भी गठजोड़ में कांग्रेस के शामिल होने के खिलाफ़ हैं, जिसमें सपा या बसपा हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़े और विधायकों की संख्या 28 से आगे बढ़ाए, इस पर पार्टी में घनघोर मंथन चल रहा है। खत्री ने कहा कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव खुलेआम मोदी की तारीफ़ कर चुके हैं और महागठबंधन से अलग होकर उन्होंने भाजपा से अपनी साठगांठ साबित भी कर दी है। बसपा भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। बिहार में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही मुलायम और मायावती ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। सपा के खिलाफ़ कांग्रेस



सूबे के लोग गठबंधन-राजनीति के खिलाफ़

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं के आगमन ने आसन्न चुनावों में गठबंधन के प्रयोग की अनिवार्यता महसूस किए जाने का यथार्थ अभिव्यक्त किया। असम में चुनाव है और वहां के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई महागठबंधन की ज़रूरत जता चुके हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरल समेत कई राज्यों में चुनाव हैं और दो साल बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिहार के महागठबंधन की चर्चा ज़रूर है, लेकिन बिहार एवं उत्तर प्रदेश के हालात और राजनीतिक समीकरण अलग-अलग हैं। केंद्र में भाजपा सत्ता में है और प्रदेश में सपा। दोनों पार्टियों को यह विश्वास नहीं है कि वे उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार बना लेंगी। चूंकि दोनों सत्ता में हैं, लिहाजा दोनों को सत्ता विरोधी मतों का भय सता रहा है। राजनीतिक दलों और नेताओं की राय से अलग राज्य की आम जनता गठबंधन राजनीति के खिलाफ़ है और इसे विकास की राह में बाधक मानती है। बसपा नेता मायावती के इंकार और सपा-बसपा के बीच दुश्मनों जैसे व्यवहार के बावजूद गठबंधन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। अतीत में भले ही कई गठबंधन हुए, टूटे और तालमेल के प्रयोग सफल साबित नहीं हुए, लेकिन प्रयोग और दुष्प्रयोग तो जारी हैं। यह भी सत्य है कि बिहार के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों की तुलनात्मक समीक्षा नहीं की जा सकती। बिहार में जनता दल-यू और भाजपा का गठबंधन लंबा चल चुका है। पंजाब में भाजपा और अकांली दल का गठबंधन लंबे अर्से से चल रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसे प्रयोगों का आजमाइश-स्थल रहा है, लेकिन यहां गठबंधनों की उम्र अधिक नहीं रही। धुर राजनीतिक विरोधी कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ भी एक सरकार में साथ-साथ रह चुके हैं, लेकिन कोई भी पांच साल तक सरकार नहीं चला सका। उत्तर प्रदेश में गठबंधन राजनीति से सरकार बनाने का प्रयोग पहली बार 1967 में हुआ, जब चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल (लोकदल) बनाया और सरकार बनाई। उस सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ भी शामिल हुए, लेकिन वह सरकार एक साल भी नहीं चली। चरण सिंह के बाद 1970 में कांग्रेस से अलग हुए विधायकों ने त्रिभुवन नारायण सिंह के नेतृत्व में साझा सरकार बनाने का प्रयोग किया, जिसमें कई अन्य दलों के साथ जनसंघ भी शामिल था, लेकिन सरकार छह महीने नहीं चल सकी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल से नाराज़ विभिन्न राजनीतिक दलों ने 1977 में जनता पार्टी के नाम से गठबंधन तैयार किया, इसमें भी जनसंघ शामिल था। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यह बहुदलीय सरकार भी कुछ ही दिनों में धराशायी हो गई। 1980 में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में फिर वापस आ गई। 1989 में देश एवं प्रदेश में फिर गठबंधन राजनीति का प्रयोग हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बोफोर्स तोप की खरीद में घोटेले का आरोप लगाकर उनके मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बगावत कर दी। कांग्रेस विरोधी दलों ने पहले जनमोर्च और फिर जनता दल के नाम से गठबंधन बनाया। भाजपा भी उन्हें बाहर से समर्थन देने पर राजी हो गई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में पांच दिसंबर, 1989 को जनता दल की सरकार बनी, लेकिन यह भी पांच साल नहीं चल सकी। राम मंदिर आंदोलन के चलते भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। फिर कांग्रेस ने मुलायम को समर्थन दिया, लेकिन वह भी कायम नहीं रहा। इसके बाद हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत लेकर भाजपा सत्ता तक पहुंची, लेकिन अयोध्या में विवादस्पद टांचा ठहरे के कारण कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो गई। फिर चुनाव हुआ। भाजपा से निपटने के लिए सपा-बसपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन का प्रयोग दोहराया। चुनाव में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। मुलायम सिंह यादव पांच दिसंबर, 1993 को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार भी तीन जून, 1995 को गेस्ट हाऊस कांड के चलते गिर गई और सपा-बसपा में दुश्मनी भर गई। तब भाजपा और बसपा एक हो गईं। मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन यह सरकार भी अधिक समय तक नहीं चल सकी। 1996 में फिर चुनाव हुए, लेकिन किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और बसपा के बीच समझौते के तहत छह-छह महीने के मुख्यमंत्रित्व पर सहमति बनी। मायावती 21 मार्च, 1997 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनीं। सरकार में भाजपा भी शामिल हुई, लेकिन मायावती ने सियासी वेईमानी की मिसाल कायम करते हुए छह महीने बाद कल्याण सिंह को सत्ता सौंपने से इंकार कर दिया। इस पर भाजपा ने बसपा के विधायकों को तोड़कर कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो 2002 तक चली। 2002 में हुए चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और बसपा ने पुरानी कटुता भुलाकर फिर साझा सरकार बनाने का फैसला किया, लेकिन डेढ़ साल में ही दोनों के बीच राह इतनी बढ़ गई कि 29 अगस्त, 2003 को सरकार जाती रही। फिर मुलायम सिंह ने भाजपा और बसपा के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई। 2007 में प्रदेश की जनता ने गठबंधनगामी परिणाम देने से परहेज कर लिया। प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बसपा की सरकार बनी। 2012 में भी जनता ने यही किया और गठबंधन से परहेज करते हुए समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर उसकी सरकार बनवा दी। कुछ राजनीतिक समीक्षकों को 2017 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से ऐसी ही उम्मीद है। राज्य के आम लोग मानते हैं कि अवसरवादी गठबंधन विकास के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनता है। ■

इतनी तलख हो गई है कि उसने मुलायम सिंह यादव के 76वें जन्मदिवस पर उत्तर प्रदेश के सैफई में किए गए आयोजन पर भी करारा प्रहार किया। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि मुलायम का जन्मदिवस समारोह दिखावा है और कांग्रेस इस तरह की फिजूलखर्ची की तीव्र भर्त्सना करती है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख के जन्मदिवस पर करोड़ों रुपये खर्च करके भव्य आयोजन किया जाना घोर निंदनीय है। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद)

के अध्यक्ष अजित सिंह भी उत्तर प्रदेश में महा-गठबंधन के प्रयोग में रालोद के शामिल होने से इंकार कर चुके हैं। रालोद ने भी कांग्रेसियों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सैफई में करोड़ों रुपये खर्च करके समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह का आलीशान जन्मदिवस समारोह मनाया जाना जनविरोधी कृत्य है। उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में है। ऐसे में किसानों की तरफ़ ध्यान देने के बजाय सरकार सैफई में मुलायम सिंह का जन्मदिवस मनाने में लगी रही। यदि समारोह पर खर्च की गई रकम का इस्तेमाल बीज

खरीदने में कर लिया जाता, तो पूरे प्रदेश के किसानों को बीज मुफ्त में मिल जाते। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मसूद अहमद ने कहा कि सिर्फ़ एआर रहमान की टीम के मुंबई से सैफई आने-जाने का खर्च दो करोड़ रुपये आया। इसके अलावा खाना बनाने वाले गुजरात, बिहार एवं महाराष्ट्र से बुलाए गए थे। इसी से बेहिसाब खर्च का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मसूद ने कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश को अपनी जागीर समझ लिया है। रालोद महासचिव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में न जाने को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि शपथ ग्रहण में पूरे देश के लोग जुटे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश औपचारिकता निभाना भी भूल गए। बिहार जाने के बजाय वह सैफई में संगीतकार एआर रहमान का स्वागत करने चले गए, यह अत्यंत दुःख की बात है।

लम्बोलुबाव यह है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की संभावनाओं के अब तक सोचे गए विभिन्न कोणीय समीकरणों पर फिलहाल विराम लग गया है। अब महागठबंधन के नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही उत्तर प्रदेश में गठजोड़ की संभावनाओं पर सकारात्मक रुख दिखाकर इस चर्चा को गर्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के तीखे तेवर देखते हुए सपा प्रमुख मुलायम भी आपा खोने लगे हैं। पिछले दिनों जनेश्वर मिश्र पार्क में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज देश को समर्पित करते हुए मुलायम बोले कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करती है। मुलायम ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि तिवारी यदि समाजवादी पार्टी में होते, तो समाजवादी नेताओं में उनका नाम अग्रणी होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बने रहने के लिए ऊंची कृपा होनी चाहिए। अगर कृपा नहीं रही, तो आप कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, विडंबना यह है कि जिन्होंने कभी गांव-खेत के दर्शन नहीं किए, वे कांग्रेसी भी अब किसानों का मसीहा बनने का नाटक कर रहे हैं। पगडंडी और मेड़ पर चलने का जिन्हें अभ्यास नहीं, वे किसानों के हितों के संरक्षक बन रहे हैं। दुर्भाग्य से इस देश में ज़्यादातर समय ऐसे ही लोग सत्ता में रहे, जिनका किसानों और खेती से कोई लगाव नहीं रहा। भाजपा और कांग्रेस का कभी खेती, गांव-गरीब से कोई रिश्ता नहीं रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि एक सकारात्मक कृषि नीति के अभाव में किसानों को फसल का लाभप्रद मूल्य तो मिला नहीं, सकल घरेलू उत्पादों में कृषि का हिस्सा भी कम होता गया। चौधरी कहते हैं कि मुलायम सिंह बराबर इस बात पर ज़ोर देते आए हैं कि किसानों की तरक्की के बिना देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि के लिए रखा था। प्रदेश में 2012 के चुनाव के बाद बहुमत से बनी समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र के लिए रखा और वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष घोषित किया। जब भाजपा नीत केंद्र सरकार ने स्पार्ट सिटी बनाने की बात कही, तो अखिलेश ने स्पार्ट विलेज की अवधारणा रखी। ■



महागठबंधन के तीनों घटक दलों ने पांच विधायकों पर एक मंत्री का सूत्र इस्तेमाल किया। यदि इसी सूत्र के आधार पर महिलाओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाता, तो चार महिला विधायकों को मंत्री पद मिलना तय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के सभी पांच चरणों को मिलाकर देखें, तो आप पाएंगे कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी 59.92 फीसद रही। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी, जिसके चलते मंत्रिमंडल के गठन के समय महिला विधायकों की उपेक्षा कर दी गई।

सातवां वेतन आयोग आसान नहीं सरकार की राह

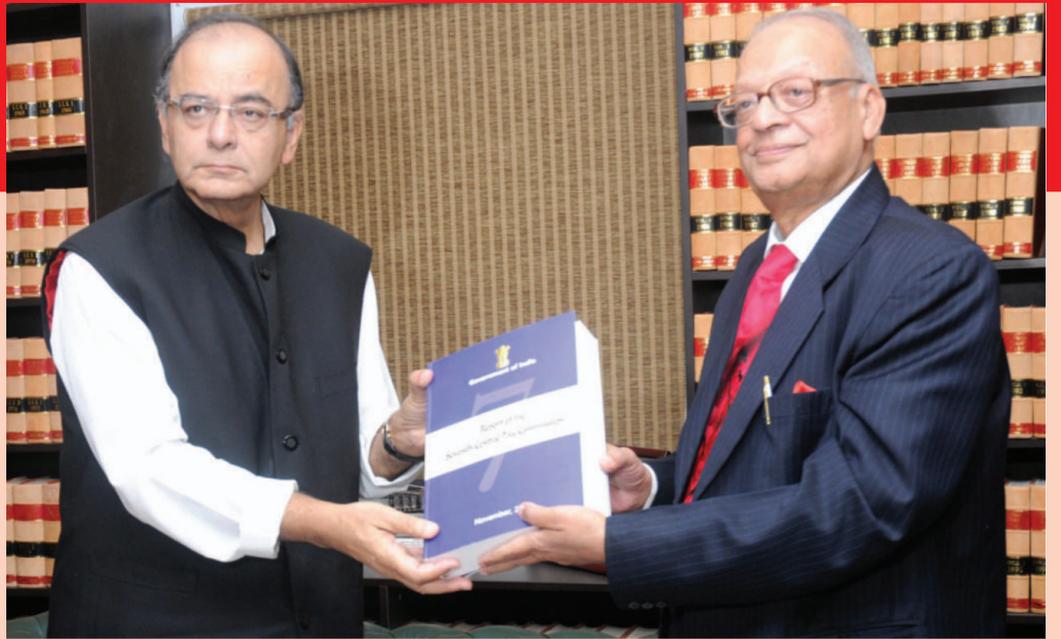
आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम तनखाह को 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया है। जबकि सचिव स्तर के अधिकारियों की तनखाह को 80 हजार से बढ़ाकर लगभग सवा दो लाख कर दिया गया है। इसके अलावा सैलरी में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन छोटे कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट में केवल अधिकारियों की तनखाह में बड़ा इजाफा किया गया है जबकि कर्मचारियों की तनखाह में मामूली।

अरुण तिवारी

जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी 900 पन्नों वाली रिपोर्ट सौंप दी है। सातवें वेतन आयोग का यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में गठन किया था। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन वह निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया, इसके बाद उसे चार महीने का समय और दिया गया था। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 प्रतिशत, वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में कुल 63 प्रतिशत, पेंशन में 24 प्रतिशत और औसतन 23.55 प्रतिशत इजाफे की अनुशंसा की है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएँ 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी। इसका फायदा 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों को होगा। इन अनुशंसाओं के लागू होने के बाद सरकारी खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 1.02 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च में से 74 हजार करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट से उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 28 हजार करोड़ रुपये रेल बजट से खर्च किए जाएंगे। यह राशि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.65 प्रतिशत होगी, छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में यह वृद्धि जीडीपी का 0.7 प्रतिशत थी। आयोग ने सैलरी में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुशंसा की है।

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ने से बाजार में तरलता में वृद्धि होगी, जिससे महंगाई में बढ़ोत्तरी होगी। जिस तरह छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद दोपहिया-चारपहिया वाहनों और कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में इजाफा हुआ था, कुछ वैसा ऐसा ही कुछ सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के बाद होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुपहिया वाहनों की मांग में 2 से तीन प्रतिशत और चारपहिया वाहनों की बिक्री में 5 से 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सरकार के ऊपर पहले से ही फिस्कल डेफिसिट को कम करने का दबाव है, ऐसे में पहले

सेना में वन रैंक, वन पेंशन को लागू करने के बाद दबाव बढ़ा है। इसके बाद सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने से सरकार के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम(एफआरबीएम) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर पाना आसान नहीं होगा, ऐसे ही सरकार ने इस वित्त वर्ष सेवा कर को पहले 12.36 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया, इसके बाद इसमें 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस लागू कर दिया है। जो बात अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कही थी कि राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2015-16 में जीडीपी का 3.9 प्रतिशत, 2016-17 में 3.5 प्रतिशत और 2017-18 में तीन प्रतिशत रहेगा, लेकिन सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद सरकार इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी। वर्तमान में राजकोषीय घाटा 4.1 प्रतिशत है। ऐसे में सरकार के पास केवल चार रास्ते हैं। पहला वह कर में वृद्धि करे, दूसरा, अपने खर्च में कटौती करे और तीसरा, कर्ज ले या एफडीआई के लिए रास्ता खोले। एनडीए सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में कई बार यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि हो चुकी है, सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी रेलवे में कार्यरत हैं, ऐसे में रेल बजट पर पड़ने वाला 28 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ की पूर्ति सरकार के लिए कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। किराए और माल भाड़े में वृद्धि करके सरकार यात्रियों के लिए किसी तरह की



सुविधाओं का इजाफा नहीं कर पाएगी। ऐसे में रेलवे में एफडीआई लाना ही उसके पास एकमात्र और अंतिम रास्ता बचता है जिसे वह अपनाएंगे। ऐसे ही अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रेलवे में एफडीआई के संकेत दे चुके हैं।

आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम तनखाह को 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया है। जबकि सचिव स्तर के अधिकारियों की तनखाह को 80 हजार से बढ़ाकर लगभग सवा दो लाख

कर दिया गया है। इसके अलावा सैलरी में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन छोटे कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सातवें वेतनमान आयोग की रिपोर्ट में केवल अधिकारियों की तनखाह में बड़ा इजाफा किया गया है जबकि कर्मचारियों की तनखाह में मामूली। इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का अनुपात 1:12 हो जाएगा। हालांकि न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी इसे 26 हजार रुपये करने की मांग कर रहे थे। आयोग ने कर्मचारियों का परफॉर्मस रिलेटेड पे(पीआरपी) लागू करने का प्रस्ताव दिया है। आयोग का मानना है कि सरकार को पीआरपी को एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करना चाहिए। ताकी सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी बेहतरतर परफॉर्मस दें। पर ये भी सिफारिश की है कि 20 साल सही परफॉर्मस नहीं करने वाले का इन्कीमेंट रोक दें। दो वजहों हैं। पहली- जब भी कोई नौकरी जवाइन करता है तो कुछ साल प्रोबेशन पर रहता है। उसी के बाद वास्तविक जिम्मेदारी शुरू होती है। दूसरी- उसे परफॉर्मस दिखाने का पर्याप्त समय मिले, ताकि वह कोई बहाना न बना सके।

केंद्रीय कर्मचारियों की तनखाह के बढ़ने से कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स में 6 से 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जिसका महंगाई से सीधा वास्ता है।

यदि मांग और आपूर्ति के बीच सही संतुलन नहीं बनाया गया तो महंगाई के रूप में जनता को खामियाजा भुगतान पड़ेगा। हालांकि औद्योगिक विकास दर इससे जरूर बढ़ेगी लेकिन इसका फायदा जनता को नहीं, उद्योगपतियों को होगा। आयोग ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वन रैंक-वन पेंशन देने, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने, वेतन निर्धारण के लिए ग्रेड पे और पे बैंड की व्यवस्था खत्म करने, पैरा मिलेट्री फोर्स को भी शहीद का दर्जा देने, सैन्य सेवाओं के कर्मचारियों की तनखाह दोगुनी करने (केवल सेना पर लागू होगा) जैसी अनुशंसा की है। साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का सेवाकाल अधिकतम 33 साल तय किए जाने की अनुशंसा भी की है। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी। इस तरह की अनुशंसाओं का भी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं।

हालांकि सरकार आयोग की कितनी अनुशंसाओं को लागू करती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसके अलावा सरकार अपने आय और व्यय में किस तरह संतुलन लाएगी यह फरवरी में आने वाले बजट में दिखाई पड़ जाएगा।

feedback@chauthiduniya.com

महत्वपूर्ण अनुशंसाएं

1. बेसिक सैलरी में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
2. न्यूनतम वेतन 18,000 हजार रुपये हो जाएगा।
3. भत्तों में 63 फीसद की बढ़ोतरी होने के साथ ही पेंशन में 24 फीसद बढ़ोतरी।
4. सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकार पर एक लाख दो हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
5. सातवें वेतन आयोग के तहत की गई ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी।
6. पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी मिलेगा शहीद का दर्जा।
7. सैलरी में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा।
8. फायदा 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारकों को होगा।
9. पे-बैंड और ग्रेड-पे की प्रणाली को खत्म करने की सिफारिश।
10. सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वन रैंक, वन पेंशन लागू करने की सिफारिश।
11. शॉर्ट सर्विस कमीशन के कर्मचारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोड़ने की अनुमति होगी।

मंत्रिमंडल में महिलाओं को मिले पूरा हक

महागठबंधन की ओर से चुनाव में उतरी 25 महिला उम्मीदवारों में से 23 ने जीत दर्ज की। नोखा की विधायक अनीता देवी राजद कोटे से मंत्री बनाई गई, जबकि जदयू कोटे से चेरिया बरियारपुर की विधायक मंजू वर्मा मंत्री बनीं। महा-गठबंधन के तीसरे घटक दल कांग्रेस की चार महिला विधायकों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनने वाली दोनों महिला विधायकों ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता है।

दिव्या त्रिपाठी

देश की आधी आबादी ने स्वयं को हर क्षेत्र में साबित किया है। सीमा की सुरक्षा से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक सभी जगहों पर महिलाएं पुरुषों के साथ खड़ी नजर आती हैं। महिलाएं समाजसेवा में पीछे नहीं हैं, राजनीति में पीछे नहीं हैं, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के बावजूद अक्सर उन्हें नेतृत्व की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। बिहार सरकार के गठन में महिला विधायकों की उपेक्षा इस बात का ताजातरीन उदाहरण है। राज्य की आधी आबादी ने मतदान में सबसे ज्यादा भागीदारी की। चुनाव में महिलाओं का समर्थन महागठबंधन को मिला, लेकिन मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं का चेहरा पीछे नजर आ रहा है। महिलाओं की उम्मीदों को ग्रहण तब लगा, जब सरकार गठन के समय सिर्फ दो महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के साथ ही विभागों का भी बंटवारा



हो चुका है।

महागठबंधन की ओर से चुनाव में उतरी 25 महिला उम्मीदवारों में से 23 ने जीत दर्ज की। नोखा की विधायक अनीता देवी राजद कोटे से मंत्री बनाई गई, जबकि जदयू कोटे से चेरिया बरियारपुर की विधायक मंजू वर्मा मंत्री बनीं।

महागठबंधन के तीसरे घटक दल कांग्रेस की चार महिला विधायकों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनने वाली दोनों महिला विधायकों ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता है। पिछली बार मंत्री रहें लेसी सिंह एवं बीमा भारती को इस बार नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली। चुनाव के दौरान राज्य की महिला मतदाताओं ने नीतीश कुमार का जबरदस्त समर्थन किया, क्योंकि वे नीतीश सरकार के कामकाज से काफी खुश हैं। खासकर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने के चलते वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करती रही हैं। राजद के साथ गठबंधन के बावजूद महिलाओं ने नीतीश कुमार पर विश्वास करते हुए महागठबंधन के पक्ष में जमकर मतदान किया।

महागठबंधन के तीनों घटक दलों ने पांच विधायकों पर एक मंत्री का सूत्र इस्तेमाल किया। यदि इसी सूत्र के आधार पर महिलाओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाता, तो चार महिला विधायकों को मंत्री पद मिलना तय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के सभी पांच चरणों को मिलाकर देखें, तो आप पाएंगे कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी 59.92 फीसद रही। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी, जिसके चलते मंत्रिमंडल के गठन के समय महिला विधायकों की उपेक्षा कर दी गई। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरसंभव प्रयास किए। पंचायती राज्य एक्ट 2006 के तहत महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना। क्या मंत्रिमंडल के गठन में राज्य की महिलाओं की उपेक्षा नहीं की गई? राजनीति में जब-जब महिलाओं को समुचित भागीदारी देने की बात आती है, तो यह सवाल किसी न किसी तरह हाशिये पर डाल दिया जाता है। आखिर आधी आबादी को बराबरी का हक कब मिलेगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में पूर्ण शराबबंदी

नीतीश के साहस को सलाम



सरोज सिंह

पटना में 9 जुलाई, 2015 को आयोजित ग्रामवार्ता कार्यक्रम में नीतीश कुमार अपने संबोधन के बाद बैठ चुके थे। इसी बीच एक महिला की आवाज गुंजी-मुख्यमंत्री जी, शराब बंद कराइए घर बर्बाद हो रहा है। कई और महिलाएं बोले लगीं। सीएम उठे, माइक पर बोले अगली बार सरकार में आए, तो कर दूंगा। नीतीश कुमार के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूँज उठा। नीतीश कुमार की इस घोषणा को विपक्षी दलों ने चुनावी घोषणा कह कर बहुत ही हल्के में लिया। चुनाव के समय भी बार-बार विरोधी दलों ने इस बात को लेकर नीतीश कुमार पर ताना जड़ा कि नीतीश केवल वोट लेने के लिए शराबबंदी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इस एलान को न केवल अपने सात निश्चय में शामिल किया, बल्कि सरकार बनने के बाद अपने पहले ही सार्वजनिक भाषण में पहली अप्रैल, 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध का एलान कर दिया। मध्य निषेध दिवस पर नीतीश कुमार ने कहा कि शराब से गरीबों का जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है। कुछ समय पहले मैंने श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं की मांग पर वादा किया था कि अगली बार आए तो शराब बंदी लागू कर दूँगे। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। एक अप्रैल से ऐसी नीति लागू करेंगे कि

सरकार के आला अफसर भी दूसरी जगह जारी शराबबंदी के मॉडल की समीक्षा में जुट गए हैं। नीतीश कुमार इस बात को जान रहे हैं कि अगर वह शराबबंदी लागू करने में सफल रहे तो फिर जिस तरह महादलितों का एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने बनाया, ठीक उसी तरह महिलाओं का भी एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। इसलिए सरकार के स्तर पर पूरी कोशिश है कि शराबबंदी का हाल गुटखा जैसा न हो।

गरीब के जीवन पर शराब के कारण छाने वाला अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयोग होगा कि नशा सेवन के कारण आमदनी का पैसा शिक्षा पर खर्च हो, पोषणयुक्त भोजन पर खर्च हो, न कि नशा सेवन पर। ऐसे परिवार की महिलाओं को शराबबंदी से खुशी मिलेगी और परिवार का विकास तेजी से होगा। मैंने मुख्य सचिव और उत्पाद विभाग को नई नीति बनाने का आदेश दे दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीने वाले दो तरह के होते हैं। पहला वे लोग, जिनके पास अकूत संपत्ति है, वे महंगी शराब पीते हैं। ऐसे लोगों को शराब से होने वाले

नुकसान की जानकारी रहती है, फिर भी वे शराब पीते हैं, जबकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरे वे लोग हैं, जो देशी और मसालेदार शराब पीते हैं। कम आमदनी वाले लोग इस तरह की शराब ज्यादा पीते हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी की घोषणा का व्यापक स्वागत हुआ, लेकिन इस फैसले ने कई तरह की आशंकाओं को भी जन्म दिया। गौरतलब है कि 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शराब पर रोक लगायी थी, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। तस्करी तथा कई अन्य व्यवहारिक दिक्कतें सामने आईं। बहुत मायनों में यह राजनीतिक मसला भी बना। अंततः डेढ़ साल बाद नई सरकार ने रोक हटा दी। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि प्रदेश में पान मसाले पर भी प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। हां, अंतर यह आया है कि पहले यह दुकानों में खुलेआम बिकता था, पर अब दुकानदार इसे छिपा कर ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं। जहां तक छिपा कर बेचने की बात है तो यह केवल पटना में ही है। दूसरे शहरों में यह खुलेआम बेचा जा रहा है। इसी आधार पर आशंकाओं ने जन्म लिया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि नीतीश ने अपने अधिकारियों से साफ कर दिया है कि शराबबंदी में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के आला अफसर भी दूसरी जगह जारी शराबबंदी के मॉडल की समीक्षा में जुट गए हैं। नीतीश कुमार इस बात को जान रहे हैं कि अगर वह शराबबंदी लागू करने में सफल रहे तो फिर जिस तरह महादलितों का एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने बनाया, ठीक उसी तरह महिलाओं का भी एक

राज्य में शराब की 5967 दुकानें

5967 5446 2471 1434

स्वीकृत दुकानें बन्दोबस्त दुकानें देशी शराब की दुकानें विदेशी शराब की दुकानें

521 दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं हो सकी

10 वर्षों में 1255 प्रतिशत बढ़ा राजस्व

वर्ष	राजस्व राशि करोड़ रु. में
2005-06	295
2009-10	1099
2010-11	1543
2011-12	2045
2012-13	2432
2013-14	3173
2014-15	3220
2015-16	4000 लक्ष्य

अक्टूबर 2015 तक 2240 करोड़ रुपये की वसूली

सालाना 1410 लाख लीटर से अधिक खपत

देशी शराब	विदेशी शराब	बीयर
990.36 लाख लीटर	420 लाख लीटर	512.37 लाख लीटर

इन राज्यों में है रोक

गुजरात, नागालैंड, लक्षदीप तथा मणिपुर के कुछ हिस्सों में, केरल में 30 मई 2014 के बाद से शराब दुकानों को लाइसेंस मिलना बंद हो गया है। ऐसा अगले कुछ वर्षों में पूर्ण पाबंदी के मकसद से हो रहा है।

यहां पहले था प्रतिबंध

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम में शराबबंदी हुई थी, लेकिन कारगर न हो सकी। अब यहां शराब बिकती है।

बड़ा वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। इसलिए सरकार के स्तर पर पूरी कोशिश है कि शराबबंदी का हाल गुटखा जैसा न हो। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि पुलिसवाले की मनमानी काफी बढ़ जाएगी और बढ़े हुए दाम पर चोरी-छिपे शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इस आशंका में दम भी है, इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि इस तरह की बातें सामने न आए। अन्यथा यह पूरा मिशन ही भटक जाएगा और नीतीश कुमार के इमेज को भी दाग लगेगा। फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि शराबबंदी का एलान कर नीतीश कुमार ने साहस का काम किया है और कोई 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है।

feedback@chauthiduniya.com

अपर्णा के स्टैंड से सकते में सपा

मुलायम की बहू ने आमिर को धिक्कारा

वैष्णवी वंदना

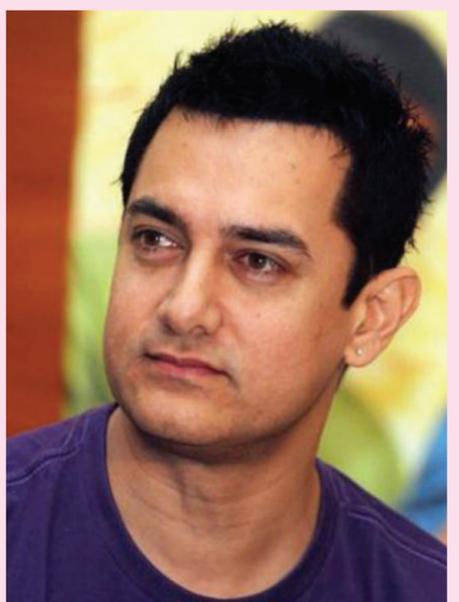
समाजवादी पार्टी की नीतियां मुलायम परिवार के अंदरूनी विरोधाभास में खंडित और प्रतिखंडित होती रहती हैं और कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी भ्रम की स्थिति बनती रहती है। सपा कार्यकर्ताओं और सामान्य नेताओं को यह समझ में ही नहीं आता कि वे देश-प्रदेश के जरूरी मसलों पर मुलायम परिवार से आने वाले परस्पर विरोधी बयानों में आखिर किस तरफ खड़े हों। सहिष्णुता और असहिष्णुता के ताजातरीन सियासी मसले पर भी ऐसी ही स्थिति बन गई है। मुलायम परिवार का कोई सदस्य असहिष्णुता के आरोपों के पक्ष में खड़ा है तो कोई असहिष्णुता का आरोप लगाने वालों को धोने में लगा है। समाजवादी पार्टी से गहरे जुड़े महाकवि गोपाल दास नीरज असहिष्णुता के मसले पर पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों को आडम्बरी बता कर अपनी खुली प्रतिक्रिया जता चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड इसके विपरीत रहा है। नीरज ने कहा था कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार सस्ती राजनीति कर रहे हैं। इन साहित्यकारों को कांग्रेस के राज में पुरस्कार मिला था और अब वही इनसे ये पुरस्कार लौटाने का काम करवा रही है। इससे कांग्रेस की ही बदनामी हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने असहिष्णुता का आरोप लगाने वाले फिल्म अभिनेता आमिर खान को आड़े हाथों लिया है और देश के लोगों द्वारा मिले प्रेम और समर्थन का ऐसा प्रतिकार करने के खिलाफ आमिर की खूब निंदा की है। मुलायम के छोटे पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव के इस स्टैंड से सपा नेतृत्व सकते में है। समाजवादी पार्टी ने इस मसले में आमिर खान का पक्ष लिया था और पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान भी आया था। मुलायम की बहू अपर्णा यादव ने आमिर खान के खिलाफ जो कमेंट लिखे, वह सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया और उस पर देशभर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। अपर्णा ने अपने फेसबुक-टाइमलाइन पर लिखा, यह सत्यापित हो गया है कि आमिर खान सिर्फ अभिनेता हैं, जो कि रंग दे बसंती और मंगल पांडे जैसे देशभक्तों के किरदार निभाने के बावजूद अपनी पत्नी को देश प्रेम नहीं समझ पाये। हमारी गलती है कि आमिर से इतनी बड़ी अपेक्षा की। जय हिन्द, जय भारत! इससे पहले भी अपर्णा यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ कर सुधियां बटोर चुकी हैं। आमिर पर अपर्णा के कमेंट से यह जाहिर हुआ कि फिल्म अभिनेता आमिर खान को देश में असहनशीलता बढ़ने जैसा महसूस होना और उनकी पत्नी किरण राव द्वारा इस डर से देश छोड़ने की बात करना उन्हें अत्यंत नागवार गुजरा है। उन्हें आमिर



और उनकी बीवी किरण राव की यह बातें बेमानी और फिजूल लगती हैं, लेकिन अपर्णा यादव जो महसूस कर रही हैं, वहीं उनके ससुर मुलायम सिंह यादव ऐसा महसूस नहीं कर रहे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आमिर खान के बयान का समर्थन किया था और कहा था कि आमिर एक बड़े अभिनेता हैं और केंद्र सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मुलायम ने कहा था कि आमिर खान को कहीं चोट लगी होगी, किसी बात पर वे आहत हुए होंगे, तभी उन्होंने असहिष्णुता पर इस तरह का बयान दिया है। हर किसी को अपनी-अपनी राय देने का अधिकार है। अपने विचारों को रखने की इस स्वतंत्रता को ही लोकतंत्र कहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भी आमिर खान के बयान का समर्थन करते हुए एक हाथ आगे बढ़ कर कहा था कि फिल्म अभिनेता को किसी वजह से देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। वह बड़े आराम से उत्तर प्रदेश में आकर रह सकते हैं। उन्हीं की बहू ने आमिर खान को पूरी तरह गलत करार दिया। सपा नेता आजम खान ने आदतन क्रीज से बाहर निकल कर



खलेते हुए फटाफट आमिर खान के समर्थन में चिट्ठी लिख डाली। अपने अलग विचार और तेवर से मुलायम की बहू पहले भी समाजवादी पार्टी को हतप्रभ करती रही हैं। बीफ वाले मसले पर सपा नेतृत्व के स्टैंड के खिलाफ जाकर उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि गाय का मांस खाना जायज नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका यह विचार किसी धर्म विशेष पर कमेंट नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया था कि गाय हमारी मां के समान है और इसका मांस खाना जायज बात नहीं है। गरीबों के बीच गाय काटने पर जो लोग आग भड़काते हैं, वे वे अमीर हैं, जो अपनी थाली में गोमांस परोसे हैं। यदि अमीरों के पैसों से गाय का मांस खया जाएगा तो हिंदुस्तान कल तालिबान कहल-एगा। मेरा ये बयान किसी विशेष धर्म पर टिप्पणी नहीं है। हमें अपनी मां को बचाना ही होगा। इस ट्वीट को अपर्णा ने अपने फेसबुक पेज से भी लिंक किया था, जिसमें हर धर्म से जुड़े लोगों के काफी कमेंट आए। दादरी मसले पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के यूएन जाने की धमकी पर जब सपा नेतृत्व ने आजम के बयान से पल्ला झाड़ लिया और इसे उनका निजी



विचार बताया, तब भी अपर्णा ने विरोधी लाइन लिया और आजम का समर्थन कर डाला। तब अपर्णा ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय फोरम है। ऐसी घटनाएं यूएन में जाएं या नहीं, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र को लिखे आजम के पत्र से भारत की छवि खराब नहीं होती। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की कुछ ही दिनों पहले गोरखनाथ मंदिर के मुख्य महंत योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात ने भी देश का ध्यान खींचा था। अपर्णा ने गोरखनाथ धाम जाकर योगी से मुलाकात की थी और दिवंगत महंत अवैद्यनाथ के प्रति संवेदना जताई थी। अपर्णा ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए थे और महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफलाइटिस पीड़ितों से मुलाकात कर उन्होंने पीड़ितों के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से किए जा रहे इंतजामों की प्रशंसा की थी। सपा नेताओं को अपर्णा द्वारा योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा अत्यंत नागवार गुजरी थी।

feedback@chauthiduniya.com

पेरिस हमले के बाद

यूरोप में बढ़ता इस्लामोफोबिया

शफीक आलम

छले महीने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हुए भयानक आतंकवादी हमलों में लगभग 150 लोग मारे गए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे. इन हमलों के बाद फ्रांस से जिस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, उसके अनुरूप फ्रांस ने आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलान्ड ने हमलों के फौरन बाद कहा था कि फ्रांस का जवाब बेरहम होगा. बहरहाल जहां एक तरफ इन हमलों की जिम्मेदारी लेने वाले आईएसआईएस के ठिकानों पर फ्रांस ने हमले शुरू कर दिए, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही. फ्रांस में हो रही आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में तीन आतंकवादी मारे गए और कई गिरफ्तारियां भी हुईं. लेकिन फ्रांस में इस दौरान एक अहम बयान गुहमंत्रि बैर्ना कासेनेव की ओर से आया, जिसमें उन्होंने उन मस्जिदों को बंद करने की वकालत की थी जहां से दुर्भावना फैलाई जाती है. इसे एक महत्वपूर्ण बयान के रूप में इसलिए भी देखा गया क्योंकि फ्रांस में मुसलमानों की आबादी देश की कुल आबादी की 9.6 प्रतिशत है.

ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई फैसला पहले नहीं लिया गया था. फ्रांस की मैग्जीन शार्ली हेब्डो पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही फ्रांस ने विदेशी अतिवादी इमामों को देशबाद करना शुरू कर दिया था. जिसके तहत 20 इमामों को देश से निकाला दिया गया था. जाहिर है हालिया हमले के बाद इस प्रक्रिया में और तेज़ी आएगी. लेकिन इस तरह के सरकारी रुख की वजह से शक के दायरे में आए मुसलमानों के प्रति दुर्भावना में और अधिक इजाफा हो जाएगा, साथ ही यूरोप के अतिवादी-दक्षिणपंथी नेताओं को भी अपने हमले तेज़ करने का मौका मिल जाएगा. इस वजह से मुस्लिम विरोधी मामलों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी होगी. इस तरह के मामले भी रह-रहकर सामने आने लगे हैं.

शार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हुए आतंकी हमलों के फौरन बाद फ्रांस में 166 मुस्लिम विरोधी घटनाएँ दर्ज की गई थीं, जिनमें बुरा ओढ़ने वाली महिलाओं पर हमले, मस्जिदों के आसपास सूअर का मांस फेंकने और धमकी भरे ई-मेल भेजने जैसे मामले शामिल थे. हालिया पेरिस हमले की वजह से भी यूरोप में मुस्लिम विरोधी ध्रुवीकरण को और मजबूती मिली है. जहां एक तरफ अतिवादी-दक्षिणपंथी अपने देशों में सीरिया से आने वाले शरणार्थियों को पनाह नहीं देने की मांग कर रहे हैं वहीं इन देशों में मुसलमानों के खिलाफ हमले भी हुए हैं, और वही



दरअसल, पेरिस हमले के तत्काल बाद से ही यूरोप में रहने वाले मुसलमानों को आने वाले खतरे का एहसास था. उन्हें महसूस होने लगा था कि एक बार फिर उन्हें इस्लामोफोबिया की नई लहर का सामना करना पड़ेगा. साथ ही उन्हें यह भी आभास हो गया था कि सीरिया से यूरोप आने वाले शरणार्थियों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी एवं अधिक जटिल हो जाएंगी. लेकिन जो सवाल सबसे अहम है वह यह है कि आखिरकार आतंकवाद, खासतौर पर इस्लामिक आतंकवाद से कैसे छूटकारा हासिल किया जाए?

पुराना सवाल एक बार फिर खड़ा हो रहा है कि क्या इस्लाम आधुनिक विचारों के अनुकूल स्वयं को ढाल सकता है या नहीं? यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आज दुनिया में जहां-कहीं भी जंग हो रही है या आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तकरीबन उन सभी जगहों में खुद को मुसलमान कहने वाले और इस्लाम को खतरे से निजात दिलाने का दावा करने वाले लोग शामिल हैं.

इसमें कोई शक नहीं है कि पेरिस हमलों के बाद फ्रांस और यूरोप में आतंकी पर मुस्लिम विरोधी घटनाओं, जैसे मुस्लिम महिलाओं पर हमले और दीवारों पर घृणायुक्त ग्राफिटी बनाने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. फ्रांस में इस्लाम विरोधी भावना का अध्वन करने वाली संस्था नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इस्लामोफोबिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस हमले से पहले जहां प्रतिदिन चार से पांच इस्लाम विरोधी मामले सामने आते थे, वहीं हमले के बाद पहले सप्ताह ही ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 32 तक पहुंच गई. एक दूसरी संस्था कलेक्टिव अगेंस्ट इस्लामोफोबिया इन फ्रांस के मुताबिक इस अवधि में ऐसे 29 मामले सामने आए. प्रेस टीवी न्यूज़ के मुताबिक पेरिस हमलों के बाद से ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया के मामलों में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. कलेक्टिव अगेंस्ट इस्लामोफोबिया इन फ्रांस के प्रवक्ता यासिर लौअती के मुताबिक उनके पास अनेकों शिकायतें आई हैं जिनमें मुसलमानों के ऊपर हमलों का जिक्र है. उनका कहना है कि कई लोग यह सलाह मांग रहे हैं कि ऐसे माहौल में बच्चों को स्कूल भेजना उनके लिए ठीक है या नहीं. इसमें कोई शक नहीं है कि इन हमलों से पहले भी फ्रांस में लगातार मुस्लिम विरोधी हमले होते रहे थे. लेकिन पेरिस की घटना ने कड़ु राष्ट्रवादियों के साथ-साथ अतिवादी दक्षिणपंथी नस्लवादियों

को भी मुसलमानों पर हमले का मौका दे दिया है. यू-ट्यूब पर ऐसे विडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें मुस्लिम औरतों और मर्दों पर हमला करता दिखाया जा रहा है. वहीं ट्विटर और फेसबुक पर भी घृणायुक्त सामग्री अपलोड की जा रही है.

यही नहीं इन हमलों के बाद सीरिया से यूरोप आने वाले शरणार्थियों का सवाल भी कठघरे में खड़ा हो गया है. इस सवाल को और अधिक बल इस तथ्य से मिला कि पेरिस पर हमला करने वाले आतंकियों में से एक के पास सीरिया का पासपोर्ट मिला था. शरणार्थियों के मामले पर सबसे पहले पोलैंड ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सीरिया से पोलैंड आने वाले शरणार्थियों के संबंध में कहा कि वह शरणार्थियों को तभी शरण देगा जब उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी. शरणार्थियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना के तहत पोलैंड को 4500 शरणार्थियों को स्थानांतरित करना था. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन का कहना है कि आतंकवादी मौजूदा संकट का फायदा उठाकर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं. यूरोपीय देशों में कई दक्षिणपंथी गिरोह पिछले कई महीनों से शरणार्थियों से जुड़े खतरे को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं. तकरीबन इसी तरह सभी यूरोपीय देशों के दक्षिणपंथी नेताओं ने यूरोप की शरणार्थी नीति पर पुनर्विचार करने की वकालत की है.

दरअसल, पेरिस हमले के तत्काल बाद से ही यूरोप में रहने वाले मुसलमानों को आने वाले खतरे का एहसास था. उन्हें महसूस होने लगा था कि एक बार फिर उन्हें इस्लामोफोबिया की नई लहर का सामना करना पड़ेगा. साथ ही उन्हें यह भी आभास हो गया था कि सीरिया से यूरोप आने वाले शरणार्थियों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी एवं अधिक जटिल हो जाएंगी. लेकिन जो सवाल सबसे अहम है वह यह है कि आखिरकार आतंकवाद, खासतौर पर इस्लामिक आतंकवाद से कैसे छूटकारा हासिल किया जाए? यह ठीक है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसके साथ यह बात भी माननी होगी कि आतंकवादी खुद को मुसलमान कहते हैं और इस्लाम की रक्षा के नाम पर अपने क्रियाकलापों को अंजाम देने का दम भरते हैं. इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश इस्लामिक देश ही हैं और आतंकवाद का सर्वाधिक दुष्परिणाम भी मुसलमानों को ही भुगतना पड़ रहा है. इसलिए आतंकवाद के दानव से निपटने के उपाय भी मुसलमानों को ही तलाश करने होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

जल और नदियों को बचाने के लिए

महिलाओं की अनोखी पहल

कुमार कृष्ण

गंगा का सवाल पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है. गंगा से करोड़ों देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है और हमारे अधिकांश पर्व-त्योहार एवं धार्मिक अनुष्ठान नदियों के किनारे संपन्न होते हैं. नदियां एक बड़ी आबादी के लिए जीविका का आधार भी हैं. अफसोस यह कि देश की अधिकांश नदियां ने कचरा ढोने वाले मालवाहक की शकल अख्तियार कर ली है. नतीजतन, न केवल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बल्कि नित नई बीमारियां सामने आ रही हैं. नदियों को प्रदूषण मुक्त करने और जीवन के लिए पर्यावरण जल को बचाने की छतपटाहट पूरी दुनिया में देखी जा रही है. अमेरिकी शिक्षाविद् ऐन बैनक्रॉफ्ट के नेतृत्व में दुनिया की आठ साहसी महिलाएं नदियों और जल के सवाल पर जन-जागरूकता फैलाने के लिए इन दिनों यात्रा पर हैं. बैनक्रॉफ्ट ने 1986 में उत्तरी ध्रुव और 1992 में दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करके अपने साहस का परिचय दिया. टीम की दूसरी सदस्य नार्वे की लिव अर्सेनेन हैं, जो बिना किसी सहारे के 2000 में स्की करके अंटार्कटिका महाद्वीप गई थीं. तीसरी हैं, भारत की कुष्णा पाटिल, जिन्होंने बहुत कम उम्र में 2009 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विजय पताका फहराई और 2009 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजी गईं. चौथी सदस्य न्यूजीलैंड की लीजा हे टू टू हैं, जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और पायलट भी रह चुकी हैं. इसके अलावा टीम में चिली की पर्वतारोही मर्सिया गुटिरेज़, इजरायल की शांति कार्यकर्ता ऑल्फ्रेड हेइर, चीन की इंजीनियर जियाओ हू एवं दक्षिण अफ्रीका की किम स्मिथ भी शामिल हैं.

दुनिया के विभिन्न देशों की उक्त महिलाओं का एकजुट होकर एक बड़े अभियान के लिए निकलना एक खास मायने रखता है. मुद्दा है नदियों और पानी का. उक्त महिलाएं 60 दिनों में 2,525 किलोमीटर की गंगा यात्रा करेंगी. बीते 23 अक्टूबर को उन्होंने गोमुख से अपनी यात्रा बोट द्वारा शुरू की. यह यात्रा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में सूचीबद्ध हिमालयन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के बैनर तले की जा रही



है. उक्त महिलाओं के अलावा टीम में कमांडेंट एसपी आहूजा समेत 11 अन्य लोग भी शामिल हैं. सभी लोग बीते 24 नवंबर को मुंगेर (बिहार) पहुंचे. न कोई तामझाम, न कोई दिखावा. गंगा के किनारे तंबू लगाकर रहना, शाम के समय या रात में सोलर लाइट का इस्तेमाल. स्थितियों को समझना और फिर जन-साधारण को उनसे वाकफ कराना, यह टीम का प्रमुख कार्य है. यात्रा के दौरान टीम आमजन, जनसंगठनों एवं स्कूली बच्चों के साथ संवाद भी करती है और उन्हें संदेश देती है कि यदि अभी नहीं चेंते, तो आने वाले समय में क्या-क्या होने वाला है. टीम गंगा और जल को लेकर एक डाक्युमेंट्री भी तैयार कर रही है.

टीम के सदस्यों ने बताया कि गोमुख से लेकर ऋषिकेश तक तो गंगा की स्थिति ठीक है. हरिद्वार आते-आते वह प्रदूषित होनी शुरू हो जाती है. कानपुर में तो सबसे भयानक स्थिति है, जहां हजारों लीटर गंदा पानी प्रतिदिन गंगा में डाला जा रहा है. सीवरेज सिस्टम एवं ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था बदतर है. प्रदूषण के चलते लोग कैंसर एवं अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. टीम का नेतृत्व कर रहीं ऐन बैनक्रॉफ्ट कहती हैं कि नदियों और जल का मुद्दा किसी एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक है. नदियां एवं जल के संरक्षण

दुनिया के विभिन्न देशों की उक्त महिलाओं का एकजुट होकर एक बड़े अभियान के लिए निकलना एक खास मायने रखता है. मुद्दा है नदियों और पानी का. उक्त महिलाएं 60 दिनों में 2,525 किलोमीटर की गंगा यात्रा करेंगी. बीते 23 अक्टूबर को उन्होंने गोमुख से अपनी यात्रा बोट द्वारा शुरू की. यह यात्रा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में सूचीबद्ध हिमालयन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के बैनर तले की जा रही है.

की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं पर नहीं छोड़ी जा सकती. इसके लिए आम लोगों को जागरूक बनाना होगा. संवाद के क्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मुंगेर प्रमंडल के उपनिदेशक कमलाकांत उपाध्याय ने गंगा में गाद की समस्या के संदर्भ में बातचीत की. उन्होंने गंगा के सवाल पर बिहार सरकार के नज़रिये और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से टीम को वाकफ कराया. मुंगेर नगर निगम की महापौर कुमकुम देवी ने अपने क्षेत्र में गंगा

तट की सफाई की बात कही. ऐन बैनक्रॉफ्ट ने कहा कि नदियों एवं जल का सवाल महिलाओं से जुड़ा है, इसलिए ऐसे अभियानों में महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की ज़रूरत है. गंगा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल जालान ने बताया कि गंगा आरती एवं अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

शुद्ध पेयजल का सवाल बहुत अहम है, लेकिन यह अभी तक सिर्फ नारों तक सीमित है. आज भी देश के अनपिनित परिवारों को शुद्ध पेयजल मयस्सर नहीं है. महिलाओं को इस समस्या से रोजाना दो-चार होना पड़ता है. घर में पानी भरने से लेकर बाहर से पानी ढोने तक की जिम्मेदारी आज भी महिलाओं के कंधों पर है. देश के कई राज्यों में पानी के लिए महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है. पर्वतारोहण से जुड़ी कुष्णा पाटिल कहती हैं कि इन सवालों को समझना होगा और इन्हें वैश्विक मुद्दा बनाना होगा, अन्यथा एक दिन स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि उसका मुकाबला करना असंभव होगा. दिल्ली एवं मुंबई सहित देश के 71 बड़े शहरों में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है. इन शहरों में पानी का एक तिहाई हिस्सा लीकेज और खराब पाइप लाइनों की वजह से व्यर्थ चला जाता है. देश के 97 फीसद लोग शुद्ध पेयजल से वंचित हैं. चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है, जहां जनसंख्या के लिहाज से पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा है. हर साल जिस

तरह वर्षा में कमी आ रही है और देश के कई हिस्से सूखे की चपेट में हैं, उससे यह साबित होता है कि पानी का सवाल आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा.

वैज्ञानिक काफी पहले चेता चुके हैं कि वर्ष 2025 तक दुनिया के दो तिहाई देशों में पानी की किल्लत हो जाएगी, जबकि एशिया और खास तौर पर भारत में 2020 तक ही ऐसा होने की आशंका है. पृथ्वी पर कुल पानी का महज 2.5 फीसद जल ही पीया जल यानी पीने योग्य है. भंडारण एवं संसाधनों की कमी के चलते कुल 18 फीसद वर्षाजल का उपयोग हो पाता है. हाल के वर्षों में भूजल स्तर में गिरावट और वर्षा की कमी के साथ ही आम लोगों की जीवनशैली में भी परिवर्तन आया है. नतीजतन, पानी की खपत और कुप्रबंधन, दोनों में वृद्धि हुई है. धरेलू कार्यों, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की मांग सबसे ज़्यादा है. 2025 तक इस मांग में 40 फीसद बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है. जल संकट से जूझ रहे दुनिया के 20 शहरों में जापान की राजधानी टोक्यो नंबर एक पर है. इस सूची में भारत के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु एवं हैदराबाद आदि शहर भी शामिल हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com





भारत में लगभग साढ़े छः करोड़ से ज्यादा लोग आज ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अगर बात गांवों की की जाये तो गांवों में आज भी पुराने और परम्परागत तरीकों से खाना बनाने का काम प्रतिदिन होता है। गांवों में अभी तक लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं उपलों, कोयलों और केरोसिन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करती हैं। खाना बनाते वक्त लकड़ी, केरोसिन और कोयले से निकलने वाला धुआं रसोई में काम करने वाली महिलाओं के लिए फेफड़ों, आंखों समेत कई जानलेवा बीमारियां लेकर आती है।

धुएं के ज़हर से बचाता है आधुनिक कोयला

किसानों ने आधुनिक कोयला बनाने के साथ-साथ स्टेनलेस स्टील से बने कुकिंग स्टोव का भी निर्माण किया है, जिसमें बिना किसी झंझट और धुएं के स्वादिष्ट खाना तैयार किया जा सकता है।



मानसी बत्रा

feedback@chauthiduniya.com

मनुष्य को जीवन देने वाली हवा को आज चारों ओर फैल रहे प्रदूषण ने इतना प्रदूषित कर दिया है कि सांस लेने के लिए भी वह महफूज नहीं है। बढ़ते हुये कारखाने, सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती हुई गाड़ियों का धुंआ, संयंत्रों में बढ़ती कोयले की खपत, ये सभी मिलकर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। सफलता और विकास को पाने के लिए आज हम जो दूसरी जरूरी बातें भूल चुके हैं, वह है बेहतर स्वास्थ्य। यह बगैर स्वच्छ पर्यावरण के संभव नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में लगभग 13 शहर भारत के ही हैं। प्रदूषण के कारण कई बीमारियां जन्म ले रही हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिये बड़ा खतरा बनती जा रही हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग साढ़े छः करोड़ से ज्यादा लोग आज ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहां हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अगर बात गांवों की की जाये तो गांवों में आज भी पुराने और परम्परागत तरीकों से खाना बनाने का काम प्रतिदिन होता है। गांवों में अभी तक लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं उपलों, कोयलों और केरोसिन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करती हैं। खाना बनाते वक्त लकड़ी, केरोसिन और कोयले से निकलने वाला धुआं रसोई में काम करने वाली महिलाओं के लिए फेफड़ों, आंखों समेत कई जानलेवा बीमारियां लेकर आता है। ग्रामीण महिलाओं को इन बीमारियों से सचेत करने के लिए राजस्थान के मोरारका फाउंडेशन ने आधुनिक तकनीकों के जरिए किसानों के प्रति जागरूकता अभियान की शुरुवात की है। हर साल लगभग 1.6 मिलियन लोग इसके कारण पैदा होने वाले धुएं



और प्रदूषण के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। लगभग 10 लाख बच्चों की हर साल मौत का कारण भी ये धुआं और प्रदूषण ही हैं। मोरारका फाउंडेशन किसानों को रोजगार और बीमारियों से बचाने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाता आ रहा है और इस बार खेतों के बचे कचरे से कोयला बनाने की तकनीक सीखाकर किसानों को मोरारका फाउंडेशन जागरूक कर रहा है। खेतों के बचे कचरे से आधुनिक कोयला तैयार किया जाता है, जो स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिये भी फायदेमंद होता है। आधुनिक कोयला बनाने की आधुनिक तकनीक और नवलगढ़ के किसान बचे हुए कचरे से आधुनिक कोयला बना रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसानों ने

कोयला बनाने की तकनीक

1. किसी भी प्रकार की सूखी पत्तियां, लकड़ी, सूखी घास व खेत का कचरा काम में लिया जा सकता है।
2. फसल काटने के बाद खेत में छोड़े हुए कचरे को इकट्ठा करके जला दिया जाता है और उसे चिमनी से ढक दिया जाता है।
3. चारकोल का भूरा और आटे के बाइंडर (गिला आटे) को मिलाकर कर दिया जाता है।
4. मिक्सर को मशीन में डालकर छोटे-छोटे कोयले के टुकड़े तैयार किए जाते हैं।

आधुनिक कोयला बनाने के साथ-साथ स्टेनलेस स्टील से बने कुकिंग स्टोव का भी निर्माण किया है, जिसमें बिना किसी झंझट और धुएं के स्वादिष्ट खाना तैयार किया जा सकता है। खाना पकने तक महिलाएं अपने अन्य काम निपटा सकती हैं। कुकिंग स्टोव में खाना मात्र 45 मिनट में तैयार हो जाता है। बढ़ते प्रदूषण के चारे में अगर लोगों को जानकारी दी जाए तो प्रदूषण से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। जागरूकता के अभाव में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिसे हम जान नहीं पाते। थोड़ा बहुत बदलाव करके ग्रामीण लोगों के खाना बनाने के कार्य को स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की यह कोशिश अच्छा कदम है। ■

तस्वीरों में यह सप्ताह

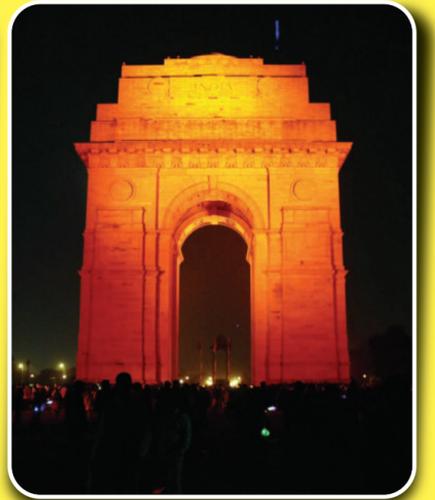
सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय / सुनील मल्होत्रा



● नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उमड़े लोग।



● सुलभ इंटरनेशनल द्वारा आयोजित क्वीन इंडिया मूवमेंट में बच्चों के साथ भाजपा सांसद हेमा मालिनी।



● महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नारंगी रंग में रंगा इंडिया गेट।



● द्वारका (नई दिल्ली) में कार फ्री डे के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।



● इंदिरा गांधी के 98वें जन्मदिवस के मौके पर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी।



● जंतर-मंतर पर आईएसआईएस के मुखिया बगदादी और सपा नेता आजम खान का पुतला फूंकते हुए राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता।

www.kamalmorarka.com



कमल मोरारका

»»

राजनाथ सिंह सही कहते हैं कि पंथ में मतभेद हो सकते हैं,

लेकिन धर्म एक है, लेकिन,

वह थह भूल जाते हैं कि

हिंदुइज्म सभी पंथों को

स्वीकार करता है, तो फिर

मतभेद का सवाल कहां से

उता है? फिर लोग ऐसा क्यों

कहते हैं कि मुसलमानों को

पाकिस्तान चले जाना

चाहिए? वे क्यों कहते हैं कि

यह मुसलमान है, वह ईसाई

है? वे सब वैतुकी बातें हैं, इसे

जितनी जल्दी समझेंगे, संवाद

को पुनर्स्थापित कर सकेंगे,

संविधान पर जो बहस शुरु

हुई है, उससे कोई नुकसान

नहीं है, संविधान के दायरे में

रहने के व्यवाहारिक रास्ते क्या

हैं? आग्निस्कार, इस देश में

हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई

संविधान के साथ रहते

हैं, उनमें रोजाना कोई तनाव

नहीं होता, हिंसा नहीं होती,

तो फिर आप यह सब क्यों

पैदा करता चाहते हैं?

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

यह देश हमेशा से धर्मनिरपेक्ष है

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

सांकेतिक भाव तो बहुत अच्छा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. बीआर अंबेडकर को सम्मान देना भी अच्छा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम संविधान में नहित मूल्यों का अनुकरण कर रहे हैं? मुझे यह कहने में दु:ख हो रहा है कि संविधान में नहित मूल्यों की कौन करे, संविधान में जो बातें कही गई हैं, उनकी पर्याप्त का अक्सर उल्लंघन होता रहता है. संविधान में यह स्पष्ट है कि सेकुलरिज्म शब्द 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया था. मैं सेकुलरिज्म शब्द का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ, लेकिन संविधान सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किए बिना नैतिक निंदेक सिद्धांतों में साफ़ तौर पर यह कहना है कि भारत के सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल और लिंग भेद के बिना एक समान अधिकार है. राजनाथ सिंह शायद सही कहते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द का सबसे अधिक दुपयोग हुआ है. लेकिन, वह एक बात भूल जाते हैं कि इस शब्द का सबसे अधिक दुपयोग तो उनकी पार्टी, उनके सहयोगी एवं समर्थक कर रहे हैं. जब भी उन्हें किसी शब्द के खिलाफ़ कोई बात

बुनाव ख़त्म हो गया है, अब शांत हो जाइए. जब 2019

आएगा, तब आप अपनी कोई रणनीति बना लीजिएगा.

लेकिन, धीमा ज़हर बोमे से हमारा मला नहीं होगा. इस

तरह के व्यपहार से, सबका साथ—सबका विकास का जो

रास्ता आपने चुना है, वह हानित नहीं हो सकेगा.

दरअसल, इस देश में जो नहीं है, वहां आपना किरदार अदा

कर रहा है. सिर्फ़ कॉन्सिपेट सेक्टर की तरफ़ देखने से भी

मला नहीं होगा. कृपि के बारे में आप क्या सोच रहे हैं?

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

संपादकीय



संतोष भारतीय

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

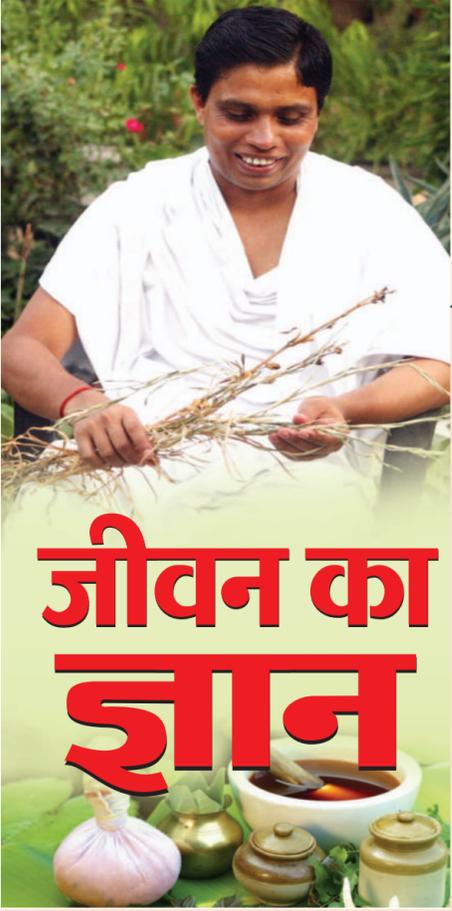
»»

»»

»»

»»

»»



जीवन का ज्ञान

भा रतवर्ष में अनार के वृक्ष सर्वत्र पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड की पहाड़ियों पर तथा ईरान तथा अफगानिस्तान में यह स्वयंजात होता है। स्वाद-भेद के अनुसार अनार की तीन किस्में पाई जाती हैं। देशी अनार खट्टे-मीठे होते हैं। काबुल और कंधार के अनार मीठे होते हैं। अनार का केवल फल ही नहीं, अपितु वृक्ष का सर्वांग ही औषधीय होता है।

बाह्य-स्वरूप

अनार का लगभग 8 मी तक ऊंचा, पर्णपाती, शाखा-प्रशाखाओं से युक्त झाड़ीनुमा, मध्यम आकार का वृक्ष होता है। इसका काण्ड चिकना तथा छाल धूसर वर्ण की, पतली होती है।

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

1. अनार त्रिदोषहर, तृप्तिकारक, पाचक, लघु, किंचित कसैला, मलावरोधक, स्निग्ध, मेघ्य, बलकारक, ग्राही, दीपन तथा तृष्णा, दाह, ज्वर, हृदय रोग, मुख दुर्गन्ध, कंठरोग और मुख रोगनाशक है।
2. रस भेद से अनार के फल तीन प्रकार के होते हैं- (1) मधुर रस युक्त, (2) अम्ल रस युक्त (3) मधुर-अम्ल रस युक्त
3. खट्टा अनार- रूक्ष, रक्त पित्तकारक तथा वात-कफशामक होता है।
4. खट्टा मीठा अनार- दीपन, रुचिकारक, वात-पित्तशामक और पाचन में हलका है। अनारदाना (कच्चा सुखाया हुआ अनार) रुचिकारक हृदय को प्रिय और वातानुलोमक होता है।
5. काण्ड की छाल- कृमिनाशक, मलरोधक, रक्तान्तरित और कास नाशक है।
6. कच्चा फल- पाचक, पौष्टिक, क्षुधा-वर्धक, पित्तकारक और वमन को रोकने वाला है।
7. पुष्प- नासिका से प्रवृत्त स्राव को दूर करता है। अनार की जड़ कृमिहर है। फीता कृमियों को नष्ट करने की यह उपयुक्त औषधि है।
8. इसका ऐल्कोहॉलिकसरा शक्तिशाली मूत्राशमरीरोधी एवं अनांक्सीकारक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है।

शिरःशूल-अनार के छाया शुष्क आधा किलो पत्तों में आधा किलो सूखा धनिया मिलाकर महीन चूर्ण कर लें। इसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा मिलाकर गाय के घी में भून लें। ठंडा होने पर 1 किलो खांड मिला लें। प्रातः और सायं गर्म दूध के साथ 50 ग्राम तक सेवन करने से सिर दर्द और सिर चकराना दूर होता है।



9. इसका सार विविध प्रतिजैविक-प्रतिरोधी हेलिकोबैक्टर पायलोरी के प्रति-जीवाणुरोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है।
10. इसका जलीय सार इस्चैरिशिया कोलाई के प्रति निरोधात्मक प्रदर्शित करता है।

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि शिरो रोगः

1. खालित्य-पलित-अनार के ताजे हरे पत्तों के रस में 100 ग्राम अनार के पत्तों का कलक और आधा ली सरसों का तैल मिलाकर, तैल पका कर लगाने से सिर का गंजापन दूर होता है तथा बालों का झड़ना रुकता है।
2. अनार के तैल की मालिश करने से चेहरे की कील, झाँड़ और काले धब्बे नष्ट होते हैं।
3. शिरःशूल- अनार के छाया शुष्क आधा किलो पत्तों में आधा किलो सूखा धनिया मिलाकर महीन चूर्ण कर लें। इसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा मिलाकर, गाय के घी में भून लें। ठंडा होने पर 1 किलो खांड मिला लें। प्रातः और सायं गर्म दूध के साथ 50 ग्राम तक सेवन करने से सिर दर्द और सिर चकराना दूर होता है।
4. अनार की छाल को घिसकर कपाल पर लेप करें। इससे सिर के दर्द तथा आधा सीसी में सद्यः लाभ होता है।

नेत्र रोगः

1. आंख की फूली (मोतियाबिन्द)- अनार वृक्ष छाल को पके हुए अनार फल के रस में घिसकर फिर इसमें 1 या लाल गुंजा का छिलका निकाल कर घिसें। इसे फूली पर दिन में 3 बार लगाने से लाभ होता है।
2. नेत्रविकार- अनार के 5-6 पत्रों को पीना में पीसकर दिन में 2 बार लेप करने तथा पत्तों को पानी में भिगोकर पोटली बनाकर आंखों पर फेरने से नेत्र वेदना में लाभ होता है।
3. अनार के 8-10 ताजे पत्तों का रस खरल में डालकर शुष्क हो जाने पर कपड़े से छानकर रख दें। प्रातः और सायं सलाई द्वारा नेत्रों में लगाएं। इससे खुजली, नेत्रस्राव आदि रोग दूर होते हैं।

नासा रोगः

1. नकसीर- अनार के फूलों का 1-2 बूंद रस नाक में टपकाने से या सुघाने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। यह नकसीर की अति उत्तम औषधि है।
2. अनार के छिलके को छुहारे के पानी के साथ पीसकर लेप करने से सूजन में तथा इसके शुष्क महीन चूर्ण का नस्य लेने से नकसीर में लाभ होता है।

अनार

अनार के छाया शुष्क पत्तों के महीन चूर्ण में शहद या गुड़ मिलाकर झड़बेरी जैसी गोलियां (0.1-1 ग्राम) बनाकर छाया शुष्क कर लें। इन गोलियों को मुंह में रख कर चूसने से लाभ होता है।



में लाभ होता है।

3. अनार के पत्रों का काढ़ा (10-30 मिली) या पत्र-स्वरस (10 मिली) पिलाने से तथा पीसकर मस्तक पर लेप करने से नकसीर में लाभ होता है।

कर्ण रोगः

1. कर्ण विकार- अनार के ताजे पत्तों का रस 100 मिली, 400 मिली गोमूत्र और 100 मिली तिल तैल को मंद आंच पर पकाएं। तैल मात्र शेष रहने पर छानकर रख लें। इसकी कुछ बूंदें थोड़ा गर्म कर प्रातः और सायं कान में डालने से कर्ण वेदना, कर्णनाद और बधिरता में लाभ होता है।

मुख रोगः

1. दंतशूल- अनार तथा गुलाब के शुष्कफल, दोनों को पीसकर मंजन करने से मसूढ़ों से पानी आना बंद हो जाता है। केवल अनार की कलियों के चूर्ण मंजन करने से मसूढ़ों से खून आना बंद हो जाता है।
2. मुख और मसूढ़ों के विकार में अनार की मूलत्वक के काढ़े से कुल्ला करने से लाभ होता है।
3. मीठे अनार के छाया शुष्क 8-10 पत्तों के चूर्ण का मंजन करने से दांतों का हिलना, मसूढ़ों से खून और पीव का आना बंद हो जाता है तथा सूजन में फायदा पहुंचता है।
4. मुंह के छाले- अनार के 25 ग्राम पत्तों को 400 मिली पानी में उबालकर चतुर्थांश शेष क्वाथ से कुल्ला करने से मुंह के छाले आदि मुख रोग दूर होते हैं।
5. दाड़िम छाल का चूर्ण बनाकर मुंह में रगड़ने से या धमसे के जल का क्वाथ कर कुल्ला करने से मुखपाक ठीक हो जाती है।
6. 10 ग्राम अनार के पत्तों को 400 मिली पानी में उबालकर चतुर्थांश शेष क्वाथ बनाकर कुल्ला करने से मुख के छालों में लाभ होता है।

कण्ठ रोगः

1. कंठ-विकार- अनार के ताजे पत्रों के 1 ली रस में मिश्री मिलाकर शर्बत बना लें। 20-20 मिली दिन में 2-3 बार पीने से आवाज का भारीपन, खांसी, नजला तथा जुकाम दूर होता है।
2. अनार के छाया शुष्क पत्तों के महीन चूर्ण में शहद या गुड़ मिलाकर झड़बेरी जैसी गोलियां (0.1-1 ग्राम) बनाकर छाया शुष्क कर लें। इन गोलियों को मुंह में रख कर चूसने से लाभ होता है।

जारी...

आचार्य शतकृष्ण



अवैध व्यवसायिक गतिविधियां रोकने के लिए आरटीआई

आगर आप अपने क्षेत्र में व्यवसायिकरण के खिलाफ हैं, अगर आपको इससे संबंधित कोई सूचना चाहिए, लेकिन वह मिल नहीं पा रही है, अगर आपको किसी सूचना की दारकार हो, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से इससे सम्बंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस अंक में हम एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं। चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है। आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया.....क्षेत्र में व्यवसायिकरण से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त क्षेत्र में उन सभी भवनों की सूची प्रदान करें, जिनका उपयोग कानून का उल्लंघन करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
2. ऐसे प्रत्येक मामले में किस तरह के कानूनों का और किस प्रकार उल्लंघन हो रहा है? इसका विवरण दें। आपके विभाग को इन उल्लंघनों के बारे में सबसे पहले कब जानकारी मिली?



3. इन उल्लंघनों की जानकारी मिलने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इसका पूरा विवरण दें।

4. कृपया उन नियमों, कानूनों और सरकारी आदेशों की जानकारी दें, जिनका आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण उल्लंघन हुआ है।
5. आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में निर्धारित सजा अथवा नियम के मुताबिक की जाने वाली कार्रवाई का विवरण दें।
6. ऐसे प्रत्येक मामले में आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रत्येक घटना का अलग-अलग पूरा विवरण दें। यदि किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्यों?
7. मैं ऐसे प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई से सम्बंधित सभी दस्तावेजों व फाइलों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे दिन, समय तथा स्थान के बारे में सूचित करें, जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूँ।
8. उन अधिकारियों के नाम, पद और संपर्क का विवरण बताएं, जो इन व्यवसायिकरण के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।
9. क्या ये अधिकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं करने के कारण भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13(घ) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217 के उल्लंघन के दोषी हैं?

10. इन अधिकारियों के खिलाफ अब आगे कब और क्या कार्रवाई की जाएगी?
11. उपरोक्त व्यवसायिकरण कब तक पूर्ण रूप से रोक अथवा हटा दिए जाएंगे?
12. उपरोक्त क्षेत्र से दिनांक.....से.....के दौरान आपके विभाग को व्यवसायिकरण से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण दें। मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा /रही हूँ। या मैं वी.पी.एल. कार्ड धारी हूँ, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूँ। मेरा वी.पी.एल. कार्ड नं.....है। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से

सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतावें।

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें। हम उसे प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है-

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर- 11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com





आसियान सम्मेलन के दौरान एक बेहतरीन पहल आसियान इकोनोमिक कम्युनिटी (ईसी) के रूप में सामने आई. मलेशिया के प्रधानमंत्री नाजिब रज़ाक ने आसियान इकोनोमिक कम्युनिटी (ईसी) के गठन की औपचारिक घोषणा की. कुआलालंपुर में आयोजित दसवें आसियान सम्मेलन में यह घोषणा की गई. ईसी अगले वर्ष प्रभाव में आएगा और इसका मकसद आसियान के दस सदस्य देशों के बीच सहयोग को अगले दौर में ले जाना है. इसके तहत आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा, जिससे आगे चलकर श्रमिकों के बेरोकटोक एक-दूसरे देश में जाने का मार्ग प्रशस्त होगा.

आसियान से उठी आतंकवाद के खिलाफ आवाज़



चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद अब किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया है. उन्होंने कहा कि अक्सर इस मंच पर हम सोचते हैं कि आतंकवाद हमारे आसपास की समस्या है, लेकिन पेरिस, अंकारा, बेरूत, माली और रूसी विमान पर हुए हमलों से स्पष्ट है कि आतंकवाद की परछाई ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें नए संकल्प और नई नीति के साथ आगे बढ़ना होगा. किसी भी देश को आतंकवाद का इस्तेमाल या समर्थन नहीं करना चाहिए. आतंकी गुटों के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए. उनके लिए कोई पनाहगाह नहीं होनी चाहिए. उन्हें कहीं से मदद नहीं मिलनी चाहिए. उनकी पहुंच हथियारों तक नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा, आसियान सम्मेलन के दौरान एक बेहतरीन पहल आसियान इकोनोमिक कम्युनिटी (ईसी) के रूप में सामने आई. मलेशिया के प्रधानमंत्री नाजिब रज़ाक ने ईसी के गठन की औपचारिक घोषणा की. कुआलालंपुर में आयोजित दसवें आसियान सम्मेलन में यह घोषणा की गई. ईसी अगले वर्ष प्रभाव में आएगा और इसका मकसद आसियान के दस सदस्य देशों के बीच सहयोग को अगले दौर में ले जाना है. इसके तहत आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा, जिससे आगे चलकर श्रमिकों के बेरोकटोक एक-दूसरे देश में जाने का मार्ग प्रशस्त होगा.

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो अबे से भी अलग से मुलाकात की और जापान को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. अबे ने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंधों की तुलना में भारत-जापान संबंधों में सबसे अधिक संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि भारत-जापान के बीच विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी का विस्तार हो.

इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो अबे से भी अलग से मुलाकात की और जापान को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. अबे ने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंधों की तुलना में भारत-जापान संबंधों में सबसे अधिक संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि भारत-जापान के बीच विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी का विस्तार हो.

आसियान सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे. उन्होंने सिंगापुर में भारतीय लोगों के बीच भाषण भी दिया. उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ एक विश्वास से देख रहा है. इस भाषण की खास बातें ये रहीं कि इसमें कहा गया कि भारत विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ेगा. विदेशी दौर के संबंध में मोदी का यह कहना काफी अहम रहा कि इसलिए विश्व के साथ हमारे संबंध जीवंत होने चाहिए. औपचारिक संबंधों से कुछ नहीं मिलता है. चार देशों से संबंध रखकर कोई भी देश चल नहीं सकता है. आज सभी देशों से संबंध होने चाहिए, फिर वह छोटा देश ही क्यों न हो. दोनों देशों के बीच दस समझौते भी हुए. भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय एग्रीमेंट्स के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और को-ऑपरेशन पर ज्वाइंट डिक्लरेशन जारी किया. दोनों देशों ने डिफेंस, साइबर सिक््योरिटी और सिविलियन मामलों में एग्रीमेंट किए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

लाशों की पलश करने वाला दरिंददा डेनिस



डेनिस एंड्रयू निल्सन का जन्म 23 नवंबर, 1945 को फ्रेजरबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ. कौन कह सकता था कि मासूम सा दिखने वाला डेनिस आगे चलकर मुसवेल् हिल खूनी और काइनडली खूनी के नाम से कुख्यात होगा. एक ऐसा ब्रिटिश सीरियल किलर, जिसने लंदन में रहकर सन् 1978 से लेकर सन् 1983 के दौरान 15 नौजवानों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया. डेनिस का बचपन शुरू से ही आम बच्चों के बचपन की तरह नहीं गुजरा. डेनिस की मां स्कॉटलैंड और पिता नॉर्वे के थे. पिता के शराब पीने की आदतों की वजह से डेनिस के माता-पिता का तलाक हो गया. जब डेनिस महज चार साल का था, तब उसकी मां ने किसी दूसरे से शादी कर ली और डेनिस को उसके नाना-नानी के पास रहने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कुछ साल बाद डेनिस अपनी मां के साथ ही रहने लगा. डेनिस को बचपन से ही अपने दादा से बहुत लगाव था, लेकिन दादा की मौत के बाद और बार-बार मां और सौतेले पिता द्वारा देह ही अशुद्धियों पर उपदेश सुनने से डेनिस की मानसिकता भयानक रूप लेने लगी. इसी भयानक दरिंदगी के चलते डेनिस छात्राओं और बेघर आदमियों से मिलता और किसी बहाने उन्हें बहला-फुसलाकर अपने घर लाता और रात में उनके साथ दुष्कर्म करके उनका बेरहमी से गला घोट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता. डेनिस की दरिंदगी इतनी बढ़ गई थी कि वह शवों को कसाई की तरह काटकर अपने घर के बगीचे में जला देता. सन् 1981 में डेनिस ने अपना घर निचली मंजिल से ऊपर के प्लेट में शिफ्ट कर लिया. इस दौरान हत्याओं का दौर चलता रहा, लेकिन डेनिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि शवों को कहा ठिकाना लगाया जाए. इस बीच घर पर पड़े शवों की बदबू पड़ोसियों को आने लगी थी. डेनिस को डर था कि कहीं उसका असली चेहरा लोगों के सामने न आ जाए और इसी डर से वह लाशों के छोटे-छोटे टुकड़े कर शौचालय के कंभों में पलश करके लाशों को ठिकाने लगाने लगा. कुछ महीने डेनिस का आतंक यू ही चलता रहा, लेकिन एक दिन सीवेज पाइप ब्लॉक हो जाने की वजह से सिवेज कर्मचारियों को बुलाया गया. जब सिवेज पाइप की सफाई की गई तो भारी मात्रा में मांस के टुकड़े मिले. संदेह होने पर सिवेज कर्मचारियों ने पुलिस को बुलाया. छानबीन के चलते सन् 1983 में कई लोगों की हत्याओं के आरोप में डेनिस को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद डेनिस का खूंखार चेहरा लोगों के सामने आया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान डेनिस के घर की तलाशी ली गई और तलाशी में डेनिस की अलमारी से तीन आदमियों के सिर मिले. 13 लाशें भी डेनिस के पुराने घर से मिलीं. डेनिस पर 15 लोगों की हत्याओं के आरोप साबित होने के बाद 4 नवंबर, 1983 को उसे उग्रकैद की सजा सुना दी गई. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त खबरें

ओबामा ने रूस से मांगी मदद



स्लामिक स्टेट (आईएस) का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है. आईएस के खात्मे के लिए उसने अपने विरोधी देश रूस से मदद मांगी है. 10वें ईस्ट एशिया समिट के दौरान एशियन लीडर्स से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यूएस और उसके साथी देश आईएस के खिलाफ नरमी नहीं बरतेंगे. उन्होंने कहा कि हम आतंकियों के लीडर्स को टारगेट कर गुप की फाइनेंसिंग सोर्स को खत्म करेंगे. हालांकि, ओबामा ने यह भी कहा है कि मास्को का पूरा फोकस सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद को सपोर्ट करने पर है. उन्होंने रूस से अपनी नीति में बदलाव करते हुए असद को सपोर्ट न करने की भी अपील की है. ओबामा ने कहा कि हम आईएस को खत्म कर देंगे और उसके कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे. उनके लीडर्स को टारगेट कर उनके नेटवर्क और सप्लाय लाइन को नेस्तनाबूत कर देंगे. ओबामा ने कहा कि अगर रूस आईएस के खिलाफ कार्रवाई में आगे आएगा, तब यह काफी मददगार साबित होगा. हालांकि, ओबामा ने उम्मीद जताई है कि मास्को असद को हटाने लिए राजी हो जाएगा. सीएनएन, रॉयटर्स और गार्जियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरिया का सिविल वॉर अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है. दरअसल, दुनिया के दो सुपरपावर अमेरिका और रूस सीरिया के बहाने पाँचवीं वॉर में लगे हैं. अमेरिका और कई पश्चिमी देश सीरिया के प्रेसिडेंट के विरोधी हैं. वे उन्हें सत्ता से बेदखल कर सरकार में अपने मोहरे बैठाना चाहते हैं. अमेरिका पर आरोप है कि वह असद के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देकर मदद करता है. ऐसे में, रूस अगर असद की मदद करता है तो अमेरिका के साथ उसके रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं. अब यह तो वक्त ही बताएगा कि आईएस के खात्मे के लिए रूस अमेरिका की मदद करेगा या नहीं. ■

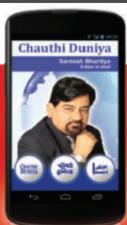
आखिर पाकिस्तान बेचैन क्यों है



सन् 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों के लिए बांग्लादेश में दो शीर्ष विपक्षी नेताओं को फांसी दिए जाने पर पाकिस्तान ने गहरी चिंता और आक्रोश प्रकट किया है. हाल ही में विदेश विभाग ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेताओं सलाउद्दीन कादिर चौधरी और अली अहसान मुजाहिद को फांसी दिए जाने पर एक बयान भी जारी किया है, जिनकी दया याचिका राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने अस्वीकार कर दी है. विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हम दुर्भाग्यपूर्ण फांसी पर गहरी चिंता और आक्रोश जताते हैं. फिलहाल तो इस घटनाक्रम को लेकर

तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध

रूस तुर्की पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है. तुर्की ने रूसी विमान गिरा दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है. टीवी पर दिए गए एक बयान में रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवदेव ने कहा है कि व्यापार, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए जाएंगे और साझा निवेश की योजनाओं को भी बंद किया जा सकता है. मेदवदेव ने कहा कि रूस में तुर्की के आर्थिक हितों को सीमित करना या रोक लगाना और सामानों की सप्लाय रोकने जैसे कदम उठाए जाएंगे, जिसमें खाद्य सामग्री भी शामिल है. उन्होंने कहा कि निवेश योजनाओं के साथ भी इसी तरह के नियम लागू होंगे. इन पर तुर्की के साथ सहयोग उसके साथ उच्च स्तर के आधार पर तय होगा. रूस व्यापार के क्षेत्र में तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी है, तो वहीं तुर्की रूसी पर्यटकों में सबसे लोकप्रिय विदेशी पर्यटक स्थल है. रूस का आरोप है कि तुर्की ने बिना किसी चेतावनी के रूसी विमान को गिरा दिया. दूसरी तरफ तुर्की का दावा है कि रूसी विमान ने चेतावनी के बावजूद तुर्की की वायु सीमा का उल्लंघन किया. तुर्की ने माफी मांगने की रूस की मांग को खारिज कर दिया है. ■





आनंद थोड़ी देर में फिर खाली लौट आया। पानी अब भी गंदा था पर बुद्ध ने उसे इस बार भी वापस लौटा दिया। कुछ देर बार जब तीसरी बार आनंद झरने पर पहुंचा, तो देखकर चकित हो गया। झरना अब बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया था, कीचड़ बैठ गया था। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि यही स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की दौड़-भाग मन को भी विक्षुब्ध कर देती है, मथ देती है।

साई वंदना

श्रद्धा और सबूरी



धर्म

बैजनाथ मंदिर

भक्तों के संकट हरते हैं शिव

भूव्य प्राचीन शिव मंदिर बैजनाथ हिमाचल प्रदेश की हिमाच्छादित धौलाधर पर्वत श्रृंखला के प्रांगण में स्थित है। यह मंदिर सन् 1204 में दो क्षेत्रीय व्यापारियों अहक और मनुक द्वारा बनवाया गया था। माघ कृष्ण चतुर्दशी को यहां विशाल मेला लगता है जिसे तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। बैजनाथ मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण ने हिमाचल के कैलाश पर्वत पर शिवजी के निमित्त तपस्या की। कोई फल न मिलने पर उसने घोर तपस्या प्रारंभ की। अंत में उसने अपना एक एक सिर काटकर हवनकुंड में आहुति देकर शिव को समर्पित करना शुरू किया। दसवां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिव जी ने प्रसन्न हो प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया। उसके सभी सिरों को पुनर्स्थापित कर शिव जी ने रावण को घर मागने को कहा। रावण ने शिवजी से कहा मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। आप दो भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे अत्यंत बलशाली बना दें। शिवजी ने तथ्यास्तु कहा और लुप्त हो गए। शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप दो चिन्ह रावण को देने से पहले कहा इन्हें जमीन पर मत रखना। अब रावण लंका को चला और रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र (बैजनाथ क्षेत्र) में पहुंचा, तो रावण को लघुशंका लगी। उसने बैजू नाम के गवाले को सब बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिया और शंका निवारण के लिए चला गया। शिवजी की माया के कारण बैजू शिवलिंग के वजन को ज्यादा देर तक



मंदिर के प्रांगण में कुछ छोटे मंदिर हैं और नंदी बैल की मूर्ति है। नंदी के कान में भक्त मंत्रत मांगते हैं। बैजनाथ शिव मंदिर दूर-दूर से आने वाले लोगों की धार्मिक आस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां पर भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं। तभी तो भक्त क्या देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए शिव की शरण में जाते हैं। ■

शांति और धीरज

महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ



कहीं जा रहे थे। वन में काफी चलने के बाद दोपहर में एक वृक्ष तले विश्राम को रुके और उन्हें प्यास लगी। आनंद पास स्थित झरने पर पानी लेने गया, लेकिन झरने से अभी-अभी कुछ पशु दौड़कर निकले थे, जिससे उसका पानी गंदा हो गया था। पशुओं की भाग-दौड़ से झरने का पानी कीचड़ ही कीचड़ और सड़े पत्ते बाहर उभरकर आ गए थे। गंदा पानी देख आनंद पानी बिना लिए लौट आया। उसने बुद्ध से कहा कि झरने का पानी निर्मल नहीं है, मैं पीछे लौटकर नदी से पानी ले आता हूँ। लेकिन नदी बहुत दूर थी तो बुद्ध ने उसे झरने का पानी ही लाने को वापस लौटा दिया। आनंद थोड़ी देर में फिर खाली लौट आया। पानी अब भी गंदा था पर बुद्ध ने उसे इस बार भी वापस लौटा दिया। कुछ देर बार जब तीसरी बार आनंद झरने पर पहुंचा, तो देखकर चकित हो गया। झरना अब बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया था, कीचड़

बैठ गया था। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि यही स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की दौड़-भाग मन को भी विक्षुब्ध कर देती है, मथ देती है। पर कोई यदि शांति और धीरज से उसे बैठा देखता है, तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है और सहज निर्मलता का आगमन हो जाता है। ■

feedback@chauthiduniya.com



डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

सबूरी क्या है?

अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों को अविचलित भाव से ग्रहण करने को ही सबूरी कहते हैं। संस्कार हमारे भीतर जड़ जमाए हुए हैं और इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो हमारे आनुवंशिकी कूट में चली जाती हैं। ये संस्कार आसानी से खत्म नहीं होते हैं। जब कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो इन संस्कारों को और मजबूत करते रहते हैं। इन संस्कारों की जड़ों को काटने का उपाय है-सकारात्मक विचारों को अपनाना। सकारात्मक विचार की तरह नकारात्मक विचार फलते-फूलते रहते हैं। किसी व्यक्ति को पहले ही अगर हम पूर्वाग्रह के साथ नहीं देखकर सामान्य रूप से देखेंगे तो धीरे-धीरे हम पाएंगे कि वह उतना बुरा नहीं है जितना कि हम उसे समझ रहे हैं। इस प्रकार सकारात्मक सोच के साथ प्रतिक्रिया-रहित होकर धीरे-धीरे संस्कारों को काटना ही सबूरी कहा जा सकता है।

सबूरी को मन में कैसे बसाए रखें?

सबूरी रखना कठिन है। फिर भी अपने जीवनकाल में हर इंसान कभी न कभी सबूरी अवश्य रखता है। प्रश्न तो सबूरी के स्तर का है। सबूरी की शक्ति को स्वयं ही बढ़ाना पड़ता है, जिससे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इंसान की सहनशीलता बढ़ सके। जब इंसान का अहंकार घटता है, तो सबूरी बढ़ती है, क्योंकि इंसान जीवन के हर पहलू को अहंकार से जोड़ लेता है और इसलिए अधीर हो जाता है। इंसान जो कुछ भी कर रहा है, उसका कारक नहीं है और न ही वह उसके अंतिम परिणाम को नियंत्रित कर सकता है। सब कुछ किसी ईश्वरीय शक्ति, किसी सद्गुरु द्वारा संचालित है, इसका बोध होने पर इंसान कठिन क्षणों में प्रतिक्रियात्मक न होकर धीरे-धीरे सहनशील बनता जाएगा। सहनशीलता बढ़ाने के लिए सदैव गुरु के वचन याद रखने चाहिए तथा कठिनाई के क्षणों में गुरु को याद करना चाहिए।

श्रद्धा की ज्योति आत्मा में कैसे जगाए रखें?

श्रद्धा की ज्योति सदैव आत्मा में प्रज्वलित रहती है, लेकिन उस पर माया का परदा पड़ा रहता है। ज्योति तो प्रज्वलित है ही, प्रश्न उठता है- परदा हटाने का। परदा हटाने के लिए मन को गुरु के प्रति केंद्रित करें। आत्मा गुरु के प्रति समर्पित हो तो हर समय गुरु के विषय में ही सोचेगी और सदैव ही हर कर्म में गुरु की महानता, विशालता एवं कृपा का अनुभव होगा। इसी अनुभव के सहारे धीरे-धीरे स्वयं ही माया का परदा हटता जाएगा और श्रद्धा की ज्योति अवश्य प्रज्वलित होगी।

विश्वास और तार्किक बुद्धि

अध्यात्म में प्रायः दृढ़ निष्ठा या विश्वास एवं तार्किक बुद्धि की अलग-अलग दिशाएं निर्धारित की गई हैं। आपकी इस संबंध में क्या मान्यता है?

रीजनिंग का मूल अर्थ तर्क, युक्ति या विचारणा मात्र नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ-किसी भी घटना या स्थिति के कारण को समंजित रूप में समझने का प्रयत्न करना। अर्थात् हमारे भीतर, आस-पास या व्यापक रूप में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, इसे तत्त्वतः जानने का प्रयत्न करना। मेरी दृष्टि में इसी समझ का चरम रूप दृढ़-निष्ठा या विश्वास है। दृढ़ निष्ठा-भाव या विश्वास इस समझ के बिना कायम नहीं रह सकता और बिना दृढ़ निष्ठा या विश्वास के यह समझ नहीं रह सकती। अतः ये दोनों

श्रद्धा की ज्योति सदैव आत्मा में प्रज्वलित रहती है, लेकिन उस पर माया का परदा पड़ा रहता है। ज्योति तो प्रज्वलित है ही, प्रश्न उठता है-परदा हटाने का। परदा हटाने के लिए मन को गुरु के प्रति केंद्रित करें। आत्मा गुरु के प्रति समर्पित हो तो हर समय गुरु के विषय में ही सोचेगी और सदैव ही हर कर्म में गुरु की महानता, विशालता एवं कृपा का अनुभव होगा। इसी अनुभव के सहारे धीरे-धीरे स्वयं ही माया का परदा हटता जाएगा और श्रद्धा की ज्योति अवश्य प्रज्वलित होगी।

वस्तुतः एक-दूसरे पर आश्रित हैं।

हमारा विश्वास एक हवा का झोंका आने पर अविश्वास में बदल जाता है, इसको हम कैसे रोक पाएंगे?

गुरु के प्रति आस्था हर परिस्थिति में बनाए रखना ही एक मात्र मार्ग है उन लोगों के लिए जो उनके समीप आना चाहते हैं। पर कुछ लोग जो सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा से सद्गुरु के पास आते हैं या इस आशा को मन में रखकर भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, कभी न कभी अपनी इच्छा-पूर्ति न होने पर या अपने कर्मफल भोगने के समय विश्वास खो देते हैं। किसी भी अवतार या सद्गुरु के समय में हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी नहीं हुई। सद्गुरु उन इच्छाओं को कभी पूर्ण नहीं करते, जो उन्हें ईश्वर के समीप लाने के लिए बाधक होंगी। इस इच्छा-पूर्ति न करने के पीछे उनका ही हाथ रहता है। इसलिए जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में बाबा को देख सकता है, वही बाबा का असली भक्त होगा। ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं। मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े। साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई। आप साई को क्यों पूजते हैं? कैसे बने आप साई भक्त। साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें।

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com



पाठकों की दुनिया

भाजपा को छवि सुधारने की जरूरत

आलेख-बिहार के नतीजों का केंद्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा (23 नवंबर-29 नवंबर, 2015) पढ़ा। बेहद प्रभावित किया। कमल मोरारका से मैं सहमत हूँ कि महागठबंधन ने भाजपा को न केवल हराया, बल्कि बुरी तरह से हराया। दोनों पक्षों में सीटों का एक बड़ा अंतर है। लेकिन यह जरूर है कि केंद्र पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार के नतीजों से भाजपा पर असर पड़ेगा जो हम देख भी रहे हैं। बिहार चुनाव में भाजपा की हार के बाद से ही उसके वरिष्ठ नेता केंद्रीय नेतृत्व पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अंसतोष का बिगुल बजाते हुए कहा कि एक साल में पार्टी शक्तिहीन हुई है। इससे भी मैं सहमत हूँ कि यही समय है जब भाजपा को अपने पर लगे आरोपों की पड़ताल करनी चाहिए और साथ ही नेताओं के बड़बोलेंपन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं न कहीं भाजपा की छवि खराब हो रही है।

-निशांत चतुर्वेदी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

यह देश का अपमान है

आलेख-साहित्यिक असहिष्णुता पर हो विचार (23 नवंबर-29 नवंबर, 2015) पढ़ा। काफी विचारोत्तेजक है। इस लेख में अनंत विजय ने लिखा है कि आज जिस तरह से असहिष्णुता को मुद्दा बनाकर लेखक अपने राजनीतिक आकाओं के हाथ के मोहरे बन रहे हैं उससे बेहतर होता कि वो अपनी लेखनी से सत्य की प्रतिभा गढ़ते और विरोध के मुंह में जीभ धर देते। अनंत विजय की इस बात से मैं शत-प्रतिशत सहमत हूँ। साहित्यकारों को लगता है कि देश में असहिष्णुता फैल रही है, तो वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष से मिलते और इस मुद्दे पर एक साथ बैठकर विचार करते। अपनी कलम की ताकत से इसका विरोध दर्ज कराते, लेकिन साहित्यकारों ने पुरस्कार लौटाना ही सही समझा। उन्होंने बिना साहित्य अकादमी को सूचित किए अपने सम्मान लौटा दिए। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक हित जुड़े हैं या फिर कुछ और। मुझे लगता है कि अपने पुरस्कार लौटा देना किसी समस्या का हल नहीं है,

बल्कि यह देश का अपमान है, क्योंकि साहित्य पुरस्कार देश देता है न की कोई सरकार।

-घनश्याम चौरसिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.

मुख्यमंत्री की तानाशाही

आलेख-मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर लगा देशद्रोह (23 नवंबर-29 नवंबर, 2015) पढ़ा। काफी प्रभावित किया। चौथी दुनिया में प्रकाशित खबर पढ़कर यह पता चला कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की आलोचना करने और सरकार के शराब नीति के विरोध में दलित गायक कोवचन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। यह सरकार की तानाशाही है और लोकतंत्र का अपमान है। इस घटना से यही प्रतीत होता है कि तमिलनाडु में किसी को सरकार का विरोध करने का हक नहीं है। अगर लोकतंत्र में कोई जनकल्याण के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो इसके लिए आवाज उठाने वाले पर देशद्रोह का केस लगाकर उसे जेल में डाल देना यह कहाँ का न्याय है।

-रवि ओझा, पटना, बिहार.

अनेकता में एकता

तंद्रा टूटती है। नौ बजे वाली न्यूज चालू होती है, रिमोट का बटन दूरदर्शन पर रुक जाता है। देखने पर लगता है जैसे देश में सब कुछ ठीक ठाक है और अचानक कुछ साल पहले की यादों में मैं डूब जाता हूँ। जब हम सिर्फ दूरदर्शन ही देखते थे कम से कम, मन के चैनल तो ठीक रहते थे सुबह घर से निकलते समय यह डर तो नहीं था कि पड़ोसी चचा कहीं सींगी वाले जिन न बन गए हों। सब कुछ इतना बुरा नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति हर बात से सहमत हो। यहां बात चाहे व्यक्ति विशेष की हो या किसी राजनीतिक दल की। सभी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। मैं उन सभी से विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहता हूँ जिन्होंने असहिष्णुता के विरोध का तरीका पुरस्कार लौटाना चुना है। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूँ, लेकिन कहीं वे सब उस नई परंपरा को जन्म तो नहीं दे रहे हैं जहां पुरस्कारों को किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल विशेष से जोड़कर देना शुरू हो।

यह दुखद होगा, क्योंकि सरकारी सम्मान संपूर्ण राष्ट्र या राज्य की जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, किसी दल को नहीं। पुरस्कार लौटाने का यह सिलसिला जाने-अनजाने में देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकता है, जिसमें आम आदमी सहिष्णुता-असहिष्णुता के जाल में फंसकर दिशाहीन हो सकता है। मेरा निवेदन है कि सहिष्णुता के नाम पर परंपराओं को न्यूठावरण न करें, क्योंकि अच्छी परंपराएं विधि अनुरूप होती हैं और अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी। महान कवि सुब्रह्मण्यम की कविता की ये पंक्तियां सहसा प्रासंगिक हो उठी हैं कि सभी के दिलों में सर्वदा संवेदना की आह हो, हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो। आइए इन पंक्तियों को आत्मसात् करते हुए हम सभी यह शपथ लें कि हम अपनी गली अपने मोहल्ले से भारत बनाएंगे, क्योंकि भारत एक भावना है, अनेकता में एकता की भावना, जिसकी अक्षुण्णता की रक्षा हम सभी का धर्म है।

-भूपेन्द्र प्रताप सिंह, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश.

चुनिंदा खामोशी, नपुंसक कलम



अनंत विजय

अभी हाल में कई खबर आई जिसपर हमारे देश के प्रगतिशील साहित्यकारों का ध्यान लगभग न के बराबर गया. चीन के एक विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए एक फरमान जारी किया. इस फरमान के मुताबिक कैंपस में कोई लड़का या लड़की एक-दूसरे के हाथ में हाथ डालकर नहीं चल सकते हैं. इसी फरमान में ये भी आदेश दिया गया कि लड़का-लड़की एक-दूसरे के कंधे पर हाथ भी नहीं रख सकते हैं और उनको एक-दूसरे को खाना खिलाने पर भी पाबंदी लगाई गई. इसके अलावा भी इस फरमान में कई ऐसी बातें हैं जो बालिंग छात्र-छात्राओं के फैसले लेने पर बाधा बनती हैं. चीन के एक विश्वविद्यालय का ये फैसला एक खबर की तरह आया और चला गया. देश में हर बात पर प्रगतिशीलता को गले में मेडल की तरह डाल कर घूमने वाले बुद्धिजीवी या लेखक संगठनों के मुंह से चूं तक नहीं निकली. किसी को निजता का हनन नजर नहीं आया. प्रगतिशील जमात में से किसी ने चीनी विश्वविद्यालय के इस फैसले पर विरोध नहीं जताया, बयान जारी करने तक की औपचारिकता नहीं निभाई गई.

दूसरा मसला भी चीन का ही था. चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने एक बार फिर से अजीबोगरीब फरमान जारी कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. वहां के शासक दल के नए हुक्मनामे के मुताबिक पार्टी कांडर के गोल्फ खेलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. तर्क यह दिया गया है कि इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी. चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के नए फरमान के मुताबिक पार्टी के करीब पीने की करोड़ सदस्यों के लिए जिस आठ सूत्रीय नैतिक फॉर्मूले को जारी किया गया है उसमें गोल्फ के अलावा होटलों में अधिक खाने पीने की मनाही तो है ही विवाहेतर संबंधों पर रोक भी लगा दी गई है. गोल्फ से तो कम्यूनिस्ट पार्टी का पुराना बैर रहा है. माओ ने इसको बुजुआ खेल मानते हुए इसपर पाबंदी लगाई थी. उसके बाद दंग के शासनकाल में गोल्फ को अनुमति मिली थी लेकिन लगातार इस खेल के खिलाफ चीन में मुहिम चलती रही. चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के इस नए निर्देशों के बाद पूरी दुनिया में मानवाधिकार को लेकर सचेत

लोगों ने विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं लेकिन चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी को मानवाधिकार की कहां फिक्र है. सेंट्रल कमेटी ने अपने कांडर से साफ तौर पर कहा है कि वो व्यक्तिगत बातों को पार्टी के साथ साझा करें और फैसले की जिम्मेदारी पार्टी पर छोड़ें. कार्यकर्ताओं की रुचि से लेकर उसकी व्यक्तिगत जिंदगी तक तो पार्टी के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है. उनका चेरमैन हमारा चेरमैन का नाम लगानेवाली प्रगतिशील जमात चीन के इस कदम पर खामोश है. ये दोनों मसले चीन के थे, लिहाजा उनके मुंह पर ताला लग गया. जहां से वैचारिक ऊर्जा मिलती हो, वहां की हुकूमत के फैसले के

लड़ा लेकिन सिर्फ तीन सीटों पर संतोष करना पड़ा. लोकतंत्र में जब साख छीजती है तो जनता की अदालत में यही हथ्र होता है.

अब जरा एक और खबर की ओर नजर डाल लेते हैं. अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में एक नाटक में भारतीय चरित्र के लिए श्वेत अमेरिकी लड़कों के चुनाव के बाद हंगामा मच गया. पश्चिमी पेनसिलवेनिया के एक सरकारी संस्थान में होनेवाले इस लॉयड सुह के इस नाटक को रद्द कर दिया गया. अपने नाटक के मंचन का अधिकार लेखक ने नहीं दिया क्योंकि उनका कहना था कि ये नाटक की मूल भावना के खिलाफ होगा कि श्वेत शक्तियत के चरित्र को

से अभिनय करवाना नाटक के साथ अन्याय होगा. इसके बाद बातचीत टूट गई और नाटक का मंचन रद्द करना पड़ा. इस नाटक के निर्देशक मार्लियो मिशेल ने लेख लिखा और नाटककार को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये निर्देशक का फैसला होता है कि वो अपने किस चरित्र में किस अभिनेता से अभिनय करवाए. विश्वविद्यालय ने भी नाटककार के फैसले पर दुख जताते हुए कहा कि इससे छात्रों का दिल टूट गया है और अब वो लॉयड के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते हैं. ये खबर भी भारत के अखबारों में छपी लेकिन नस्लभेद की इस संगीन घटना पर हमारे यहां किसी भी कोने

परेशान करनेवाली है. इसी तरह का एक विवाद दो हजार ग्यारह में लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में पंकज मिश्रा और नील फरग्युसन के बीच हुआ था. दोनों के बीट नस्लवादी लेखन पर कई अंकों में लेख-प्रतिलेख छपे थे. नील फरग्युसन की किताब-सिविलाइजेशन, द वेस्ट एंड द रेस्ट पर पंकज मिश्रा ने लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में समीक्षा लिखी थी जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था. उस वक्त भी भारत के लेखक खामोश रहे थे. हमें इन खामोशियों का मतलब समझ नहीं आता है. अगर आप बौद्धिक रूप से ईमानदार हैं, अगर आप किसी विचारधारा की बेडियों में जकड़े हुए नहीं हैं तो साहित्यिक और सामाजिक मुद्दों पर आपकी कलम वस्तुनिष्ठ होकर चलनी चाहिए. यही कलम जब वस्तुनिष्ठ नहीं रहती है और चुनिंदा प्रतिक्रिया देती है तब पाठकों का विश्वास लेखक से डगता है.

चीन से लेकर अमेरिका से लेकर लंदन तक ये घटी घटनाओं पर लाल कलम पता नहीं क्यों नपुंसक हो जाती है? कलम में वो धार होनी चाहिए वो तेज होनी चाहिए जो कि एक न्यायप्रिय शासक के पास हुआ करती थी. जो बगैर धारा, विचारधारा, संगठन, स्वार्थ, जाति समुदाय आदि को देखे न्याय करता था. कलम को अगर हम किसी खास विचारधारा का गुलाम बनाएंगे या फिर कलम की धार किसी खास समुदाय के समर्थन में उठा करेगी तो समय के साथ उस कलम पर से पाठकों का विश्वास उठता चला जाएगा. भारत के ज्यादातर प्रगतिशील लेखकों के साथ यही हुआ है. उनकी कलम चुनिंदा मसलों पर चलती रही है. एमएफ हुसैन पर वो बोलते रहे लेकिन तस्लीमा पर साजिश खामोश रहे. हिंदुओं के बीच बढ़ रहे कथित कट्टरता पर उन्होंने जोरदार प्रतिवाद किया लेकिन जब मुस्लिम कट्टरपन की बात आए तो एक अजीब तरह की खामोशी या उदासीनता देखने को मिली. यह दोहरा रवैया प्रगतिशीलों ने जानबूझकर रखा इस बात के तो प्रमाण नहीं हैं लेकिन जब कई मसलों पर ऐसा हुआ तो लगा कि इसके पीछे कुछ है. अब वक्त आ गया है कि प्रगतिशील जमात अपने पूर्व के कारनामों पर सफाई दे और ये साफ करे कि उनकी प्रतिक्रिया किन मसलों पर नहीं आई. यह उनके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी क्योंकि विचारों का प्रवाह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn7@gmail.com



भारत में बढ़ती असहिष्णुता का आरोप लगाकर उसके खिलाफ अमेरिका से अपील करने वालों ने भी नस्लभेद की इस गंभीर घटना पर कुछ नहीं कहा. बात-बात पर संयुक्त राष्ट्र में जाने की बात करनेवाले हमारे सियासतदां ने भी इस खबर को गंभीरता से नहीं लिया. भारत में बढ़ रही कथित असहिष्णुता पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान को उद्धृत करनेवाले भी खामोश हैं. ये खामोशी बहुत परेशान करनेवाली है. इसी तरह का एक विवाद दो हजार ग्यारह में लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में पंकज मिश्रा और नील फरग्युसन के बीच हुआ था.

खिलाफ कैसे मुंह खुल सकता है? आस्था से लेकर प्रतिबद्धता का सवाल जो ठहरा. प्रतिबद्धता के बौद्धिक गुलामों से ये अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए कि वो चीन के किसी फैसले के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे. यही फैसला अगर बीजेपी शासित किसी राज्य में हो जाता तो अब तक ये जमात उस राज्य के मुख्यमंत्री समेत देश के प्रधानमंत्री से जवाब तलब कर रहे होते.

देश में निजता के दखल को लेकर छाती कूट रहे होते. इस तरह के चुनिंदा प्रतिरोध से ही प्रगतिशील जमात के विरोध को देश की जनता ने गंभीरता से लेना छोड़ दिया. विहार चुनाव में तमाम वामपंथी दलों ने एकजुट होकर चुनाव

कोई अश्वेत निभाए. उसके बाद पूरे विश्वविद्यालय में नस्लवाद पर बहस शुरू हो गई है. नाटककार लॉयड ने अपने इस नाटक - जीजस इन इंडिया- के रद्द होने को जायज ठहराते हुए कहा कि दक्षिण एशिया के लोगों के चरित्र में गोरे लोगों को दिखाना उचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ये नाटककार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नाटक में जिस रंग के चरित्र को गढ़ता है उसके मंचन के वक्त उसी रंग या नस्ल का कलाकार उस चरित्र को निभाए. नाटक को रद्द करने का फैसला लेने के पहले लॉयड ने विश्वविद्यालय के छात्रों से अभिनय कर रहे छात्रों को बदलने को कहा. बातचीत के बाद नाटककार लॉयड ने जब यह कह दिया कि श्वेत चरित्र को अश्वेत कलाकार

अंतरे से आवाज नहीं आई. क्या साहित्य जगत में इस तरह की बातों पर विमर्श नहीं होना चाहिए. क्या दुनिया के किसी कोने में भारत के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव हो तो हमारे देश के बुद्धिजीवियों को खामोश रहना चाहिए? भारत में बढ़ती असहिष्णुता का आरोप लगाकर उसके खिलाफ अमेरिका से अपील करने वालों ने भी नस्लभेद की इस गंभीर घटना पर कुछ नहीं कहा. बात-बात पर संयुक्त राष्ट्र में जाने की बात करनेवाले हमारे सियासतदां ने भी इस खबर को गंभीरता से नहीं लिया. भारत में बढ़ रही कथित असहिष्णुता पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान को उद्धृत करनेवाले भी खामोश हैं. ये खामोशी बहुत

सर्द रात, ऑटो चालक और मैं...

डर केवल उस कार्ड के गले में होने की वजह से गायब था क्योंकि एक तरफ से निश्चित था कि उपद्रवी तत्व भले ही सड़क पर परेशान कर लें लेकिन तथाकथित परेशान करने वाली पुलिस के हाथों तो परेशान नहीं ही किया जाउंगा. खैर भागते-भागते सड़क तक पहुंचा और आवाज लगाई, ऑटो, वह कहां रुकनेवाला था. ठंड तो उसके लिए भी थी ना. ऑटो का पर्दा लगाए वह बढ़ता जा रहा था. अचानक पता नहीं उसे क्या ख्याल आया होगा. मुझसे थोड़ी ही दूरी पर आगे जाकर ऑटो रुक गया. मैं ऑटो की तरफ लपका तो ऑटोवाले ने अपनी गाड़ी से गर्दन बाहर करते हुए कहा, भाई साहब गले के आईकार्ड से पता चल गया आप पत्रकार हैं नहीं तो इतनी सर्द रात में मैं कौन ऑटो रोकने वाला था.

गंगेश ठाकुर

देश की राजधानी दिल्ली, दिलवालों का शहर लेकिन दिल कहां से लाऊं? शहर ने कुल 16 सालों के अपने साथ में मुझे भी कुछ ऐसा ही बना दिया था. सर्दियों की रात और मैं बेतहाशा भागा जा रहा था. ऑफिस की छुट्टी हुई थी. रात के बारह बजे थे. गले में मीडिया कंपनी का आईकार्ड लटका हुआ था. थोड़ा-बहुत हीसला सिर्फ उस आईकार्ड की वजह से बचा हुआ था बाकी कमजोर तो मुझे उस ठिठुरती ठंड ने पहले ही बना रखा था. डर केवल उस कार्ड के गले में होने की वजह से गायब था क्योंकि एक तरफ से निश्चित था कि उपद्रवी तत्व भले ही सड़क पर परेशान कर लें लेकिन तथाकथित परेशान करने वाली पुलिस के हाथों तो परेशान नहीं ही किया जाउंगा. खैर भागते-भागते सड़क तक पहुंचा और आवाज लगाई, ऑटो, वह कहां रुकनेवाला था. ठंड तो उसके लिए भी थी ना. ऑटो का पर्दा लगाए वह बढ़ता जा रहा था. अचानक पता नहीं उसे क्या ख्याल आया होगा. मुझसे थोड़ी ही दूरी पर आगे जाकर ऑटो रुक गया. मैं ऑटो की तरफ लपका तो ऑटोवाले ने अपनी गाड़ी से गर्दन बाहर करते हुए कहा, भाई साहब गले के आईकार्ड से पता चल गया आप पत्रकार हैं नहीं तो इतनी सर्द रात में मैं कौन ऑटो रोकनेवाला था. सुकून मिला मुझे चलो इस कार्ड की इज्जत इनकी नजरों में भी है. मैंने तपाक से कहा, यार आज ऑफिस की कैब जल्दी चली गई और मुझे काम था सो देर हो गई है. क्या तुम यमुना पार तक छोड़ दोगे. उसने कहा साहब लक्ष्मी नगर तक तो मैं जा रहा हूँ. वहां से आगे कहां जाना है? मैंने कहा, बस वहीं तक. अब मेरी जान में जान आई. घबराहट से मुक्ति मिली तो इस बात को लेकर निश्चिंत था कि चलो घर तक तो पहुंच जाऊंगा. ऑटो पर चढ़ते ही पर्दा खींच दिया और हाथ पर हाथ रगड़ने लगा मैं. ठंड की वजह से कंपकंपी सी लग रही थी. वह ऑटो झड़वर पूरे ओवरकोट में लगातार गाड़ी खींचे जा रहा था. मैंने ही उससे बातचीत की शुरुआत करते हुए पूछा- भाई सीपी होते हुए जाओगे क्या? मेरे सवाल पर वह मुस्कराया और बोला- सर, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि सीपी का बाजार आपके लिए इतनी



रात गए इन सर्दियों में भी खुला होगा? फिर वह हंसने लगा. मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया. उसका भी जवाब तपाक से आया सर, मैं भी मजाक कर रहा था वहीं से होकर चलेंगे और रास्ता कौन सा है? फिर मेरी नजर अचानक फुटपाथ पर अंधेरे में कांपते दो साये पर पड़ी मैं सकपका गया. मैंने झूड़वर से कहा भाई थोड़ा ऑटो तेज करना, पता नहीं कौन लोग हैं. वह फिर हंसते हुए बोला, अरे साहब कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये उपद्रवी लोग हैं. साले वह भी इतनी ठंड में जिहाद करने नहीं निकलेंगे. आप आराम से बैठिए ये स्मैकिये होंगे. स्मैक लेने के बाद इन्हें कौन सा पता चलता है ठंड का. मैंने उसकी तरफ फिर देखा और कहा भाई रोक तो सही ये स्मैकी लोग नहीं लगते हैं कभी तो किसी की मजबूरी समझा कर यार. उसने मेरी तरफ देखकर कहा, साहब इनकी मजबूरी आप जैसे लोग ही समझो हम तो पूरे दिन रात यही समझते रहते हैं और वैसे भी आपके धंधे में तो खोज भी इसी पर होती है और खबर भी आप बना देते हैं. सरकार की बड़इंतजामी की वजह से ठंड से ठिठुरकर 100 लोग मरे, और फिर वह हंसने लगा. मैंने कहा, भाई तुम्हें जो कहना है बाद में कहना पहले गाड़ी रोक. उसने तेज ब्रेक मारी और गाड़ी खड़ी हो गई. मैं सामने पहुंचा तो देखा एक 20-22 साल का नवदंपति जोड़ा वहां ठंड से ठिठुर रहा था मैंने सीधे तौर पर उनसे सवाल किया तो वह घबरा गए. दोनों को लगा शायद पुलिस वाले हैं. मैंने पूछा भी उसी अंदाज में कि यहां क्या कर रहे हो,

दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया सर, वो दिन भर मेट्रो जहां बन रही है, वहां काम किया था अब रात में सोने के लिए यहां आ गए थे. ठंड ज्यादा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है. कमरा नहीं है क्या, जवाब मिला- सर, किसी तरह तो इस शहर में गुजारा हो रहा है. कमरा कहां से होगा? सर, दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं. पिछले कई दिनों से ठंड में ऐसे ही रात गुजार रहे हैं. फिर लड़के ने उस औरत की तरफ दिखाकर कहा सर, आज शाम से मेरी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब है. यहां पास के ही जीबीपंत अस्पताल में गया था सर उसे दिखाने. डॉक्टर ने मुफ्त में उसे देखा तो सही सर लेकिन फिर पर्चे पर दवाई लिख दी. कहा, बाहर से ले लेना. दो यहाँ से मिल जाएंगी. वह लेने दवा काउंटर पर गए तो पता चला दवा खत्म है. कहा गया, बाहर से ले लो. मैंने उनसे पूछा साहब, पैसे नहीं हैं कहां से लूंगा. उसने कहा हम केवल डॉक्टर देख सकते हैं. सरकार ने तुम लोगों को दवाई देने के लिए लंगर नहीं लगाया है. वह रोने लगा और बोला, मैंने उनसे कहा साहब कि दवाई खरीदने की हिम्मत होती तो सरकारी अस्पताल ही क्यों आते? सर, फिर क्या था गाली देकर भगा दिया मुझे. तब से आया हूँ तो इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है. मेरे अंदर की कंपकंपाती सदीं खत्म हो चुकी थी मैं गर्मी का एहसास कर रहा था. मैंने तुरंत ऑटोवाले को बुलाया तो वह दौड़कर आया और बोला-कहिए सर. मैंने कहा भाई इनकी मदद करो ऑटो में बिठाओ और पास के किसी अस्पताल में ले चला. वह भी मेरे साथ मिलकर उन्हीं अस्पताल ले आया और फिर दोनों को दवा दिलाकर ऑटोवाले के साथ मैं अपने कमरे पर ले आया. मैंने रास्ते में ऑटो वाले से बस इतना ही कहा भाई कभी स्मैकी को भूलकर इंसान समझकर सड़क के दोनों तरफ भी देख लिया करो. ऑटोवाला मेरी बात पे एकदम झंप गया और शर्माते हुए बोला सर, गलती तो है खैर अब ध्यान रखूंगा. ■

(लेखक पत्रकार हैं. इनकी कहानियां व कविताएं कई पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

कविता

नया चांद

हरिवंश राय बच्चन



उगा हुआ है नया चांद
जैसे उगा चुका है हजार बार.
आ-जा रही हैं कारें
साइकिलों की कतारें;
पटरियों पर दोनों और
चले जा रहे हैं बूढ़े
ढोते जिंदगी का भार
जवान, करते हुए प्यार
बच्चे, करते खिलवार.
उगा हुआ है नया चांद
जैसे उगा चुका है हजार बार.
मैं ही क्यों इसे देख
एकाएक
गया हूँ रुक
गया हूँ झुक!





मुन्नार का हिल स्टेशन किसी जमाने में ब्रिटिश प्रशासन का ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। इस हिल स्टेशन की पहचान है यहां के विस्तृत भू-भाग में फैली चाय की खेती, औपनिवेशिक बंगले, छोटी नदियां, झरनें और ठंडे मौसम। ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए यह एक आदर्श स्थल है। मुन्नार के आसपास कुछ ऐसे स्थल भी हैं, जो मनमोहक हिल स्टेशन का आनन्द लेने के लिए यात्रियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।



खाना पीना

सर्दियों में बनाएं स्वादिष्ट सत्तू का पराठा

बिहार में खूब पसंद किए जाते हैं सत्तू के पराठे, खाने में इनका स्वाद एकदम अलग और स्वादिष्ट होता है तो आप भी बनाकर खाएं बिहार की ये पसंदीदा डिश।

आवश्यक सामग्री

- 2 कप सत्तू
- कढ़कस की हुई 5 से 6 लहसुन की कलियां
- बारीक कटे 2 प्याज
- कढ़कस की हुई एक इंच अदरक
- बारीक कटी 3 हरी मिर्च
- 2 चम्मच नींबू का रस
- आधी चम्मच अजवायन
- आम के अचार के 2 टुकड़े पिसे हुए या अमचूर पाउडर



बारीक कटा हरा धनिया
स्वादानुसार नमक
तेल

आटा गुंदने के लिए सामग्री

- 3 कप गेहूं का आटा
- 2 चम्मच घी

आधा चम्मच नमक

विधि

स्टफिंग तैयार करने के लिए

- सत्तू में लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, नींबू का रस, अजवायन, आम का अचार, हरा धनिया, नमक और एक से 2 चम्मच पानी डालकर मिलाएं।
- एक बर्तन में गेहूं का आटा छानकर इसमें घी और आधा चम्मच नमक मिलाकर आवश्यकतानुसार पानी डालकर नर्म आटा गुंते।
- आटे की लोई बनाकर उसे पूरी के शेप में बेलें। इसमें सत्तू का मसाला भरकर (स्टफिंग) रखकर पूरी को चारों तरफ से मोड़कर बंद करके दबा दें।
- फिर भरी हुई परियों को बेलकर गोल पराठे बना लें।
- तवा को गर्म करें और उस पर तेल डालकर मध्यम आंच पर पराठा सेंक लें। दोनों तरफ से सुनहरा या ब्राउन होने तक सेंकें।
- सत्तू के पराठे तैयार हैं। इसे चटनी या दही के साथ परोसें।

फैशन



कोलकाता में मीडियाकॉम मोबाइल की लॉन्चिंग के दौरान मोबाइल का प्रदर्शन करतीं मॉडल्स।

विंडोज 10 पर चलेगा लुमिया 950 और 950 एक्सएल

माइक्रोसॉफ्ट के नए विंडोज स्मार्टफोन लुमिया 950 और 950 एक्सएल को कंपनी भारत में लॉन्च कर सकती है। यह पहला एकमात्र स्मार्टफोन होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 वर्जन पर चलेगा। लुमिया 950 में 5.2 इंच क्यूएचडी डिस्प्ले होगा, जबकि लुमिया 950 एक्सएल में 5.7 इंच का क्यूएचडी डिस्प्ले होगा। दोनों ही स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो कार्ल जेस ऑप्टिक से लैस होगा। इन दोनों ही स्मार्टफोन में 32 जीबी मेमोरी है, जिसे कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही डिवाइस विंडोज 10 पर काम करेंगे। स्मार्टफोन में 64 बिट हेक्सा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 808 प्रोसेसर और साथ ही फोन में 3 जीबी रैम होगी। डिवाइस में 21 मेगापिक्सल का प्योरव्यू रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का वाइड-एंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा, 32 जीबी की इनबिल्ट स्टोरेज (माइक्रोएसडी कार्ड के लिए सपोर्ट मौजूद) और 3000 एमएच बैटरी है।



feedback@chauthiduniya.com

करियर

मोबाइल गेमिंग में है शानदार करियर

मोबाइल गेम को लेकर लोगों के बीच क्रेज टाइम के साथ बढ़ गया है। अगर जॉब के लिहाज से देखें तो इस सेक्टर में जॉब ऑप्शंस की संभावनाएं हैं। आज के हाईटेक वर्ल्ड में बच्चों के साथ-साथ युवा भी हाईटेक गेम्स के दीवाने होने लगे हैं। तभी तो उन्हें अब आउटडोर गेम कम और इंडोर गेम ज्यादा पसंद आने लगा है। यही वजह है कि इंडोर गेम्स यानी वीडियो, कम्प्यूटर और मोबाइल गेम्स का बाजार कई गुना बढ़ गया है। जिस रफ्तार से यह सेक्टर बढ़ रहा है, उससे गेम डेवलपर्स की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मोबाइल गेम्स के फिल्ड में आप गेम डेवलपर, कम्प्यूटर गेम प्रोड्यूसर, गेम डिजाइनर, एनिमेटर, ऑडियो प्रोग्रामर और ग्राफिक प्रोग्रामर बन कर अपना एक शानदार करियर बना सकते हैं।

रोजगार की संभावनाएं :

इस समय रोजगार के लिहाज से यह सेक्टर एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है, क्योंकि कई गेमिंग कंपनियां भारत में अपना सेटअप तैयार करवा रही हैं, लेकिन अच्छे गेम डेवलपर्स की काफी कमी महसूस की जा रही है। इस क्षेत्र में जावा, सी, सी प्लस प्लस, 2डी गेम डेवलपर्स, 3डी डेवलपमेंट के जानकारों के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं। इस फिल्ड में कई तरह से काम किया जा सकता है।

सैलरी पैकेज :

देश में गेमिंग की दुनिया में 2डी और 3डी डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की मांग है। इस हाईटेक गेम वर्ल्ड में शुरुआती दौर में ही आपकी सैलरी 2 लाख रुपये सालाना हो सकती है।

टॉप गेम डेवलपर्स :

डिजिटल चॉकोलेट, बंगलुरु
इंडिया गेम्स, मुंबई
जंप गेम्स, मुंबई



शैर-सपाला

अनोखा पर्यटन स्थल है मुन्नार

मुन्नार का केरल में पर्यटन स्थल के तौर पर काफी महत्व है। मुन्नार तीन पर्वतों की श्रृंखला है। मुन्नार का हिल स्टेशन किसी जमाने में दक्षिण भारत के पूर्व ब्रिटिश प्रशासन का ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। इस हिल स्टेशन की पहचान है यहां के विस्तृत भू-भाग में फैली चाय की खेती, औपनिवेशिक बंगले, छोटी नदियां, झरनें और ठंडे मौसम। ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए यह एक आदर्श स्थल है। मनमोहक हिल स्टेशन के कारण इस स्थान की छवि देखते ही बनती है। अगर आपको असीम आनंद चाहिए तो मुन्नार आना न भूलें। और क्या देखने के लिए है मुन्नार में, आइए आपको बताते हैं:

राष्ट्रीय उद्यान

इचिकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार और उसके आसपास के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह मुन्नार से लगभग 14 किमी दूर है और लुमप्राय

प्राणी-नीलगिरी टार के लिए जाना जाता है। लगभग 96 वर्गकिमी में फैला यह उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों का बसेरा है। यह ट्रैकिंग के लिए भी सर्वोत्तम स्थान है। यह उद्यान चाय के बगान और साथ ही लहरदार पर्वतों पर भुंध की चादर का एक विस्तृत नजारा पेश करता है। नीलकुर्रिजी के फूल यहां के वातावरण को और भी मनोरम कर देता है। नीलकुर्रिजी नीले रंग का फूल होता है। जब यह खिलता है तो पहाड़ों की ढाल नीली चादर से ढक जाती है, तब यह उद्यान ग्रीष्मकालीन पर्यटन के लिए खूबसूरत स्थल बन जाता है।

माट्टूपेट्टी

मुन्नार शहर से लगभग 12 किमी दूर स्थित दूसरा दिलचस्प स्थान है माट्टूपेट्टी। माट्टूपेट्टी अपने स्टारज मेसनरी बांध और खूबसूरत झील के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्वतों के लिए आसपास के पहाड़ों और

भू-दृश्यों का मजा लेते हुए आनन्ददायक नौकाविहार की सुविधा है। यहां आप गायां की अधिक दूध देने वाली नस्लें देख सकते हैं। हरे-भरे चाय के बगान, ऊंचे-नीचे घास के मैदान और शोला वन के साथ-साथ माट्टूपेट्टी ट्रैकिंग के लिए भी आदर्श स्थल है और यहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों का भी बसेरा है।

पल्लिवासल

पल्लिवासल मुन्नार के चितिरपुरम से लगभग 12 किमी दूर स्थित है। यह स्थल व्यापक प्राकृतिक सुन्दरताओं से भरा पड़ा है और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्थल है।

चिन्नकनाल

चिन्नकनाल मुन्नार शहर के निकट स्थित है। यहां के झरनें, जिसे आमतौर पर पावर हाउस वाटरफॉल कहा जाता है, खड़ी चट्टान पर समुद्र तल से 2000



मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। यह स्थल पश्चिमी घाट की पर्वत-श्रेणियों के प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध हैं।

टॉप स्टेशन

मुन्नार-कोडेकनाल सड़क पर स्थित यह सबसे ऊंचा स्थान है। टॉप स्टेशन देखने आने वाले पर्यटक मुन्नार को अपना पड़ाव बनाते हैं और इस टॉप स्टेशन से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के विहंगम दृश्यों का आनन्द लेते हैं। मुन्नार में, यहां से विस्तृत क्षेत्र में

नीलकुर्रिजी के खिले हुए फूलों को देखने के लिए भी यह एक उपयुक्त स्थान है।

कैसे जाएं:

मुन्नार जाने के लिए सड़क और हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध है।

चौथी दुनिया व्यूरो

feedback@chauthiduniya.com



पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने हाल ही में एक कॉलम में लिखा कि आईसीसी को भी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार होने वाली पिचों के निर्माण में अहम भूमिका निभानी होगी. पहले जिस तरह काउंटी क्रिकेट में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) खराब पिच या साधारण पिच की वजह से रैंकिंग अंक घटा दिया करता था, कुछ ऐसी ही मैकनिज्म टेस्ट क्रिकेट में भी लानी होगी.

खराब पिचों के कारण

टेस्ट क्रिकेट तमाशा बन गया है

भले ही टीम इंडिया अपनी जीत पर इतरा रही है लेकिन हकीकत यह है कि स्पिनर्स की स्किल से ज्यादा पिच का कमाल है. पिच इतनी खराब है कि भारत के बल्लेबाज भी बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं. लेकिन इससे तब कोई फर्क नहीं पड़ता जब टीम को जीत मिल रही है. मोहाली में तो फिर भी पिच सही थी, लेकिन नागपुर में तो हद हो गई. एक ऐसी पिच बनाई गई, जिस पर दुनिया की नंबर एक टीम साउथ अफ्रीका का टिकना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो गया. ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भारतीय स्पिनर ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं.



नवीन चौहान

भारतीय उप-महाद्वीप में खराब पिच को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रही हालिया टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में यह सवाल एक बार फिर जीवंत हो उठा. दोनों देशों के बीच मोहाली में खेला गया पहला टेस्ट तीन दिन में समाप्त हो गया, बंगलुरु में खेला गया दूसरा टेस्ट बारिश की भेंट चढ़ गया, इसके बाद नागपुर में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच भी तीसरे दिन ही खत्म हो गया और भारत ने सीरीज में अपराजेय बढ़त हासिल कर ली. ऐसे में पिच पर सवाल उठने भी लाजिमी थे. नागपुर में तो अप्रत्याशित तौर पर पहले ही दिन पिच टूटने लगी. यदि दूसरे दिन लंच तक पिच से धूल उड़ने लगे तो गेंद जरूरत से ज्यादा स्पिन होगी ही. ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के पास आर अरिचन, रविंद्र जड़ेजा और अमित मिश्रा की घूमती गेंदों का कोई जवाब नहीं था और वे एक-एक करके धराशायी होते चले गए.

आम तौर पर भारतीय खिलाड़ी इस बात की शिकायत करते हैं कि जब वे उप-महाद्वीप के बाहर दौड़ें पर जाते हैं, तब उन्हें वहां ज्यादा घास वाली तेज पिचों पर खेलना पड़ता है. वहां की परिस्थितियां उप-महाद्वीप की परिस्थितियों से बिलकुल अलग होती हैं, ऐसे में विदेशी दौड़ों पर भारतीय टीम को

अक्सर हार का मुंह देखना पड़ता है. ऐसे में यदि कोई टीम भारतीय उप-महाद्वीप का दौरा करती है और उसके खिलाड़ियों को जल्दी टूटने वाले विकेटों पर स्पिन गेंदबाजी का सामना करना पड़ता है और वे उसमें असफल रहते हैं. उनकी हार के लिए विकेट जिम्मेदार कैसे हो जाता है जबकि भारतीयों की विदेशों हार के लिए पिचों की बजाय बल्लेबाजों की तकनीक को जिम्मेदार ठहराया जाता है. यदि हर मेजबान देश अपने खिलाड़ियों की मदद करने वाले विकेट बनाता है तो भारत क्यों और कहां गलत है.

जब कभी भारतीय टीम विदेशी धरती पर धराशाही होती है उन्हीं पिचों पर मेजबान देशों के बल्लेबाज नए-नए कीर्तिमान बनाते हैं. भारत में ठीक इसके उलट हो रहा है. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भले ही इन पिचों पर ढेर हो रहे हों, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की स्थिति भी सुखद नहीं है. सीरीज के पहले तीन टेस्ट मैचों में भारतीय बल्लेबाज भी घुटने टेकते दिखाई दिए. वे भी इन घुमावदार टेस्ट पिचों पर खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं. सीरीज में कोई भी भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं बना सका, साथ ही तीन टेस्ट मैचों में भारतीय टीम एक बार भी तीन सौ के आंकड़े को छू नहीं पाई. एक पूरे दिन भारतीय टीम के लिए भी पिच पर बल्लेबाजी करना असंभव था. टीम इंडिया अधिकतम 76 ओवर तक पिच पर टिक पाई. इसे आप कैसा होम एडवांटेज कहेंगे. होम एडवांटेज बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मिलना

चाहिए. विदेशी धरती में उसी पिच पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के प्रदर्शन में संतुलन होता है लेकिन टीम इंडिया के घरेलू सरजमीं पर प्रदर्शन में ऐसा संतुलन दिखाई नहीं पड़ रहा है.

भले ही टीम इंडिया अपनी जीत पर इतरा रही है लेकिन हकीकत यह है कि जीत में स्पिनर्स की स्किल से ज्यादा पिच का योगदान है पिच इतनी खराब है कि भारत के बल्लेबाज भी बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं. लेकिन इससे तब कोई फर्क नहीं पड़ता जब टीम को जीत मिल रही है. मोहाली में तो फिर भी पिच सही थी, लेकिन नागपुर में तो हद

भले ही टीम इंडिया अपनी जीत पर इतरा रही है लेकिन हकीकत यह है कि जीत में स्पिनर्स की स्किल से ज्यादा पिच का योगदान है पिच इतनी खराब है कि भारत के बल्लेबाज भी बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं. लेकिन इससे तब कोई फर्क नहीं पड़ता जब टीम को जीत मिल रही है. मोहाली में तो फिर भी पिच सही थी, लेकिन नागपुर में तो हद हो गई. एक ऐसी पिच बनाई गई, जिस पर दुनिया की नंबर एक टीम का टिकना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो गया.



हो गई. एक ऐसी पिच बनाई गई, जिस पर दुनिया की नंबर एक टीम साउथ अफ्रीका का टिकना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो गया. ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भारतीय स्पिनर ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं. बल्लेबाज और तेज गेंदबाज तो बस टाइम पास कर रहे हैं. मौजूदा टेस्ट सीरीज के तीन मैचों में दक्षिण अफ्रीका की पांच पारियों के 50 में से 47 विकेट भारतीय स्पिनरों ने लिए हैं. ओपनिंग गेंदबाजी स्पिनर कर रहा है. यह क्रिकेट नहीं, तमाशा लग रहा है. आईसीसी को निश्चित तौर पर पिचों के निर्माण के लिए कुछ मापदंड स्थापित करने होंगे. क्या दर्शकों के प्रति बीसीसीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या खेल स्तर में सुधार की बीसीसीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कहते हैं कि समय के साथ खेल के स्तर में सुधार आता है, लेकिन पिचों को लेकर जो जंग चल रही है, वह कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिए ठीक नहीं है. यह टेस्ट क्रिकेट के वजूद के सामने सबसे बड़ा खतरा है. ऐसे भी टेस्ट मैच देखने के लिए मैदान पर दर्शक नहीं उमड़ रहे हैं, उसमें भी जो दर्शक मैदान में खेल देखने आते हैं, उनकी रुचि भी इस तरह की नीरस, लो-स्कोरिंग और अप्रतिस्पर्धी क्रिकेट देखकर निश्चित तौर पर कम होगी. इस तरह की चुनौती से पार पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं.

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने हाल ही में एक कॉलम में लिखा कि आईसीसी को भी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार होने वाली पिचों के निर्माण में अहम भूमिका निभानी होगी. पहले जिस तरह काउंटी क्रिकेट में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) खराब पिच या साधारण पिच की वजह से रैंकिंग अंक घटा दिया करता था, कुछ ऐसी ही मैकनिज्म टेस्ट क्रिकेट में भी लानी होगी. ईसीबी की तर्ज पर अंक घटाने की प्रथा शुरू करनी चाहिए. जिसका सीधा असर मेजबान देश की विश्व रैंकिंग पर पड़े. ऐसी कोई व्यवस्था शुरू होने तक हमें नागपुर जैसी पिच पर अखाड़ा देखने को मिलना रहेगा. जहां गेंद मुश्किल से बल्ले पर आ रही थी. मेजबान टीम को लाभ मिलना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जैसा हमने नागपुर में देखा वैसा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए.

यदि हार-जीत और अहम का यह खेल चलता रहा तो, यकीन मानिए टेस्ट क्रिकेट एक दिन हारकर दम तोड़ देगा. हार-जीत के लिए परिस्थितियों या मेजबानी का फायदा उठाने की स्पर्धा में क्रिकेट का बड़ा नुकसान हो रहा है. उसी दौर में एक तरफ टेस्ट क्रिकेट के वजूद को बचाए रखने के लिए डे-नाइट टेस्ट जैसे प्रयोग हो रहे हैं, जहां पारंपरिक तरीकों से हटकर गुलाबी गेंद का इस्तेमाल हो रहा है. वहीं दूसरी तरफ भारत में स्पिन विकेटों पर पांच दिन तक खेल जाने वाले टेस्ट मैच तीन दिन में समाप्त हो रहे हैं. यदि आगे भी इसी तरह पिचों ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा हार-जीत का कारण बनती रहें तो यह टेस्ट क्रिकेट के वजूद के खत्म होने की दिशा में आखिरी कदम साबित होगा. ■

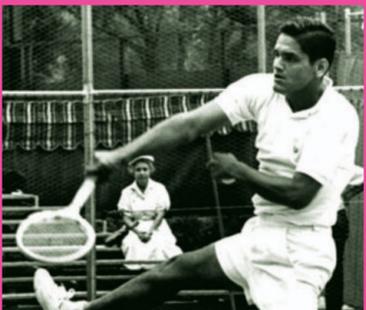
navinonline2003@gmail.com

यूना भूला पाएंगे...

रामनाथन कृष्णन

भारतीय टेनिस का पहला सितारा

क्रिकेट को छोड़कर, अन्य खेलों में भारत को सफलता कभी-कभी हासिल होती है. लेकिन कई बार ऐसे खिलाड़ी हमारे सामने आते हैं जो अपने प्रदर्शन से इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं और देश-विदेश में भारत का परचम



लहराते हैं. ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं रामनाथन कृष्णन. रामनाथन कृष्णन का जन्म 11 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु के नागकोइल में हुआ था. 1950 और 1960 के दशक के सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ियों में से एक थे. 1960 और 1961 में वो लगातार दो बार विम्बलडन के सेमीफाइनल तक

पहुंचे. 1954 में विम्बलडन में जूनियर एकल का खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने. कृष्णन 1962 में विम्बलडन में टखने की चोट के कारण नहीं खेल पाए. 1959, 1962, 1963 और 1968 में डेविस कप में कृष्णन ने अपने खेल से दुनिया को हैरान कर दिया. कृष्णन को 1962 में पद्म श्री और 1967 में पद्म भूषण में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया. उन्होंने विम्बलडन जूनियर, लंदन ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप, अमेरिकन हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप और एशियन लॉन टेनिस सिगल्स में जीत हासिल की थी. कृष्णन ने अ टच ऑफ टेनिस शीर्षक नाम की एक किताब भी लिखी. रामनाथन कृष्णन पहले भारतीय टेनिस प्लेयर थे जो दुनिया के उस दौर के 5 सबसे बेहतरीन टेनिस प्लेयर्स में शामिल हुए थे. भारत की ओर से खेलते हुए उन्होंने डेविस कप में 69 सिंगल गेम्स में से 50 जीते और 29 डबल्स गेम्स में से 19 में जीत हासिल की. दो बार के विम्बलडन सेमीफाइनलिस्ट रामनाथन ने दुनियाभर की 58 अन्य टेनिस प्रतियोगिताएं भी जीतीं. उनकी वजह से ही आगे की पीढ़ी की टेनिस में रुचि बढ़ी. ■

एक नजर

अर्जुन तेंदुलकर पर रहेगा पिता के नाम का दबाव : जहीर खान



हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का मानना है कि पिता सचिन तेंदुलकर के नाम का दबाव अर्जुन पर रहेगा. बड़ादा के खिलाफ विजय मर्चेंट ट्राफी के लिए मुंबई अंडर-16 टीम के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में अर्जुन का चयन हुआ है. अर्जुन ने अंडर-16 पय्यादे ट्राफी में कमाल का प्रदर्शन कर यह मुकाम हासिल किया है. जहीर ने अर्जुन के बारे में कहा कि वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने अपना पहला शतक भी इसी ही हफ्ते जड़ा है, उन पर पिता के नाम का दबाव रहेगा, लेकिन वह मैदान में क्या कर पाते हैं, सबसे अहम

यही है. अंडर-16 टीम और आगे की राह के बारे में जहीर ने कहा कि यदि कोई खिलाड़ी अच्छा है और बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, तो मेरी राय में इस प्लेनफॉर्म के जरिये उसे परखना चाहिए और युवा खिलाड़ियों को चाहिए कि वो इस मंच का इस्तेमाल लोगों की नज़रों में आने के लिए करें. अर्जुन मुंबई की अंडर-14 टीम का हिस्सा भी रहे हैं. अंडर-16 पय्यादे ट्राफी में सुनील गावस्कर इलेवन की ओर से खेलते हुए मैच की पहली पारी में 16 चौके, 2 छक्कों की मदद से अर्जुन ने 106 रन बनाए, इसके बाद गेंद गेंदबाजी में 73 रन खर्च कर 4 विकेट झटके. दूसरी पारी में भी अर्जुन ने अपनी टीम के लिए 40 रनों का योगदान दिया. ■

क्रिकेट के मैदान में महिला अंपायर

क्रिकेट के मैदान पर एक नया इतिहास आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के लिए 28 नवंबर से शुरू हुए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में लिखा गया. इस दौरान पहली बार महिला अंपायर अंपायरिंग के लिए मैदान में उतरीं. इससे पहले आईसीसी के मैचों में केवल पुरुष ही अंपायरिंग करते थे. आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए चार महिला अंपायरों की नियुक्ति की घोषणा करके इस परंपरा को तोड़ा और न्यूजीलैंड की अनुभवहीन खिलाड़ी कैथलीन क्रॉस, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक, इंग्लैंड की स्मू रेडफर्न और वेस्टइंडीज की जैकलीन विलियम्स के नामों की घोषणा की. ये चारों इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग करती दिखाई देंगी. टी-20 विश्वकप क्वालीफायर्स में बांग्लादेश, चीन, आयरलैंड, नीदरलैंड, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और जिम्बावे सहित आठ देशों ने हिस्सा लिया. क्वालीफाइ करने वाली टीमों में अगले वर्ष भारत में होने वाले टी-20 विश्वकप में खेलती दिखाई देंगी. इन चार महिला अंपायरों के अलावा पुरुष अंपायरों में एलन हेगो और निजेल मॉरिसन भी फील्ड अंपायर के रूप में नियुक्त किए गए थे. आईसीसी के महिला अंपायरों की नियुक्ति के फैसले के बाद इंग्लैंड की पूर्व कप्तान और आईसीसी महिला समिति की अध्यक्ष क्लेयर कौनर ने कहा, महिला टी-20 विश्व कप क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के लिए चार महिला अंपायरों की नियुक्ति आईसीसी में अहम रणनीतिक बदलाव की तरह है, जो खेल के सभी पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है. ■



चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अब सुपरगर्ल का किरदार निभाना चाहती हैं सनी लियोनी

पाँ न फिल्मों से बॉलीवुड का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी अब सुपरगर्ल का किरदार निभाना चाहती हैं। पिछले कई सालों में बॉलीवुड में सुपरहीरो की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है। सनी अपनी आने वाली होम प्रोडक्शन फिल्म में सुपरगर्ल का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। सनी ने कहा कि वह और उनके पति वेब डेनियल सुपरगर्ल का किरदार तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही सनी ने कहा कि वह अलग तरह की चीजें करने में विश्वास रखती हैं। यह फिल्म सनी लियोनी की होम प्रोडक्शन फिल्म होगी। फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले अभिनेता रितिक रोशन क्रिश सीरीज में सुपरहीरो का किरदार निभा चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ भी उनकी आगामी फिल्म में सुपरहीरो के किरदार में नजर आएंगे। ■

प्रीति जिंटा बनेंगी दुल्हन

एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जेने, प्रीति के ब्वॉयफ्रेंड नहीं हैं बल्कि करीबी दोस्त हैं। हालांकि प्रीति अपने भाई और उसके परिवार से मिलने नियमित तौर पर अमेरिका जाती रहती हैं। इसके अलावा उनके कई करीबी दोस्त भी अमेरिका में रहते हैं।

बाँ लीवुड की चुलबुली अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अंततः शादी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रीति अगले साल जनवरी तक अपने अमेरिकी ब्वॉयफ्रेंड जेने गुडेनसेफ से शादी कर सकती हैं। शादी के लिए प्रीति अमेरिका जाएंगी। इस विवाह समारोह में प्रीति का परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। हालांकि, एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जेने, प्रीति के ब्वॉयफ्रेंड नहीं हैं बल्कि करीबी दोस्त हैं। हालांकि प्रीति अपने भाई और उसके परिवार से मिलने नियमित तौर पर अमेरिका जाती रहती हैं। इसके अलावा उनके कई करीबी दोस्त भी अमेरिका में रहते हैं। हालांकि प्रीति ने शादी की खबरों को अफवाह बताया है। इससे पहले प्रीति का नेस वाडिया के साथ संबंध रहे थे। इनसे ब्रेकअप के बाद उनका नाम युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मिलर से भी जुड़ चुका है। ■



तमाशा आत्मकथा नहीं है इम्तियाज अली

नि देशक इम्तियाज अली ने बताया कि उनकी फिल्म तमाशा में उनकी जिंदगी के कुछ पल हैं लेकिन, यह कोई आत्मकथा नहीं है। फिल्म की कहानी के बारे में इम्तियाज ने कहा कि फिल्म तमाशा ऐसे प्यार की कहानी है, जो सामान्य लोगों के लिए असाधारण है, जिससे वह कलाकार और आम आदमी बनते हैं। यह इस तरह की कहानी है, जिसमें आप समझेंगे कि जिंदगी में महिलाएं क्यों जरूरी हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको पहचान दिलाएगी। इम्तियाज अली अपनी पत्नी से कुछ साल पहले अलग हुए हैं, उनका मानना है कि व्यक्तिगत जीवन और विचार आपको कहानी सुझाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी निजी जिंदगी पर आधारित फिल्म पर कहानी गढ़ें। उन्होंने बताया, फिल्म तमाशा में मेरी जिंदगी के कुछ पल हैं जिन्हें आप देखेंगे, लेकिन यह आत्मकथा नहीं है। अली ने कहा, मुझे तमाशा शीर्षक पहली बार में पसंद आया। तमाशा का अर्थ दृश्य जिसे आप देखेंगे और आनंद लेंगे। इम्तियाज ने इस फिल्म में अपने अंग्रेजी शीर्षक की प्रवृत्ति तोड़ी है, इससे पहले अपनी फिल्मों को जब वी मेट, रॉकस्टार और हाइवे जैसे नाम दिए हैं। ■

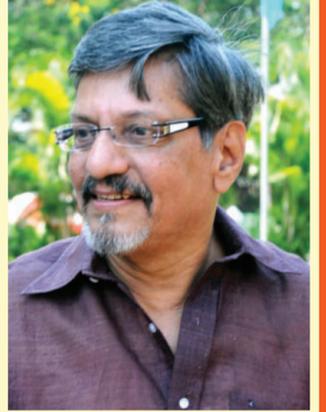
सेंसर बोर्ड पर आमिर ने उठाए सवाल



जे मस बांड की फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची के बारे में आमिर ने कहा है कि हाल-फिलहाल में सेंसर बोर्ड थोड़ा आक्रामक हुआ है। उनका मानना है कि यदि फिल्म को वयस्क प्रमाणपत्र (एडल्ट सर्टिफिकेट) मिल गया है, तो उसमें आप लगभग सबकुछ दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी वयस्क तय कर सकता है कि उसे फिल्म देखनी है या नहीं। प्रमाणपत्र के बाद सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। प्रमाणपत्र की हमारी समझ यही है। आमिर खान ने वर्तमान सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए और कहा कि सेंसर बोर्ड का असली काम इस बात का प्रमाण देना है कि किस आयु वर्ग के लोग कौन सी फिल्म देखें। आमिर ने मजाक के लहजे में कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी फिल्म राजा हिंदुस्तानी का किस सीन सेंसर नहीं किया गया था। दरअसल सेंसर बोर्ड ने हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म स्पेक्टर के किसिंग सीन्स पर कैंची चलाते हुए उसकी अवधि कम कर दी है। इस वजह से सेंसर बोर्ड को सोशल मीडिया पर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ■

हिंदी फिल्मों का अनमोल रत्न अमोल पालेकर

महाराष्ट्र के साधारण परिवार में जन्मे अमोल पालेकर ने बैंक में क्लर्क की नौकरी भी की थी। उनकी तीन बहनें थीं। उनके परिवार का फिल्मों से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। स्कूल-कॉलेज के दिनों तक अमोल ने कभी नाटक में भी काम नहीं किया था। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। मां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थीं। ग्रैजुएशन के बाद अमोल ने बैंक ऑफ इंडिया में आठ साल तक नौकरी की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मेरी शुरुआती तीन फिल्में सिल्वर जुबली हिट हो गई थीं, तब मेरे लिए नौकरी छोड़ना एकदम आसान हो गया था।



चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अमोल पालेकर हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने आर्ट और व्यावसायिक सिनेमा के बीच की खींचतान के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। 24 नवंबर को वह 71 साल के हो गए। फिलहाल वह एक पेंटर की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि पेंटिंग उनका पहला प्यार था। उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से पोस्टक ग्रेजुएशन करने के बाद करियर की शुरुआत बतौर पेंटर ही की थी। वह अक्सर कहते रहे हैं, मैं प्रशिक्षण पाकर पेंटर बना लेकिन दुर्घटनावश एक्टर बन गया, मजबूरी में प्रोड्यूसर बना और अपनी पसंद से डायरेक्टर बना। 1970 के दशक में अमोल पालेकर की बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान थी। उस दौर में वह काफी सोच-समझ कर फिल्में करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह दस में से नौ फिल्में रिजेक्ट कर देते थे। सत्तर के दशक में बासु चटर्जी-अमोल पालेकर की जोड़ी मनमोहन देसाई-अमिताभ बच्चन जैसी थी। इसके अलावा उन्होंने कैमरे के पीछे भी गजब की क्रिएटिविटी दिखाई। आकृत, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, दायरा, कैरी, पहली आदि फिल्मों और कच्ची धूप, नकाब, मृगनयनी जैसे टीवी सीरियलों के निर्देशन में अपना कमाल दिखाया।

महाराष्ट्र के साधारण परिवार में जन्मे अमोल पालेकर ने बैंक में क्लर्क की नौकरी भी की थी। उनकी तीन बहनें थीं। उनके परिवार का फिल्मों से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। स्कूल-कॉलेज के दिनों तक अमोल ने कभी नाटक में भी काम नहीं किया था। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। मां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थीं। ग्रैजुएशन के बाद अमोल ने बैंक ऑफ इंडिया में आठ साल तक नौकरी की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मेरी शुरुआती तीन फिल्में सिल्वर जुबली हिट हो गई थीं, तब मेरे लिए नौकरी छोड़ना एकदम आसान हो गया था।

एक्टिंग से उनका रिश्ता कुछ इस तरह जुड़ा, उनकी गर्लफ्रेंड थिएटर में दिलचस्पी रखती थीं। जब वह थिएटर में रिहर्सल के लिए जाती थीं तब अमोल वहां उनका इंतजार करते थे। इसी दौरान एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे की नज़र उनपर पड़ी। दुबे ने उन्हें मराठी नाटक शांताता! कोर्ट चालू आहें में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफी अच्छा रिव्यू मिला। इसके बाद

सत्यदेव दुबे ने अमोल से कहा कि अब जब लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है, तो उन्हें एक्टिंग का प्रशिक्षण लेना चाहिए, अगले नाटक के लिए उन्होंने अमोल को प्रशिक्षित किया। इस तरह नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला काफी आगे बढ़ गया। अमोल पालेकर शुरू से तड़क-भड़क से दूर रहने वाले हैं। वह ऑटोग्राफ देने से भी मना कर दिया करते थे। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें डांटती भी थीं। अमोल ने दो शायदियां कीं।

फिल्मों में अभिनय करने से पहले अमोल पालेकर थिएटर जगत में निर्देशक के रूप में स्थाई पहचान बना चुके थे। सत्यदेव दुबे के साथ शुरुआती दौर में काम करने के बाद साल 1972 में उन्होंने अनिकेत नाम से अपने थिएटर ग्रुप की शुरुआत की। बासु

1970 के दशक में अमोल पालेकर की बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान थी। उस दौर में वह काफी सोच-समझ कर फिल्में करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह दस में से नौ फिल्में रिजेक्ट कर देते थे। सत्तर के दशक में बासु चटर्जी-अमोल पालेकर की जोड़ी मनमोहन देसाई-अमिताभ बच्चन जैसी थी। इसके अलावा उन्होंने कैमरे के पीछे भी गजब की क्रिएटिविटी दिखाई।

चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य उनके नाटक देखने आया करते थे। उन्होंने सन 1974 में बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म सफल हुई। उन्होंने एक्टर के रूप में चितचोर, घरींदा, मेरी बीवी की शादी, बातों-बातों में, गोलमाल, नरम-गरम, श्रीमान-श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्मों दीं। वे ज्यादातर फिल्मों में मध्यवर्गीय समाज के नायक का प्रतिनिधित्व करते दिखे। उनकी हास्य फिल्मों को दर्शक आज भी याद करते हैं। उन्हें खुशी है कि वे अपने करियर में फिल्म जगत के श्रेष्ठ निर्देशकों और श्रेष्ठ तकनीशियनों के साथ काम कर सके सन 1981 में मराठी फिल्म आक्रित से अमोल ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। अब तक वे कुल दस हिंदी-मराठी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी पिछली हिंदी फिल्म पहली को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था जिस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने निर्देशक के रूप में मनमाफिक फिल्म बनाई। बहुत जल्द फिल्म दुमकटा रिलीज होगी। उनकी यह फिल्म बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित होगी। ■

मेरी इजाजत के बगैर रणबीर नहीं कर सकते शादी: दीपिका

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तमाशा रणबीर और दीपिका की एक-साथ तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों फिल्म बचना ऐ हसीनों और ये जवानी है दीवानी में एक-साथ दिखाई दिए हैं। दोनों के बीच की केमेस्ट्री को भी दर्शकों ने पसंद किया है।

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का कहना है कि उनकी इजाजत के बिना अभिनेता रणबीर कपूर शादी नहीं कर सकते हैं। जब उनसे रणबीर और कैटरिना की शादी से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो इसके उत्तर में दीपिका ने यह बात कही। इस प्रकार रणबीर और दीपिका अनेक सालों तक रिश्तों में थे और आज भी दोनों के मध्य संबंध काफी सौहार्दपूर्ण हैं। दीपिका ने कहा कि रणबीर मेरी इजाजत के बिना शादी नहीं कर सकते। रणबीर ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरा शादी के रिश्ते में पूर्ण भरोसा है। जब मैं शादी करूंगा तो पूरी दुनिया को इसके संबंध में अवश्य ही जानकारी दूंगा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तमाशा रणबीर और दीपिका की एक-साथ तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों फिल्म बचना ऐ हसीनों और ये जवानी है दीवानी में एक-साथ दिखाई दिए हैं। दोनों के बीच की केमेस्ट्री भी दर्शकों ने पसंद किया है, हाल ही में हुए एक सर्वे में दोनों की जोड़ी शाहरुख और काजोल की जोड़ी से आगे नज़र आई थी। ■



चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

बिहार-झारखंड

07 दिसंबर-13 दिसंबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार का पहला आधुनिक तकनीक से निर्मित सरिया

PRIME GOLD

TMT, COIL & ANGLE PATTI
PURE STEEL

PLATINUM ISPAT INDUSTRIES PVT. LTD.
DIDARGANJ PATNA CITY
Mob : 9470036601, 9334317304



The Most Cost Effective Builder in India

4 से 50 लाख तक में घर

Customer Care : 080 10 222222

www.vastuvihar.org



सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

आखिर कौन है हार का जिम्मेदार

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. चुनाव में एनडीए की हुई करारी हार जगजाहिर है. इस हार से जमीनी कार्यकर्ता व नेता हताश हैं लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर इस बात का शायद कोई असर नहीं पड़ रहा है. एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के नेता इस हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ कर अपना सिर बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं. एनडीए के नेताओं के बीच चलती कशमकश पर पढ़िए हमारी यह स्टोरी...



सरोज सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के घटक दलों में एक अजीब खामोशी है. झटका ऐसा है कि संभलने में चकत्त लोगो लेकिन लगभग सभी पार्टियों के दफ्तरों में इस बात की चर्चा दबी जुबान से जरूर है कि आखिर कौन है इस हार का जिम्मेदार? कोई भी नेता अपने ऊपर हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. हां, जीत की स्थिति में ऐसे नेता मुख्यमंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री तक बनने का दावा ठोंके हुए थे, लेकिन जैसे ही बाजी पलटी बड़े नेताओं ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया. कुछ औपचारिक बयान देकर हार से पल्ला झाड़ने की कोशिश हुई पर न ही किसी ने अपने हार से इस्तीफा दिया और न ही किसी नेता को साइडलाइन किया गया. ऐसे में छोटे नेता और कार्यकर्ता जगह-जगह यह सवाल उठा रहे हैं कि एनडीए के बड़े नेताओं को अब हो क्या गया है? चुनाव से पहले बड़े-बड़े दावे कर हेलिकॉप्टर पर उड़ान भरने वाले नेता अब चुप क्यों हैं? आखिर किसी न किसी को इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी लेनी होगी और इसका दंड भुगतना होगा या फिर टालमटोल कर सारी बातें रफा-दफा कर दी जाएंगी.

बात प्रदेश भाजपा की करें तो यहां मोटे तौर पर सारी कवायद मंगल पांडेय, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और संघ की ओर से नागेंद्र जी के आसपास घूमती रही. भाजपा के अंदर की यह व्यवस्था कई नेताओं को खराब भी लगती थी कि चुनाव हारने के बाद ये नेता हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने-अपने मौजूदा पदों से इस्तीफे की पेशकश करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. हद तो यह है कि ये सभी नेता एक बार फिर भाजपा पर अपना दबदबा बरकरार रखने के जुगाड़ में लग गए हैं. हार के

कारणों पर विचार के लिए हुए मंथन में यह आम राय बनाने का प्रयास हुआ कि टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा व जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर बाहरी लोगों को टिकट देने का कोई लाभ नहीं हुआ. भाजपा से जुड़े एक मंच के पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं की बेहिसाब दौरों व सभा का खराब प्रभाव पड़ा. उम्मीदवार लोग सभा को सफल बनाने में ही रह गए और जनता से सही संपर्क नहीं कर पाए. इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए कार्यकर्ताओं को भी स्थानीय कार्यकर्ताओं की तुलना में ज्यादा तरजीह दी गई. इसका कुप्रभाव यह हुआ कि भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मन से चुनाव में नहीं लगे. जो लोग टिकट न मिलने से दुखी और नाराज थे उन्हें मनाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया. केवल सतही तौर पर खाना पूर्ति की गई. एक अनुमान के अनुसार इससे भाजपा को कम से कम डेढ़ दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बैठक में कहा कि हमलोग इतने फील गुड में थे कि मतदाता जागरण और वोट पच्ची देकर अपने परंपरागत तरीके को भी भूला दिया गया. दिल्ली के नेताओं के करीबी माने जाने वाले प्रदेश के एक नेता कई क्षेत्रों में अपना एजेंडा चला रहे थे और केंद्रीय नेताओं को गलत फीडबैक दे रहे थे. मंथन में इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई पर किसी नेता ने अपने माथे पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली और न ही इस्तीफे की पेशकश की. लोजपा का हाल सबसे जुदा है.

चुनाव के दौरान तो ऐसा लगता था कि सांसद चिराग पासवान एक ऐसा जादू है जो जिस इलाके में चला गया वहां के उम्मीदवार की जीत तय है. टिकट वितरण से लेकर मतदान के दिन तक चिराग पासवान अपनी बचकानी मनमानी करते रहे और इसका नतीजा यह हुआ कि लोजपा 43 में से केवल दो सीट जीत पाई. इनमें में भी जो दो लोग जीते हैं वह अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जीते हैं, उसमें पार्टी और चिराग पासवान का कोई योगदान नहीं है. लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि अभी तक पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष और सांसद चिराग

पासवान ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश नहीं की. टिकटों के वितरण के बातचीत में चिराग के अंडियल रवैये से भाजपा के कई नेता काफी नाराज थे पर गठबंधन धर्म और रामविलास पासवान की इमेज को लेकर वे शांत रहे, लेकिन अब चिराग का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है. अंदरखाने सबसे अधिक विरोध तो उनकी पार्टी के भीतर ही हो रहा है. हाई

चुनाव से पहले बड़े-बड़े दावे कर हेलिकॉप्टर पर उड़ान भरने वाले नेता अब चुप क्यों हैं? आखिर किसी न किसी को इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी लेनी होगी और इसका दंड भुगतना होगा या फिर टालमटोल कर सारी बातें रफा-दफा कर दी जाएंगी. बात प्रदेश भाजपा की करें तो यहां मोटे तौर पर सारी कवायद मंगल पांडेय, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और संघ की ओर से नागेंद्र जी के आसपास घूमती रही.

फाई स्टाइल में पार्टी चलाने का क्या नतीजा होता है यह बिहार के चुनाव में साबित हो गया. लोजपा के कई नेता कह रहे हैं कि अगर रामविलास पासवान पुत्र मोह में फंसे रहे तो पार्टी का सत्यानाश तय है. लोकसभा में मोदी लहर के कारण मिली जीत का सेहरा रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग के सिर बांधते रहे अब अगर पार्टी की करारी हार हुई है तो पता नहीं उनकी जुबां पर क्यों ताला लगा हुआ है? प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस खुद चुनाव



हार गए इसलिए वह कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं हैं. पार्टी को नए सिरे से अगली लड़ाई के लिए खड़ा करना उनके लिए कड़ी चुनौती है. लेकिन जानकार बताते हैं कि अगर चिराग पर लगाम नहीं लगाया तो फिर पशुपति कुमार पारस भी कुछ नहीं कर पाएंगे. बिहार के बारे में चिराग की कम समझ लोजपा के लिए खतरनाक साबित हो रही है. बिना मतलब के टांग अड़ाने की चिराग की आदत पार्टी को गर्त पर लाकर खड़ा कर चुकी है. देखना है रामविलास पासवान इस संकट से कैसे निपटते हैं? जहां तक बात रालोसपा की है तो यह माना ही जा रहा था कि उसके दो बड़े नेताओं उषेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार की आपसी खींचतान से पार्टी को नुकसान होगा ही होगा. जब चुनाव के नतीजे आए तो यह बात साबित भी हो गई. दूसरे दलों की तरह इस पार्टी के भी दोनों बड़े नेताओं ने हार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली और न ही अपने पद से इस्तीफे की ही पेशकश की. पार्टी के अंदर बात चल रही है कि रालोसपा पूरे बिहार की नहीं बल्कि एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई थी और

इसी वजह से इस तरह के परिणाम आए हैं. पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हमें अपना चरित्र बदलना होगा. किसी एक जाति या वर्ग को लेकर हमलोग बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं. जीतनराम मांडी की पार्टी हम में भी मंथन जारी है पर कोई भी हार की जिम्मेदारी अपने माथे पर लेने को तैयार नहीं है. हम के सारे बड़े नेता अपनी-अपनी सीट बचाने में लगे थे और सामूहिक तौर पर कोई पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा था. नतीजा यह हुआ कि सारे बड़े नेता और इनके रिश्तेदार तो हार ही गए पार्टी भी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई. अकेले जीतनराम मांडी ने हार की समीक्षा के लिए एनडीए की एक बैठक बुलाने की मांग की है पर उनकी मांग पर किसी भी दल ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है. देखा जाए तो हार के बाद एनडीए के दल हताश हैं क्योंकि एक सूत्र में बंधने की इनकी आधे मन से की गई कवायद पूरी तरह फेल हो गई है. पहले तो सभी दलों को अपने ही दल में सामने आ गई चुनौतियों से निपटना है एनडीए को एक रखने की बात तो दूर की कौड़ी है.

चौथी दुनिया

07 दिसंबर-13 दिसंबर, 2015

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश—उत्तराखंड

सैफई में मना मुलायम का भव्य जन्मदिवस समारोह, प्रदेश भर में बांटे गए लड्डू



अमर पर मुलायमियत से बेकायदे आजम



प्रभात रंजन दीन

मुलायम सिंह यादव के तब के जन्मदिन और मुलायम सिंह यादव के अब के जन्मदिन में रेखांकित करने वाला फर्क है. पिछले साल जब आजम खान ने समाजवाद के पुरोधा को ब्रिटिश सामंती औपनिवेशिक विचार-बग्धी पर बैठा कर रामपुर की सड़कों पर विचरण करवाया था, तब समाजवाद अपनी सड़क से भटका हुआ उद्धोषित हुआ था. इस साल जब जन्मदिवस समारोह में आजम खान मुख्य भूमिका और सटीक समय, दोनों से नदारद थे, तो समाजवाद पिछली गलतियों पर प्रायश्चित्त करता हुआ प्रतीत हुआ. पिछले साल मुलायम के जन्मदिन समारोह में अमर सिंह नहीं दिखे, तो समाजवादी पार्टी की नई संभावनाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई थी. इस साल जन्मदिवस

समारोह में अमर सिंह जब मुलायम को केक खिला रहे थे और मुलायम भी बड़े प्यार से अमर के मुंह में केक ठूस रहे थे, तो विशाल शामियाने में समाजवादी पार्टी की नई संभावनाएं एआर रहमान के गाने जय-हो की तरह गूंज रही थी. पिछले साल तक आजम-प्रभाव में कोई जयाप्रदा का नाम तक नहीं ले सकता था, इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जयाप्रदा से बड़ी अंतरंगता से बतिया रहे थे, तो किसी अनजाने से नयेपन का पुरखता संदेश जनसमूह के बीच जा रहा था. अमर सिंह से परहेज करने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी अमर को स्वीकार करने के भाव में दिखे और अमर को अस्वीकार करने वाले आजम फोटो-फ्रेम में कहीं नहीं दिखे. लिहाजा, मुलायम का इस बार का जन्मोत्सव भविष्य के नए सियासी समीकरणों का भूमिकोत्सव साबित हुआ. अखिलेश यादव ने कहा भी कि वह अपने पिता को उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में 2017 में दोबारा सरकार देना चाहते हैं.

जन्मदिवस के मौके पर आयोजित भव्य

207 फीट उंचा झंडा देकर दिया बर्थ-डे गिफ्ट

लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के मौके पर राज्य सरकार ने 207 फीट उंचे फ्लैग पोल पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर प्रदेश के लोगों को उपहार दिया. इसे मॉन्यूमेंटल फ्लैग का नाम दिया गया. इस मौके पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी समेत कई हस्तियां यहां मौजूद थीं. देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा भी कि किसी भी देश की राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता में उस देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान प्रमुख होता है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों ने हमेशा ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनका अधिकतम लाभ लोगों को मिल सके. वर्तमान सरकार ने जनेश्वर मिश्र के नाम पर विश्वस्तरीय पार्क विकसित करने का काम शुरू किया था, जो अब साकार रूप ले रहा है. लगभग 376 एकड़ में विकसित हो रहे इस पार्क में दुनिया के तमाम मशहूर पार्कों की तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. मुख्यमंत्री ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं सांसद मुलायम सिंह यादव को उनके जन्म दिवस की बधाई देते हुए कहा कि नेताजी ने समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए सदैव संघर्ष किया और सभी का मार्गदर्शन किया. उन्होंने एक शिक्षक के रूप में जीवन की शुरुआत की और समाजवाद में आस्था होने के कारण राजनीति का संघर्षपूर्ण रास्ता चुना. समाज के गरीबों, मजदूरों, दबे-कुचले वर्गों, अल्पसंख्यकों इत्यादि के लिए उनके मन में अपार स्नेह है. किसानों के वे परम हितैषी हैं. अखिलेश ने सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि विकास ही समाजवादी राजनीति का मूल मंत्र है. अपने पिता के जन्मदिवस पर अखिलेश भावुक भी हुए और कहा कि हम नेताजी के मार्गदर्शन में सपा को चलाएंगे और आम आदमी की लड़ाई जारी रखेंगे. नेताजी खुद मुख्यमंत्री रहे और मुझे भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया. उनके बिना मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था. नेताजी ने जिस भी नेता



(शेष पृष्ठ 20 पर)

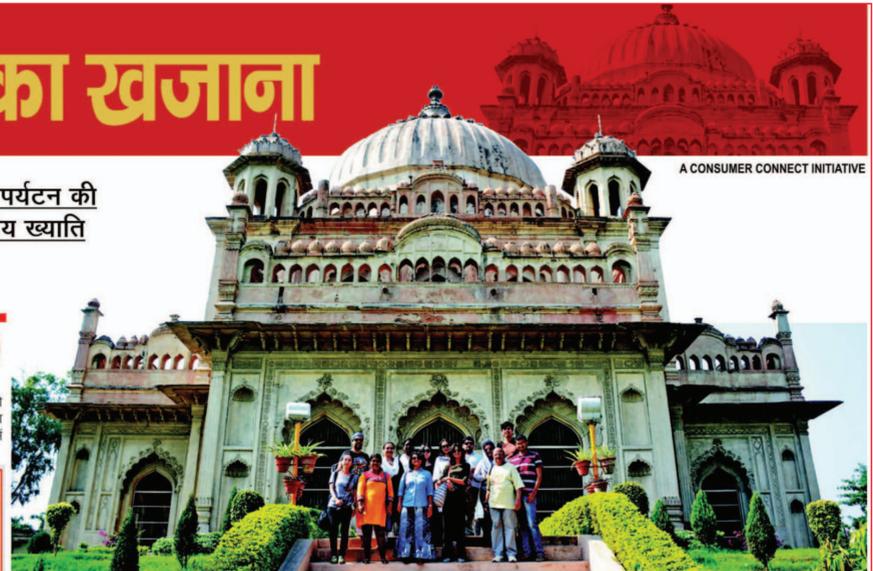
समारोह और भारी जनसमूह की मौजूदगी में मुलायम जब अपने 76वें जन्मदिवस का केक काटने स्टेज पर पहुंचे, तो अमर सिंह उनके साथ थे. अमर सिंह ने ही सपा महासचिव रामगोपाल यादव और बाकी लोगों को मंच पर बुलाया. 76 किलो का केक काटने के बाद मुलायम सिंह यादव को केक का पहला टुकड़ा अमर सिंह ने ही खिलाया. इसके बाद मुलायम ने भी केक का दूसरा टुकड़ा अमर सिंह को खिलाया. राजनीति में इस केक के दूसरे टुकड़े के भी कई विश्लेषण हैं. केक काटने के वक्त आजम खान की गैरहाजिरी भी इस समीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है. जिस समय मुलायम अपने जन्मदिन का केक काट रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जया प्रदा, डिम्पल यादव, धर्मेन्द्र यादव, लालू के दामाद तेजप्रताप यादव व मुलायम-परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे. केक काटने से पहले मुलायम ने कहा कि समाजवाद का मतलब भूखा नंगा होना नहीं होता, बल्कि समाजवाद का अर्थ सम्पन्नता की ओर बढ़ना होता है. केक काटने की औपचारिकता के बाद जब समारोह शुरू हुआ तब भी मुलायम ने अपने बगल में अमर को ही बैठाया. रामगोपाल, शिवपाल व अन्य नेता बगल की सीटों पर बैठे और अखिलेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग बैठे थे. आजम खान केक काटने के काफी देर बाद आए और थोड़ी देर बाद ही फिर कहीं नहीं दिखे. आजम खान अमर सिंह की मौजूदगी से इतने ज्यादा खफा हुए कि सैफई में होने के बाद भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए.

मुलायम के समधी लालू प्रसाद यादव जन्मदिवस समारोह में नहीं पहुंचे. ये बातें पारिवारिक नहीं, राजनीतिक हैं, यह साफ तौर पर साबित हुआ. नीतीश कुमार और लालू के बेटों के शपथ ग्रहण समारोह में न मुलायम गए थे और न ही अखिलेश. सपा की तरफ से कोई प्रतिनिधि नेता भी शपथ ग्रहण में शरीक नहीं हुआ था. लिहाजा, जन्मदिवस में लालू के शरीक नहीं होने को भी उससे जोड़ कर देखा जा रहा है. हालांकि मुलायम के पोते और लालू के दामाद तेज प्रताप यादव ने इस पर दूसरी परतें चढ़ाने की काफी कोशिश की. सांसद तेजु ने कहा, शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूरा परिवार काफी थका

(शेष पृष्ठ 20 पर)



3 दिनों में जाना उत्तर प्रदेश के पर्यटन का खजाना



A CONSUMER CONNECT INITIATIVE

#UPTWC2015 ट्वीटर पर भेजे गये सन्देश



उत्तर प्रदेश की विरासत को जानने और उसके बारे में सीखने के लिये यह यात्रा बहुत आकर्षक और मनोहर थी। #UPTWC2015 #tot @manjulika

उपग्रो पर्यटन सरकार द्वारा संगठित #UPTWC2015 में मुझे बहुत अच्छी और सुपरकित अनुभूति हुई। ट्रेनेल राइडर्स के लिए यह एक बहुत ही बारीकी से संगठित यात्रा थी। Aka Kaushik@LynfinTransit

धन्यवाद, उत्तर प्रदेश पर्यटन, आप बहुत अच्छे मेजबान थे हमारे लिए @travelwritersonclav. U.P. की विरासत से परिचय कराने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। @rauidias123

क्या कभी सोचा है ये वस्त्र किसने बनाये हैं? यह वस्त्र सेवा-चिकन-लखनऊ से ले सकते हैं। #UPTWC2015# U.P. पर्यटन सरकार चिकन का काम। Manish Kumar

चम्मल की घाटियाँ मजेदार थीं। यहाँ लाने के लिए यू.पी. पर्यटन सरकार को शुक्रिया #UPTWC2015 एक सपने को वास्तविकता में बदला है। Swati Jain

उत्तर प्रदेश पर्यटन सरकार की टीम की मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद उठाया हमने। हमें पता था जगह बहुत अच्छी है पर आपकी मेजबानी अद्भुत थी। #UPTWC2015 Anuradha Goyal

आज हमने वाराणसी के परंपरागत स्ट्रीट फूड से शुरूआत की- कचौड़ी, सब्जी और जलेबी। #UPTWC2015# IncredibleIndia. मराहर् ब्यू लस्सी शॉप की लस्सी बहुत पसन्द आयी। #UPTWC2015#IncredibleIndia

देशी मालुओं के साथ एक बहुत ही खट्टा मीठा अनुभव रहा। अत्याचारी जीवन से सुरक्षा मिली। differentdoors@dd_traveller

एक बन रहा नवीन पर्यटक आकर्षण, आगरा से हटकर इटावा में लायन सफारी #UPTWC2015#uptourismgov

अद्भुत शब्द, यू.पी. पर्यटन के मुख्यमंत्री/अखिलेश के विचार उ०प्र० की समृद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत को लेकर #UPTWC2015 @priyapathiyaa



अभिषेक.singh4@timesgroup.com उत्तर-प्रदेश उससे बहुत अलग निकला जैसा मैंने सोच रखा था। इसकी खूबसूरत, जायके, परम्परायें, तीज-त्योहार, आध्यात्मिका तथा राजमार्गों की जिन्दगी-समी मोहित कर लेने वाले हैं। मैं एक ही स्थान में सप्ताह भर तक बिना थके यहाँ के दृश्यों को निरन्तर देख सकती हूँ। हर समय मधु, आकर्षित एवं खोयी-खोयी सी, उससे जो कुछ आँखों के सामने था। यात्रा लेखकों के इस सम्मेलन को क्या शानदार तरीके से आयोजित किया गया। यह कहना है सम्मेलन में न्यूयार्क से आयी जानी मानी



समाजिक कार्यकर्त्री एवं लेखिका वन्या पोलिक विदारकी का। यह पहला अवसर था जब देश में यू.पी. यात्रा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भाग लेने वाले पत्रकार, छाया पत्रकार और ब्लागर्स ने हेरिटेज आर्क के तीन नगर- लखनऊ, आगरा और वाराणसी को भ्रमण के लिये चुना। उ०प्र० के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से नगर के प्रमुख होटल में रोचक भेंट के साथ इस भ्रमण कन्वेलव की परिधिगत हुई। इस अवसर पर नगर के बुने एवं जाने माने तथा भ्रमण जगत से जुड़े व्यक्ति उपस्थित थे। संस्थान, निर्माजिन, खानपान, वास्तु शास्त्र ऐसी विविध विधाओं के विशेषज्ञों ने समिपलित रूप से विचार-विमर्श किया कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश को पर्यटन के नये में एक सामाजिक यादवान पर स्थापित किया जाय ताकि देश और विश्व से आकर्षित होकर पर्यटक यहाँ आयें। आयोजन की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि UPTWC2015 भारत से दिव्यतर पर उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय था। यह सूचना वर्ल्डवाइड मीडिया के सी.ई.ओ. श्री दीपक लाम्बा से मिली है। इस विशाल सम्मेलन के आयोजन में उनकी संस्था ने यू.पी. पर्यटन के साथ

कुछ दिनों पूर्व देश का सर्वप्रथम यात्रा लेखक सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। यूपी में पर्यटन की सम्भावनाओं को बल देने के उद्देश्य से आमंत्रित किये गये इस सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के यात्रा लेखक, पत्रकार तथा ब्लागर्स शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश ने जीता सबका दिल

अर्पित की। जिन पत्रकारों ने आगरा में ताजमहल, अकबर का मकबरा, एतामादुद्दौला तथा लाल किला देखा थे सभी इनकी भयता से अभिभूत थे। चीन के रोन जू को लगभग आध्यात्म की अनुभूति हुई उनके अनुसार 'मैंने वर्षों से ताजमहल के विश्व में पढ़ा और सुना था लेकिन अपनी यात्रा में जब मैंने इसके प्रथम दर्शन किये, मैं रो पड़ा। मेरे लिये यह एक इमारत अथवा मकबरा मात्र नहीं था, बल्कि एक सौन्दर्य था जो प्यार की शक्ति की याद दिलाते रहने वाला था।

आगरा के छोटे ताजमहल, एतामादुद्दौला के मकबरे का जिक्र करते हुये पोलिश लेखिका मिशेला पालवित्च ने कहा "यह आगरा का अपेक्षाकृत एक शान्त स्थल है। ताजमहल से कम प्रसिद्ध है और



यात्रा के मुख्य आकर्षण आगरा : ताज महल अकबर का मकबरा इतामादुद्दौला का मकबरा लाल किला मालू अभ्यारण स्लॉथ का बघाव जरदोजी कढ़ाई की खरीददारी बाजार की फोटोग्राफी राष्ट्रीय चम्मल अभ्यारण की सैर वाराणसी : गंगा नदी में नौका विहार घाटों और मन्दिरों के दर्शन स्वास्थ्ययुद्धक सांत्विक खानपान सारनाथ के बौद्ध दर्शन बनारसी सिल्क की खरीददारी लखनऊ : ऐतिहासिक स्मारकें हेरिटेज वॉक अक्वी व्यंजन चिकन वर्क की खरीददारी

इसलिये इसने मुझे विशेषतया आकृष्ट किया। लेकिन कुल मिलाकर मुझे प्रदेश में सड़क के किनारे का खाना बहुत भाया जो विविधता लिये व्यंजनों के परसेने वाले बड़े-बड़े रेस्टोराँओं को कड़ा मुकाबला दे सकता है। मुझे पानी-पूड़ी और चाट में मजा आ गया।" जिन्होंने प्रकाश के नगर वाराणसी की यात्रा की उन्होंने भीर में गंगा की नदी द्वारा सैर की। शहर की विविधता से अविभूत जर्मनी की सुशी एलेक्जान्दर ने कहा "यह छठी बार है जब मैं भारत आई हूँ लेकिन मेरा अनुमान इस बार कहीं अधिक मार्मिक रहा। वाराणसी और लखनऊ का पुराना वास्तु सदियों बीत जाने के बाद भी एक हीरे की भाँति है

अनुभव है जिन्हें कोई भी यात्री अथवा पर्यटक इस देश की धरती से विदा लेने के बाद भी अपनी स्मृति में वर्षों तक अधुण रखेगा। खानपान एवं व्यंजनों के पारखी लेखकों तथा ब्लागर्स के मन में लखनऊ के जायके को लेकर एक अलग ही छवि बनी। उन्हें छाया पदार्थों और इमारतों दोनों में भयता प्रीति हुई। अनेक प्रतिनिधियों ने कोमल कमनीय चिकन की हस्तनिर्मित वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। श्रीलंका की जानी-मानी व्यंजन विशेषज्ञ एवं पर्यटन लेखिका सुशी विद्या बालचन्दन को लखनऊ लजीज खानों और वास्तुकला का एक अद्भुत सम्मिश्रण उगा उन्होंने कहा "मैं भारत में 31 वर्षों तक रह चुकी हूँ लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मुझे यहाँ पुराने ब्रिटिशकालीन भारत की अनुभूति हुई और मैं बस चिकित होकर रह गई। मुम्बई की सुशी केंब्रिज को मन्दिरों और अनेक पुरानी इमारतों को देखकर लगा मानों वे एक टाइम कैप्सूल (समय तालिका) में प्रवेश कर गई हों जब उन्होंने कई नवमी इमारतों को निरूट से देखा। हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह अकबर और शाहजहाँ आदि का सामान्य उल्लेख करते हुए नवमी इमारतों के ऊपर से निकल जाता है। मैंने इन तीन दिनों के अपने लखनऊ प्रवास में जितना छक्कर खाया उतना शायद वहाँ में कभी न खाया हो।" अपना अनुभव बाँटते हुये कोरिया की यात्रा लेखिका सुशी की सुन ली ने कहा "मैं तो एक ही स्थान पर शहर में इतना रंग

जोशेवर मिश्र पार्क से अधिक उपयुक्त कोई स्थल ही नहीं सकता था जहाँ अपने अतिव्यस्त कार्यक्रम की थकावट को लेकर मुक्ति पा सकें। अनेक वरिष्ठ लेखक एवं ब्लागर्स एक दूसरे के साथ अन्तरराष्ट्र से वातचीत में मशगूल थे और अन्य तरह-तरह के खेल खेलकर माहौल को मित्रपूर्ण बना रहे थे। पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंघ के साथ भी प्रतिनिधियों ने

समय बिताया जिसके बाद नगर के एक भव्य होटल में शानदार डिनर का आयोजन किया गया जहाँ परसे गये व्यंजन प्रदेश के विविधभारण जायकों की गवाही दे रहे थे। न केवल स्मृति विधाओं अन्तरराष्ट्र से वातचीत में मशगूल थे और अन्य तरह-तरह के खेल खेलकर माहौल को मित्रपूर्ण बना रहे थे। पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंघ के साथ भी प्रतिनिधियों ने

समय बिताया जिसके बाद नगर के एक भव्य होटल में शानदार डिनर का आयोजन किया गया जहाँ परसे गये व्यंजन प्रदेश के विविधभारण जायकों की गवाही दे रहे थे। न केवल स्मृति विधाओं अन्तरराष्ट्र से वातचीत में मशगूल थे और अन्य तरह-तरह के खेल खेलकर माहौल को मित्रपूर्ण बना रहे थे। पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंघ के साथ भी प्रतिनिधियों ने

मस्ती के मूड में समापन



उत्तर प्रदेश तुम्हें कोटिशः धन्यवाद

देश और देश के बाहर से आये यू.पी. यात्रा लेखक सम्मेलन 2015 से घर लौटते समय ब्लागर्स और पत्रकार यहाँ के आनन्ददायक क्षणों की ढेरों स्मृतियाँ और स्मृति चिह्न अपने साथ लेते गये। राज्य सरकार की मेहमान नवाजी और गर्मजोशी के लिए हर मेहमान शुक्रिया कहते नहीं थक रहा था। उन्होंने एक विशेष नोट बुक मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को भेंट की जिसमें सभी ने धन्यवाद सहित अपने संक्षिप्त यात्रा संस्मरण लिखे थे। नवभारत टाइम्स आपके समक्ष इस अमूल्य पुस्तक की कुछ चुनिन्दा झलकियाँ लेकर हाजिर है।

A collage of sticky notes with handwritten text in Hindi, expressing gratitude and sharing experiences from the travel writers' conclave. The notes are pinned to a light-colored background and contain various messages of appreciation and personal anecdotes.



सपा कार्यकर्ताओं ने नागरिकों से अपील की थी कि वे अपने-अपने घरों पर दीप जलाएं और लाइटिंग करें. सैफई महोत्सव के कार्यकारी प्रबंधक वेदव्रत गुप्ता ने बताया कि मुख्य समारोह स्थल एथलेटिक्स स्टेडियम में एक लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था. मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने अपने 300 सदस्यों की टीम के साथ संगीत का जादू बिखेरा. हरिहरन और जावेद अली जैसे मशहूर गायकों ने भी मुलायम के जन्मदिवस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी.

लखनऊ विश्वविद्यालय में मची है अराजकता और अंधेरगर्दी

नियम और शिक्षा दोनों ही ताक पर

रोहित पांडेय

लखनऊ विश्वविद्यालय में सिर्फ वित्तीय अनियमितता ही नहीं व्याप्त है, बल्कि विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे दो दर्जन से अधिक शिक्षकों की योग्यता पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं. विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षक भी सेवा दे रहे हैं जिनकी खुद की योग्यता भी पूरी नहीं है. विश्वविद्यालय सहित अन्य स्थानों पर लगभग हर माह शिक्षा की गुणवत्ता पर संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं. ऐसे गुरुजनों से गुणवत्तापरक शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है! यह शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों को पूरा नहीं करते और अनियमित ढंग से शिक्षण कार्य कर रहे हैं. लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जो एक योग्यताधारी शिक्षक को प्राप्त होती

विनियमित करने की शर्तें

1. अभ्यर्थी पूर्णतया यूजीसी के नियमों का पालन करता हो.
2. अभ्यर्थी लगातार कार्यरत रहा हो, किसी अन्य संस्थान में न गया हो और अधिक दिनों तक गैरहाजिर न रहा हो.
3. जिस ग्रेड की पोस्ट खाली हो उसी में नियमित कर दिया जाए.

हैं. विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉ. रंजना वैशंपायन नियुक्ति की अर्हता पर खरी नहीं उतरती हैं, जिसके बावजूद उन्हें प्रवक्ता के पद पर 10.06.2004 को नियुक्त कर दिया गया. यही नहीं इनको प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत भी कर दिया गया. डॉ. रंजना वैशंपायन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में परास्नातक हैं. जिसमें इन्हें मात्र 52 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. एक चौंकाने वाला पहलू यह भी सामने आया



लेकिन प्रावधान रख दिए गए ताक पर

नियुक्ति के समय शर्तों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए लाभ पहुंचाया गया. डॉ. रंजना वैशंपायन कानपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रो. जेबी वैशंपायन की पत्नी हैं जो पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर तैनात रहे थे. विश्वविद्यालय के इस फर्जीवाड़े को जांचने के लिए बनी कमेटी ने मात्र सात शिक्षकों को यूजीसी के नियमों के आधार पर खरा पाया था. शेष कोई भी योग्यता पूरी नहीं रखता था. इस बारे में जब डॉ. रंजना वैशंपायन से बात की गई तो उन्होंने योग्यता संबंधी सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. कुछ देर बाद उन्होंने फोन करके बताया कि जो 1991 के पहले एमए कर चुके थे उन्हें पीएचडी में पांच फीसदी अंक की राहत प्रदान की गई थी. जब लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे सम्पर्क नहीं हो सका. जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय की परिनियमावली (1993) अध्यापकों की अर्हता और नियुक्ति के विषय में कहती है कि कला, वाणिज्य और विज्ञान विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक से स्नातकोत्तर होने के साथ-साथ उत्तम शैक्षणिक अभिलेख का होना भी जरूरी है. लिहाजा, डॉ. रंजना वैशंपायन का तर्क उचित नहीं है. विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉ. अवधेश यादव (2003 के पीएचडी) इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां न्याय नहीं मिला, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने डॉ. रंजना वैशंपायन का प्रोन्नत करके प्रोफेसर की गरिमामयी कुर्सी पर बैठा दिया. यह आश्चर्यजनक है.

क्या कहता है अधिनियम

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षक पद के लिए कम से कम संगत विषय में 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होना अनिवार्य है. जबकि डॉ. रंजना वैशंपायन के शैक्षणिक अभिलेख भी मानक पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि इन्होंने हाईस्कूल में तृतीय श्रेणी व इंटर में द्वितीय श्रेणी स्थान हासिल किया है. लखनऊ विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार का यह मात्र एक बानगी है इस प्रकार न जाने कितने अयोग्य शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं. विश्वविद्यालय के एक शिक्षक नेता ने बताया कि 2004 में सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की मांग पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31-सी में परिवर्तन करके नियमों के तहत उन शिक्षकों को विनियमित करने की घोषणा की थी जो 31 दिसम्बर 1997 से 2004 तक अद्यतन शिक्षण कार्य कर रहे थे और यूजीसी के मानकों पर खरे उतरते थे. ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 50 तक थी.

है कि नियुक्ति पत्र जो कि कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, वह कुलसचिव के हस्ताक्षर से न जारी करके कुलसचिव कार्यालय में तैनात किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है. सूत्रों कि मानें तो कुलसचिव को फर्जीवाड़े की भनक लग गई तो वे अवकाश पर चले गए. नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन इतना उतावला था कि कुलसचिव व उपकुलसचिव की गैरमौजूदगी में विश्वविद्यालय के एक अवकाशप्राप्त कर्मचारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव से हस्ताक्षर करावा कर डॉ. रंजना वैशंपायन की नियुक्ति कर दी गई.

feedback@chauthiduniya.com

अमर पर मुलायमियत से बेक़ायदे आजम

पृष्ठ 17 का शेष

हुआ था. इसलिए लालू यादव जन्मदिवस समारोह में नहीं आ सके. इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन मतलब निकालने की प्रक्रिया इन बातों से और गति में रही. मुलायम के जन्मदिवस समारोह ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को खूब नाराज किया. आजम ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उससे लगा कि आजम खान अपनी मर्जी से पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं. शीर्ष नेतृत्व के फैसले उन्हें कतई गवारा नहीं. अपने निजी जौहर विश्वविद्यालय में अनुशासन पर बड़ी-बड़ी तकरारें पढ़ने वाले आजम खान अपनी ही पार्टी के अभिभावक के जन्मदिवस को लेकर क्या-क्या कहते हैं, यह सुनें तो आपको सपा नेतृत्व का विश्वास चेहरा सामने नजर आएगा, जो अनुशासनिक कार्रवाई में बड़ों के सामने पंगु और अदनों के आगे तना दिखाई देता है. आजम कहते हैं, सैफई में जो केक काटा गया था, वह असली केक नहीं था. असली केक तो उनके साथ रामपुर में कटा था. केक काटने के वक्त को लेकर भी आजम खान ने गुस्सा जताया और कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश है. मैंने नेताजी का जन्मदिन तय समय पर केक काटकर मनाया था. मुलायम के जन्मदिवस समारोह में अमर सिंह के सैफई पहुंचने पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परवाह किए बगैर आजम ने कहा, जब तूफान आता है तो कूड़ा करकट आ ही जाता है. बिहार चुनाव के तूफान के बाद अमर सिंह जैसे कूड़ा-करकट के आगमन पर कही गई आजम की ये बातें प्रदेश के आम नागरिकों और सियासतदार्ताओं को काफी नागवार लगेंगी, सपा नेतृत्व पर इन बातों का क्या असर पड़ा, अभी यह समय के पहलू में छिपा है.



207 फीट ऊंचा झंडा देकर दिया बर्थ-डे गिफ्ट

पृष्ठ 17 का शेष

को डांटा, उनका जीवन बन गया और वे भाग्यशाली हैं. इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि प्रखर समाजवादी जनेश्वर मिश्र के नाम पर पार्क का निर्माण कर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं. यह पार्क अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पार्क के रूप में विकसित हो रहा है और मॉड्युमेंटल फ्लैग लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम और गौरव की भावना जगाएगा. यह ऐसा प्रतीक-चिन्ह है, जिसके सम्मान के लिए देश का प्रत्येक नागरिक अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है. हमारा तिहुंगा भारत के मान और सम्मान का प्रतीक है. इस अवसर पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने मुलायम को इतिहास का निर्माता बताया और कहा कि नई पीढ़ी को मुलायम के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए. कार्यक्रम को महाकवि गोपाल दास नीरज, साहित्यकार उदय प्रताप, बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन, कारागार मंत्री बलवन्त सिंह रामवर्मा, टीने वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजले रहमान, इंदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष एनसी बाजपेयी वगैरह ने भी सम्बोधित किया. मुलायम के जन्मदिवस के मौके पर उनके राजनीतिक जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया. फोटो प्रदर्शनी में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की तस्वीरें खास तौर पर लगाई गई थीं. मुख्यमंत्री ने उन तस्वीरों को समाजवाद का इतिहास बताया और कहा कि ये सभी चित्र नेताजी के जीवन और संघर्ष के साथ-साथ वर्तमान सरकार के कार्यकलापों को भी दर्शाते हैं.



ढाई करोड़ का बना था मंच

मुलायम के जन्मदिवस पर सैफई में ढाई करोड़ का मंच बना था. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता के जन्मदिन को विशेष बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. स्टेडियम में आयोजित हुए भव्य समारोह में शासन के आला अधिकारी भी खास तौर मौजूद थे. प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, मुख्यमंत्री सचिवालय की प्रमुख सचिव अनीता सिंह, प्रदेश के डीजीपी जगमोहन यादव, इटावा के जिलाधिकारी नितिन बंसल, इटावा की एसएसपी मंजिल डैनी समेत तमाम अधिकारी कार्यक्रम में देखे गए. जन्मोत्सव के आयोजन में जिला प्रशासन जी-जान से जुटा रहा. शासन की लगातार निगरानी चलती रही. मुलायम के जन्मदिवस पर पूरे सैफई में प्रायोजित दीपावली मनी. सपा कार्यकर्ताओं ने नागरिकों से अपील की थी कि वे अपने-अपने घरों पर दीप जलाएं और लाइटिंग करें. सैफई महोत्सव के कार्यकारी प्रबंधक वेदव्रत गुप्ता ने बताया कि मुख्य समारोह स्थल एथलेटिक्स स्टेडियम में एक लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था. मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने अपने 300 सदस्यों की टीम के साथ संगीत का जादू बिखेरा. हरिहरन और जावेद अली जैसे मशहूर गायकों ने भी मुलायम के जन्मदिवस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी. इस मौके पर पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त किया गया था.